खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-01) अंक-81

मंगलवार 10 अप्रैल, 2018 20 चैत्र, 1940

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवाँ सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-01) में अंक 66 से अंक 81 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र–7 (भाग–01)	मंगलवार, 10 अप्रैल, 2018 / 20 चैत्र, 1940 (शक)	अंक–81
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	शोक संवेदना	4
3.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	5–16
4.	बधाई प्रस्ताव चर्चाः (दि.न.नि. की कार्य प्रणाली तथा विधायक क्षेत्रीय विकास निधि का दि.न.नि. के क्षेत्रों में उपयोग पर)	17–144

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–01) मंगलवार, 10 अप्रैल, 2018/20 चैत्र, 1940 (शक) अंक–81

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री पंकज पुष्कर
2. श्री पवन कुमार शर्मा
3. श्री अजेश यादव
4. श्री महेन्द्र गोयल
5. श्री रामचन्द्र
6. श्री सुखवीर सिंह दलाल
7. श्री ऋतुराज गोविन्द
8. संदीप कुमार
9. श्री रघुविन्द्र शौकीन
10. श्रीमती बंदना कुमारी
11. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
12. श्री राजेश गुप्ता
13. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
14. श्री सोमदत्त
15. सुश्री अलका लाम्बा
16. श्री आसिम अहमद खान
17. श्री हजारी लाल चौहान
18. श्री शिव चरण गोयल

19. श्री गिरीश सोनी
20. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
21. श्री जरनैल सिंह
22. श्री राजेश ऋषि
23. श्री महेन्द्र यादव
24. श्री आदर्श शास्त्री
25. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
26. श्री सुरेन्द्र सिंह
27. श्री विजेन्द्र गर्ग
28. श्री प्रवीण कुमार
29. श्री मदन लाल
30. श्री सोमनाथ भारती
31. श्रीमती प्रमिला टोकस
32. श्री नरेश यादव
33. श्री अजय दत्त
34. श्री दिनेश मोहनिया
35. श्री सौरभ भारद्वाज
36. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
37. श्री अमानतुल्लाह खान
38. श्री मनोज कुमार
39. श्री नितिन त्यागी
40. श्री ओमप्रकाश शर्मा
41. श्री एस.के. बग्गा
42. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
43. श्रीमती सरिता सिंह
44. मो. इशराक
45. श्री श्रीदत्त शर्मा
46. चौ. फतेह सिंह
47. श्री जगदीश प्रधान
48. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–01) मंगलवार, 10 अप्रैल, 2018/20 चैत्र, 1940 (शक) अंक–81

Lknu vijkgu 2-11 ct: leor gvkA

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ये सदन हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहा है। देश के अंदर एक ऐसा मामला पूरे देश के सामने आया है जिसने सबको झिंझोड़ कर रख दिया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन चाहूँगी कि उसके ऊपर मुझे दो मिनट का आप समय दीजिए। एक तरफ हमारी खेलों में गोल्ड मैडल लेकर हमारी बेटियाँ नाम जो है, देश का रोशन कर रही हैं और वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक बेटी के साथ क्या हो रहा है, आज देश को उसके ऊपर जरूर बात करनी चाहिए। क्योंकि वो बेटी उत्तर प्रदेश की नहीं, दिल्ली नहीं, देश की है।

अध्यक्ष महोदयः दो मिनट अलका जी, बैठिए, थोड़ा सा अलका जी, बैठिए थोड़ा।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, उम्मीद करती हूँ, आप उसमें दो मिनट के लिए...

माननीय अध्यक्षः दो मिनट, कुछ शोक संदेश हैं, मुझे वो एक बार कंप्लीट करने दीजिये।

शोक संवेदना

माननीय सदस्यगण! यह अत्यधिक दुःख का विषय है कि कल दिनांक 09 अप्रैल 2018 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर में एक स्कूल बस के खाई में गिरने से 27 बच्चों सहित 30 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि अधिकतर बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और ये सभी प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी थे। मृतकों में दो शिक्षक और बस चालक भी शामिल बताए गए हैं। मासूम बच्चों की मौत की यह दर्दनाक घटना है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से मृतकों को श्रद्धांजलि देता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण! यह अत्यधिक दुःख का विषय है कि कल दिनांक 09 अप्रैल 2018 को दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में स्थित रिहायशी क्षेत्र में चल रही एक सिलाई फैक्टरी में अचानक आग लगने से चार मजदूरों की मौत हो गई तथा दो व्यक्ति घायल हो गए। इसी तरह चाँदनी चौक में दुकानों में आग लगने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। आगजनी की इन दोनों घटनाओं के कारण सम्पत्ति का भी काफी नुकसान हुआ है। इस तरह की घटनाएं वास्तव में मानवीय लापरवाही का नतीजा हैं। किसी भी फैक्टरी या दुकान की स्थापना के समय सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। व्यवसाय से पहले जीवन को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से मृतकों को श्रद्धांजलि देता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ

तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अब हम सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(सदन द्वारा दो मिनट का मौन रखा गया।)

ओम शांति शांति शांति।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, सत्र का अंतिम दिन है और मैं ये सदन में बात रखना बहुत जरूरी समझती हूँ। अध्यक्ष जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप एक मौका जरूर दीजिए।

... (व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, वो बेटी उत्तर प्रदेश, उन्नाव की नहीं, वो भारत की बेटी है क्योंकि हर दूसरे दिन भारत में बेटियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उस पर बात बेहद जरूरी है होना।

माननीय अध्यक्षः कल हमारे नरेश बाल्यान जी का भी कोर्ट से मुकद्दमा रद्द हुआ है, वो बरी हुए हैं, नरेश बाल्यान जी आये नहीं?

सुश्री अलका लाम्बाः नहीं आये अध्यक्ष जी, पर मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगी, एक बार इन चीजों पर बात रखने का।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मेरे वाला अभी नहीं हुआ, अभी 17 तारीख है डिसीजन की।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, बीजेपी के लोगों से भी निवेदन करूँगी कि पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर देश की बेटी को बेटी देखें और बिल्कुल इस पर चर्चा होने दीजिए। हर मामले को व्यक्तिगत बता कर, ये टाल नहीं सकते कि सदन पर आवाज नहीं उठनी चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ...

... (व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बाः ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का दिया हुआ नारा है। बीजेपी को तो इसपे खुद माँग करनी चाहिए। बेटी बचाओ का नारा देश के प्रधानमंत्री ने दिया था चार साल पहले लाल किले से, आज क्यों ये वो आवाज दबाना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सैकण्ड। एक सैकण्ड। ये आपने दिया हुआ है जींस को रंगने का? ये विषय उठ चुका है चर्चा हो चुकी है

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः नहीं, अध्यक्ष जी,

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जो ये काम इसी तरह से कैमिकल और यहीं पर काम चल रहा है मैंने...

माननीय अध्यक्षः देखिए, अभी आपने कहा कि आपने जिसके लिए शोक संदेश बोला है, वो...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं यही तो कह रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः मैंने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं ये दोनों, ऐसा है, देखिए सिरसा जी, आज कमिशनर्स आये हुए, बैठे हैं। हमने एमसीडी का चर्चा का विषय गंभीर लिया है। ये विषय लिया जा सकता है। मैं देखूँगा समय के बाद क्या पोजीशन है, जीन्स पर चर्चा हो चुकी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब ये जो मेरे पास जो आया है, जीन्स के रंगने व धोने की अवैध फैक्टिरियों...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः चलिए, बैठिए। हाँ, अलका जी को मैं एलाउ कर रहा हूँ। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज सभी चैनल्स, अखबारों में हेड लाइन्स इसकी रही है।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, कल मैं सदन के लिए जब आ रही थी, उससे जस्ट पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आई कि पुलिस हिरासत में एक पिता की मौत हो गई। जब पूरी खबर जाननी चाही अध्यक्ष जी, तो बिल्कुल पाँव के नीचे से जमीन निकल गई और खून खौलने लग गया कि ये देश में हो क्या रहा है आखिर! और आप यकीन नहीं मानेंगे खुद को रोक नहीं पाई और फेसबुक पर लाइव लोगों से बात की, खास तौर से उन्नाव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के लोगों से और आपको यकीन नहीं होगा, कम से कम 25 लाख लोगों ने 25 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा ही नहीं, कम से कम 31 हजार लोगों ने शेयर भी किया क्योंकि उन्हें भी लग रहा था,

ये दर्द सिर्फ हमारा दर्द नहीं है, ये दर्द हर एक का दर्द है, खास तौर से, उस पिता का जिसकी बेटी है। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये बात जरूर कहूँगी कि किसी भी शासक का, किसी भी राजा का पिता होना और खास तौर से बेटी का पिता होना आज के दौर में बेहद जरूरी है। अगर कोई शासक बेटी का पिता होगा तो जरूर वो उस पिता का दर्द समझ पायेगा जो अपनी बेटी... जो गैंग रेप की शिकार हुई, उसके लिए न्याय की आवाज उठाते उठाते उसे जो है, फर्जी केस जो है, मुकद्दमों में फंसाने के बाद उसे जो है, कल जो है, कल जेल में उनकी हत्या हो गई। मैं हत्या कहूँगी उस को।

अध्यक्ष जी, मामला है पिछले साल का। पिछले साल हमारी एक बेटी, नाबालिग बेटी जो है, पिछले साल 4 जून, 2007 को गरीबी का फायदा उठाकर भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने घर बुलाया इस बेटी और उसके जो भाई... जो अखबार की रिपोर्ट है, जो पुलिस की एफआईआर है, मैं उसके हवाले से सारी बात कर रही हूँ कुछ भी मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रही हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के उन्नाव से जो विधायक हैं, वो उनके भाई अतुल सिंह सेंगर, इन्होंने इस गरीब बेटी को जो नाबालिग है, 4 जून को अपने घर पर नौकरी देने का लालच देकर बुलाया और सभी ने मिलकर 6 लोगों ने गैंग रेप किया। उसके बाद इस बेटी ने पूरी कोशिश की, पुलिस के पास गई, कोई सुनवाई नहीं हुई और जब इन्हें पता लगा कि ये बेटी हिम्मत दिखा रही है, थाने में जाकर इनके खिलाफ रिपोर्ट करा रही है, 11 जून 2017 को दोबारा इस लड़की को अगवा कर लिया जाता है और फिर पुलिस इस बेटी को किसी तरह इनके चुंगल से छुड़ाने में कामयाब हो जाती है ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अलका जी, शॉर्ट में करिए प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, मैं बिल्कुल, आपको सिर्फ ये तथ्यों पर बात कर रही हूँ। अध्यक्ष जी, उसके बाद लगातार एक साल तक संघर्ष चलता रहा, पुलिस में एफआईआर और इसके ऊपर दबाव हुआ है, एफआईआर नहीं हुई, शिकायत वापस लेने के दबाव में हुआ ये अध्यक्ष जी, कि 3 मई को इसके पिता की इन गुंडों ने विधायक, बीजेपी के जो विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर, अतुल सिंह सेंगर उनके भाई और उनके साथियों ने मिलकर एक पेड़ से बांधकर इसके पिता की इतनी बुरी तरह पिटाई की कि 8 मई को मजबूर हो गया पूरा परिवार बेटी, पिता, माँ मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्य नाथ जी के दफ्तर के बाहर, आवास के बाहर जाकर आत्मदाह करने को, या तो न्याय दिलाइए या हम आत्मदाह कर लेंगे। पुलिस पूरे परिवार को उठाकर थाने लेकर जाती है अध्यक्ष जी, थाने ले जाने के बाद पता लगता है कि जो पिता है, उसे डराया धमकाया जा रहा था कि आप पर फर्जी केस डालेंगे और फर्जी केस डालेंगे ही नहीं, डाल भी दिए गए और उनके यहाँ से अवैध हथियार पकड़े गए, ये फर्जी केस बनाकर पिता को जेल में डाल दिया गया और पता लगता है 9 तारीख की सुबह को पिता की, जिसको बुरी तरह से पीटा गया था 3 तारीख को, 9 तारीख को पिता की जेल के अंदर मौत हो जाती है। अध्यक्ष जी, ये हो रहा है। 'बेटी बचाओ' का नारा देकर आप बात करते हैं लेकिन एक पिता अपनी बेटी के गैंगरेप के लिए आवाज उठाता है और पूरा परिवार, अब वो बेटी कह रही है, ''आप कह रहे थे धमकी है, धमकी, धमकी सच हो गई। मेरे पिता जो है, उन्हें मार दिया गया है और आज भी उस बेटी के ऊपर दबाव है।

इतना ही नहीं, ये अखबार है 'द ट्रिब्यून' अध्यक्ष जी, 'फॉदर ऑफ वूमेन रेप्ड बाइ एमएलए डाइज इन कस्टडी।' और मुस्कुराते हुए ये जो चेहरा है,

ये बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का है। अध्यक्ष जी, वो ये लिखते हैं, ''मैं ऊंची जाति का हूँ, वो नीची जाति के थे, मेरी छवि खराब करने के लिए मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।'' ये उनकी सफाई दी गई है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष जी, ये जो विधायक हैं, ये कहते हैं उल्टा, ''राम राज्य है, आरोप तो भगवान राम पर भी लगे थे।'' ये देखिए, ये राम राज्य की बात करते हैं और इनका विधायक बलात्कार करने के बाद कहता है कि आरोप तो भगवान राम पर भी लगे थे।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ एक तरफ हमारी बेटियाँ पूरे विश्व में देश का नाम 'कॉमन वेल्थ गेम' में गोल्ड लाकर गौरवान्वित कर रही हैं। दूसरी तरफ 'बेटी बचाओ' के नारे पर अगर योगी आदित्य नाथ जी की बेटी होती तो जरूर–जरूर वो उस पिता का दर्द अध्यक्ष जी, समझ पाते। ये अभी कल की 'आज तक' की रिपोर्ट है अध्यक्ष जी, 37 प्रतिशत विधायक भाजपा के, उनके ऊपर गम्भीर आरोप हैं, मुकद्दमें चल रहे हैं जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर भी बहुत बड़ा आरोपी है, बहुत पहले इसके ऊपर मुकद्दमें हैं, जाना माना बदमाश है लेकिन इनको बचाया जा रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अलका जी, कन्क्लूड करिए, प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, दो मिनट और चाहूँगी। आज हमारे विधायक भी बैठे हुए हैं मनोज कुमार, नरेश बाल्यान जी अभी पहुंचे नहीं हैं, नरेश बाल्यान जी, मनोज कुमार हमारे विधायक हैं, गुलाब सिंह जी नहीं अभी सदन में आए। उन्हें तो गुजरात से पकड़कर लाए थे, हमारे दिनेश मोहनिया जी को महिलाओं के साथ छेड़खानी के झूठे आरोप एफआईआर करवाकर जो फंसाया गया, कैलाश गहलोत जी, ये सब कोर्ट से बरी हुए

हैं। किस तरीके से कानून, सत्ता, पुलिस का दुरूपयोग ये वहाँ बैठकर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में, देश देख रहा है। सब विधायकों के ऊपर झूठे मुकद्दमे डाले लेकिन एक भी... मुख्यमंत्री ने जब भी ये मुख्यमंत्री के पास गए, हम लोगों पर मुकद्दमा दर्ज किया, उन्होंने कहा, ''जब तुमने कुछ नहीं कहा, डरना मत जेल जाने से। कानून न्याय देगा और हकीकत है हमारे छः के छः विधायक आम आदमी पार्टी के... गर्व से कहती हूँ जोरदार तालियाँ कहूँगी... इन लोगों के लिए कि बरी होकर आए, बाइज्जत बरी होकर आए हैं। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। किसी ने जाकर इनके लिए गवाही नहीं दी। इनकी जनता इनके लिए गई। सबूत नहीं थे, झूठे केस थे इसलिए बरी हो गए लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बलात्कार के आरोप में एफआईआर में भी पुलिस ने नाम नहीं लिखा, पीड़िता के हजार बार कहने के बावजूद भी।

अध्यक्ष जी, ये बिल्कुल देश के सामने आना चाहिए, कब तक खोखले नारे 'बेटी बचाओ' के करेंगे? कहाँ है सुषमा स्वराज जी? कहाँ है स्मृति ईरानी? कहाँ है मेनका गांधी? क्यों आवाज इनकी गुम है? कहाँ है रीटा बहुगुणा जोशी? क्यों नहीं आवाज उठाती हैं आप इस बेटी की? क्योंकि ये बेटी का बलात्कार का आरोप भाजपा के एक विधायक पर लगा है, इसलिए आप बेटी की परवाह नहीं करेंगी, उस बलात्कारी भाजपा के विधायक को बचाने की कोशिश करेंगे?

यही हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, हरियाणा के, उनके बेटे के ऊपर एक आईएएस की बेटी के साथ उनकी छेड़खानी का जो लगा। गोपाल कांडा जैसे लोगों को इन्होंने अपने साथ पार्टी में लेकर रखा है और उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष जी, 114 खाली बीजेपी के ऐसे विधायक हैं जिन पर संगीन आरोप हैं बलात्कार के और बहुत गम्भीर... हत्याओं के आरोप हैं। इन लोगों

को ये लेकर बैठे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री। दुःख की बात है कि एक आवाज नहीं उठी, जिन्होंने 'बेटी बचाओ' का नारा दिया है!

अध्यक्ष जी, हाथ जोड़कर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से कमिटी का गठन होना चाहिए। किसी को भी उत्तर प्रदेश की, उन्नाव की जो यूपी की पुलिस, योगी आदित्य नाथ जी के अधीन पुलिस जो है, उस ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये सदन में आवाज उठ रही है, ये देश सुन रहा है। बेशक भाजपा के लोगों को लगेगा कि ये दिल्ली का मामला नहीं है लेकिन बेटी दिल्ली की नहीं, देश की बेटियाँ होती हैं। सांझी है हमारी बेटियाँ और हर पिता का दर्द जो है, वो समझ सकता है जिसकी खुद के घर पर एक बेटी है आज। आज दुआ करते हैं भगवान से कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद मोदी जी और योगी आदित्य नाथ जी की भी एक बेटी होती तो जरूर उस पिता का दर्द वो समझ सकते।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए अलका जी, कन्क्लूड करिए प्लीज।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूँगी पुलिस ने भाजपा के विधायक को बचाने की कोशिश की। एफआईआर में नाम नहीं है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हम देश की आवाज यहाँ से उठाना चाहते हैं कि उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो। भाजपा उसे अपनी पार्टी से बर्खास्त करे और किसी भी स्तर पर पीड़िता को जो मदद मिलनी चाहिए उस बेटी को, वो मदद जो है, हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। आपका धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इसमें मुझे बोलने का अवसर दिया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी, गम्भीर मुद्दा है, इसको प्लीज, बहुत दुखदायी मुद्दा है, थोड़ा इसको गम्भीरता से लीजिए। प्लीज बैठिए। बैठिए, बैठिए, मनोज जी। मैं मनोज जी को एलाऊ कर रहा हूँ वो पीड़ित हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी...

... (व्यवधान)

श्री मनोज कुमारः स्पीकर साहब, मैं सिर्फ दो मिनट आपका समय लूँगा। मैं भी इस पर कुछ कहना चाहूँगा सदन में ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी...

... (व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविन्दः इससे ज्यादा गम्भीर बात क्या हो सकती है अध्यक्ष महोदय, कि यहाँ पर ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं मनोज जी को एलाऊ कर रहा हूँ वो...

... (व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविन्दः गोपाल कांडा को पार्टी से... दिल्ली के अंदर एक विधायक के ऊपर अगर आरोप लगता है तो आप 20–20 दिन उनको जेल में डाल देते हैं ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी, बैठिए अब। प्लीज बैठिए, ऋतुराज जी। ऋतुराज जी, मैं आग्रह कर रहा हूँ, बैठिए।

श्री मनोज कुमारः अध्यक्ष जी, ये बहुत गम्भीर विषय है जिस पर हमारी सदस्या अलका बहन ने बहुत सारी संक्षेप में बातें रखीं कि किस तरह देश के अंदर दो तरह की सरकारें काम कर रही हैं; जो एक दिल्ली की सरकार है, उसके साथ किस तरह पुलिस आपराधिक मामले झूठे बनाकर के हमारे विधायकों को जेल भेजते हैं और वहीं जो देश में एक सरकार चल रही है, जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार चारों तरफ गुंडाराज मचा हुआ है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप अपने मुकदमों का जिक्र करिए जिसमें बरी हुए हैं।

श्री मनोज कुमारः जी। मैं उस पर भी आ रहा हूँ सर। सर, मैं उसी पर आ गया... लेकिन एक बेटी का दर्द मैं भी समझता हूँ क्योंकि मैं भी एक बेटी का पिता हूँ। अगर आज हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं होंगे तो ये देश की झूठे वादे करने वाली सरकार इसी तरह लगातार बलात्कार करती रहेगी और देश का जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, वो इन्हें संरक्षण देते रहेंगे।

अध्यक्ष जी, मैं अपने मुकद्दमों की बात करूँ। 2015 में जब हम लोगों को जिम्मेवारी दिल्ली की जनता की मिली, उस समय पर हमने अपने–अपने विभागों पर, अपनी कॉन्सिटयूएन्सियों में जाकर के क्षेत्र की जनता की शिकायतों पर जो काम करना शुरू किया, वो काम अच्छे न हो पाएं, दिल्ली की जनता के साथ... राशन के माफिया ना पकड़े जाएं, राशन की चोरियाँ ना पकड़ी जाएं, राशन के दलालों को जेल ना भेजा जाए, उन सबको बचाने के लिए झूठे मुकद्दमे किए जाते हैं। मेरे ऊपर 17 मुकद्दमे किए गए, एक

घंटे के अंदर। 28 राशन की दुकानें थी मेरी कॉन्सिटयुएन्सी में। एक पहले ही सील हो चुकी थी। उनमें से जब हमने कार्रवाई शुरू करी, सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के दुकानों के विजिट किए, उनके पास पहुँचे, न उनके लेजर पूरे थे, न बिल बुक उनके पास थी, न उनके पास तराजू बट्टे थे। जब अधिकारियों ने उनकी सारी चीजें जाँच की तो उसमें कई सारी दुकानों को नोटिस भी दिए और कई सारी दुकानें सील की गई। उसमें मामले के अंदर में जो उन सबका सरगना था, उस पर कई इतने अपराधिक मुकद्दमें दर्ज थे, कांग्रेस की तरफ से वो चुनाव लड़ चुका था। उसने लामबंद होकर के हमें रोकने के लिए एक कार्यकर्ता को रोड पर रोककर बैठा लिया और कहा आइए, बैठते हैं, चाय पीते है। राशन की वो दुकान नहीं थी, टीवी की दुकान पर उसने रोका, पीछे से पुलिस बुलाई जाती है कि जी, इसने हमसे पैसे माँगे हैं। उसी के अंदर उसको अरेस्ट किया जाता है। मेरा नाम लिख दिया जाता है एफआईआर में कि विधायक के नाम से उगाही कर रहा था। जबकि कोई भी सबूत किसी भी तरह के नहीं मिले। जबकि भाजपा के पास शायद दिल्ली में सीबीआई इनके पास है, दिल्ली पुलिस इनके पास है, एसीपी इनके पास है। उसके बावजूद भी उन्होंने किसी ने शिकायत नहीं करी कि हमारे पास कोई भी एक व्यक्ति आता है और हमसे उगाही की माँग कर रहा है। बस, उसको रोकने के लिए ताकि हम काम न कर सकें। राशन वालों की चोरी उजागर न कर सकें। हमारे ऊपर झूठे मुकद्दमे लगा दिये जाते हैं। जिनमें से बहुत सारे मुकद्दमों में पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती और एनओसी दे देती है। जब छः मुकद्दमे न्यायालय में पहुँचे तो न्यायालय ने जैसे ही देखा, उसने तुरंत बरी कर दिया कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है और झूठे फर्जी मुकद्दमे हैं। ऐसे ही दिनेश मोहनिया भाई के साथ हुआ, उन्हें बरी किया गया। नरेश बाल्यान भाई कल बरी हुए हैं। कैलाश गहलौत जी बरी हुए हैं। एक दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार

चल रही है। ईमानदारी से विधायक काम कर रहे हैं, उन्हें फर्जी मुकद्मों में अरेस्ट किया जाता है, जेल भेजा जाता है, उनपे मुकद्दमे बनाये जा रहे हैं। वहीं जो हमारे बिल्कुल नज़दीक है यूपी, उनमें उनके विधायक बलात्कार करते हैं, मर्डर करते हैं, गाड़ियों से कुचल देते हैं, उन्हों के ऊपर एफआईआर नहीं होती। उस एफआईआर में उनका नाम तक नहीं होता। ये एक नारा देते हैं, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' ये बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी हत्यायें करवायीं जा रही हैं चारों तरफ। हरियाणा के अंदर लगातार बेटियों का अनुपात गिरता जा रहा है। भ्रूण हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि बेटी, अरे! साहब बेटी तो तब बचायें, जब पढ़ायेंगे, तब उनको बचा पायेंगे। अभी उनको संरक्षक की जरूरत है। उन बेटियों को सम्मान की जरूरत है। क्या देश का नाम रौशन किया जा रहा है बेटियों के द्वारा।

माननीय अध्यक्षः मनोज जी, कन्क्लूड करिये, कन्क्लूड करिए।

श्री मनोज कुमारः सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ। यहाँ बेटियाँ हमारे देश का नाम रौशन कर रही हैं, वहीं हमारे पिता गंभीर रूप से चिंतित हैं कि बेटी सुरक्षित है, नहीं है। मैं सुरक्षित हूँ, नहीं हूँ। वो अपनी पीड़ा लेके न्यायालय जाते हैं। थाने जाते हैं, वहाँ उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। कौन अपनी बेटी का दर्द किसके सामने रोयेगा? कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। न बेटियों की सुरक्षा है, न महिलाओं को सुरक्षा है। न किसी भी जाति, धर्म के लोग आज खौफ के माहौल में जी रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं गुजारिश करूँगा सदन से यहाँ से कि प्रधानमंत्री महोदय अपनी आंखें खोलें, योगी सरकार अपनी आंखें खोले, वो महिलाओं के प्रति गंभीर हों। उनकी आत्मरक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। मैं इतना कहकर के अपने वक्तव्य को खत्म करता हूँ आपका बहुत–बहुत आभार, बहुत–बहुत धन्यवाद। जयहिंद, जय भारत।

सुश्री अलका लाम्बाः इनका राज, इनका कानून, इनका सबसे बड़ी बात अपराधी भी इन्हीं के हैं और नारा भी 'बेटी बचाओ' इनका है।

माननीय अध्यक्षः अल्का जी, हो गया अभी, हो गया प्लीज। हाँ, बताइए।

बधाई प्रस्ताव

श्रीमती सरिता सिंहः अध्यक्ष महोदय, एक सरकार चल रही है जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है पर बेटी को बचा पाने में विफल हुई है जो सारे राज्यों में प्रूव हो रहा है, साबित हो रहा है पर क्योंकि जैसा अलका बहन ने कहा, पुलिस इनकी, राज इनका तो भाई सब कुछ इन्हीं का चलेगा लेकिन मैं बधाई देना चाहती हूँ दिल्ली की अपनी उस बच्ची को जो कॉमन वैल्थ...

माननीय अध्यक्षः ये चर्चा, ये संकल्प... इसकी चर्चा नहीं करना प्लीज।

श्रीमती सरिता सिंहः लेकिन मैं बधाई देना चाहती हूँ दिल्ली की अपनी उस बच्ची को जो कॉमन वैल्थ...

माननीय अध्यक्षः ये चर्चा में नहीं है। बैठिए आप प्लीज।

श्रीमती सरिता सिंहः नहीं, मैं बधाई देना चाहूँगी दिल्ली की उस बच्ची को जो कॉमन वैल्थ गेम में आज गोल्ड लेके आयी है। ये हम दिल्ली वासियों के लिए फख्र की बात है। और दिल्ली विधानसभा में ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि दिल्ली की बच्चियाँ किस तरह देश का नाम रौशन कर रही हैं। पूरी दिल्ली की विधानसभा आज उसको, आज उस बच्ची को बधाई देती है, उनको परिवार को बधाई देती है और जो सहयोग जो भी कुछ हम उनके लिए कर सकें ताकि वो और अच्छा खेलें हमारा पूरा आशीर्वाद इस सदन का उनके साथ है; मणिका बत्रा के साथ।

माननीय अध्यक्षः वैसे तो ये विषय पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है कि जो दस गोल्ड मैडल मिले हैं, उनमें से अधिकांश इस देश की बेटियाँ लेकर के आयी हैं। लेकिन इस सदन के लिए। एक सैकण्ड बंदना जी, मैं आपको मौका देता हूँ। बंदना जी, अब ये विषय... रोकिए, थोड़ी देर प्लीज। लेकिन मणिका बत्रा दिल्ली में पढ़ी, दिल्ली में पली और वो टेबल टेनिस में दिल्ली का नाम रौशन किया और ये हम सब के लिए दिल्ली की सड़कों पर सर उँचा करके चलने वाला वक्त है। मैं बहुत–बहुत इस बच्ची को बधाई देता हूँ। जब भी अवसर मिलेगा सदन में बुलाकर यहाँ वीआईपी गैलरी में बिठाकर उनका सम्मान भी करेंगे। और मैं विशेष रूप से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूँगा जो भी सरकार का नियम है, उसके लिए हम कुछ न कुछ... सिरसा जी एक मिनट कुछ कहना चाहते हैं।

श्री शिव चरणः धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः ये बहुत गौरव का विषय है हम सबके लिए।

श्री शिव चरणः सर, मणिका बत्रा को बहुत बधाई दी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ दिल्ली की सरकार... आपने कहा है तो यकीनी तौर पर उसके लिए उसका और प्रोत्साहन करेगी। मैं आपको ये भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी इस विधान सभा का चुना हुआ नुमाइंदा मनजिन्दर सिंह सिरसा जो है, टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ देहली का प्रेसीडेंट है और ये बच्ची हमारी गाइडेंस में और हमारी टेबल टेनिस एसोसिएशन के चलते ही पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रौशन करके आयी है। मैं इस बात की इस बेटी को जहाँ बधाई देता हूँ हमने तो उसके लिए प्रोग्राम रखा था, हमें ये तो पता नहीं था इतना गोल्ड मैडल भी वहाँ से लायेगी। पिछले गोल्ड मैडल का प्रोग्राम भी अभी उसका मई में रखा था कि बच्चों के एग्ज़ाम्स खत्म

हो जाएंगे तो फिर उस बेटी को बुलाके बढ़िया आपका सम्मान करेंगे। पर हमें इस बात का और भी गर्व है कि जिस मीटिंग के अंदर हमने उस बच्ची के लिए प्रस्ताव रखा, आज विधान सभा के अंदर उस बच्ची के लिए प्रस्ताव रखा। सर यकीनी तौर पर जहाँ उसने अपने माँ–बाप का नाम रौशन किया है, जहाँ उसने इस देश का नाम रौशन किया है, हम सभी लोग उस बेटी को जहाँ बधाई देते हैं, हमें बहुत गर्व है इस बात का कि वो बेटी दिल्ली से भी है और दिल्ली टेबल टेनिस एसोसिएशन की मेम्बर भी है, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः शिव चरण जी।

श्री शिव चरणः उसने हंस राज स्कूल के अंदर ट्रेनिंग ली, ये हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है। पंजाबी बाग स्कूल के अंदर...

माननीय अध्यक्षः ये रविवार की घटना है जब उसने गोल्ड मैडल जीता। सोमवार को अखबारों में आया। मैंने सोमवार को भी इंतजार किया, मंगलवार को भी इंतजार किया कोई सदस्य उठायेगा आज सरिता सिंह ने उठाया, मैं बधाई देता हूँ। कोई और सदस्य... हमको इस पर राजनीति से ऊपर उठकर लाना चाहिए था। लेकिन आज अंतिम दिन है तो मैंने भी इसमें शरीक होना चाहा... हाँ, क्या? पक्का?

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): वो तो शाम तक पता चलेगा। हमें आने से पहले कहाँ पता होता है कि कल तक, कल मीटिंग है। ऐसे ही होता है। कल भी ऐसे ही हुआ। आज तो केबिनेट मीटिंग.

माननीय अध्यक्षः भई विजेन्द्र जी के ध्यान में कोई और विषय आ गया हो तो मैं क्या करूँगा?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः सर, पूरे डेमोक्रेटिड तरीके से होता है, सदन में ही तय होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सदन की भावनाओं को आगे रखते हुए दिल्ली की बेटी मणिका बत्रा को बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सिर्फ मणिका बत्रा नहीं बल्कि इस कॉमन वैल्थ गेम्स की पूरी जो टैली, रोजाना हम देख रहे हैं। पूरे देश के बच्चे उसमें मैडल्स ले रहे हैं और टैली हमारी बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन जिस दिन मणिका बत्रा जीती तो उस दिन तीन और लड़कियों ने गोल्ड जीता था उनको टाइटल आया; गोल्डन गर्ल्स, वो हरियाणा से थी मनुकाटर और वेटलिफ्टिंग में पूनम यादव। उसी दिन हिना सिद्धू ने सिल्वर भी जीता। शूटिंग में तो ये सब गोल्डन गर्ल्स के नाम से जानी जा रही हैं और उन्हीं गोल्डन गर्ल्स में एक गर्ल हमारी दिल्ली की भी है और आपने उसका और परिचय भी दिया। शिवचरण जी ने भी परिचय दिया एसोसिएशन के लिए, उस क्षेत्र कालोनी के लिए, उस स्कूल के लिए जहाँ से वो है, पूरी दिल्ली के लिए, हम सब के लिए गर्व की बात है। दिल्ली सरकार की ओर से जो हमारी स्कीम है, उसमें कॉमन वैल्थ में गोल्ड लाने पर खिलाड़ी को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने के लिए 14 लाख रुपये की राशि पुरुस्कार स्वरूप दी जाती है। मैं सुनिश्चित करूँगा कि जल्द से जल्द उस तक पहुँचे। इसके अलावा भी अगर कोई और खिलाड़ी भी गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज़ लाते हैं तो सरकार की पॉलिसी है कि अभी हमने बनाई थी दो साल पहले ही कि गोल्ड लाने पे कॉमन वैल्थ में स्पेशली 14 लाख रूपये, सिल्वर में 10 लाख रुपये और ब्रॉन्ज पे छः लाख रुपये का पुरुस्कार दिया जाता है। इसके साथ–साथ जो अभी स्कीम बनायी गई है, सरकार ने जिसको कि फाइनलशिप देके उसके खिलाड़ियों का चयन कैसे होगा, क्या होगा... पर निश्चित रूप से ये बच्ची तो उसमें रहेगी ही रहेगी क्योंकि ये तो अचीवर है। हर साल सरकार ऐसे खिलाड़ियों को जो दिल्ली का प्राइड हैं, दिल्ली आज जैसे गर्व

कर रही है, वैसे हमेशा उनकी परफॉर्मेंस पे गर्व करती है। वैसे खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है जो इस साल से लागू हो रही है। जिसका मैंने बजट भाषण में भी जिक्र किया था कि ऐसे खिलाड़ियों को 16 लाख रुपये तक की मदद उनके हवाई यात्रा के लिए, उनकी कोचिंग के लिए, उनके इक्विपमैंटस के लिए, जो भी उनको चाहिए 16 लाख रुपये पर ईयर तक की मदद सरकार करेगी। तो इस बच्ची को भी निश्चित रूप से वो मिलेगा आगे और यहीं पे मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि इसके अलावा ये तो जो एक्सेलैंट स्पोर्ट पर्सन्स हैं, उनके लिए सरकार की योजना है, इसी तरह से सरकार ने बड्डी स्पोर्टस पर्सन के लिए भी योजना बनाई है क्योंकि आज जैसे आप बता रहे हैं कि वो आज नहीं बन गई है अचानक, उसपे मेहनत हुई है। उसपे उसके स्कूल ने, उसकी एसोसिएशन ने, उसके परिवार ने, उसकी टीम ने मेहनत की है तो ऐसे बड्डी स्पोर्टस पर्सन को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने नीति बनाई है और उसमें भी हम खिलाड़ियों के खर्चे से लेकर उनके, कोचिंग के खर्चे से लेकर उनके डाईट तक के लिए, उनकी कोचिंग के लिए, उनके इन्शोरेंस तक के लिए, उनके टिकट्स तक के लिए पैसे देते हैं, वो भी स्कीम बनाई है और एक ओर इन्टरेस्टिंग स्कीम जिसका मैं यहाँ... क्योंकि स्पोर्टस पे बात हुई है, जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि ये सारी चीजें कहीं न कहीं स्पोर्टस में आ के क्लब होंगी। हमने दिल्ली के जितने गवर्नमेंट स्कूलस हैं, शाम को आम तौर पे वो बंद रहते हैं, हमने पिछले दो साल पहले ये प्रयोग किया था, हमने दिल्ली के स्पोर्टस पर्सनस को, छोटी–छोटी एकेडमिज, जो बड़ी–बड़ी चल रही हैं, उसके अलावा जो छोटी–छोटी मोहल्लों में भी चलती हैं, उनको भी हमने इन्वाइट किया था कि अगर आप बच्चों को प्राइमरी लेवल... क्योंकि एक हो गया एक्सीलेंस स्पोर्टस परसन उसके पीछे तो सब भागते हैं, हम सब कहते हैं कि ये हमारी बच्चा है, हम सब प्राइड करते

हैं। दूसरा है, बडिंग स्पोर्टस पर्सन जिसमें सम्भावनाएं भी दिख रही होती हैं उसमें भी आज जाते हैं सपोर्ट करने। उससे पहले भी एक लेयर है जो किसी झुग्गी में, किसी अनऑथोराइज कॉलोनी में, कहीं किसी बड़े घर, कोठी में रह रहा होगा, रह रही होगी, अभी वो स्ट्रगल कर रही है, उस लेयर तक आने में भी बडिंग स्पोर्टस पर्सन की कैटेगिरी आने में अभी समय है या शायद उसको वो लेयर क्रास करना अभी बाकी है, उसको भी हम सपोर्ट कर सकें, इसके लिए हमने योजना बनाई है कि ऐसे खिलाड़ी और जिनके अंदर प्रतिभा है... पर अभी वो बडिंग स्पोर्टस पर्सन की कैटेगिरी में नहीं आए। ये दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलस में शाम को, दिल्ली की एकेडमिज, अलग–अलग स्पोर्टस की, इंडिविजुअल कोचिज, इंडिविजुअल एक्सीलेंट स्पोर्टस पर्सन्स अगर कोचिंग देना चाहें तो शाम को हमारे स्कूल ग्राउंडस को, स्कूल की फेसलिटीज को यूज कर सकते हैं। ये स्कीम हमने दो साल पहले चलाई थी। करीब 70 स्कूल्स में सक्सेसफुली चली। वहाँ कुछ स्कूल्स में बहुत बढ़िया चली, जो पॉयलेट पे चलाई थी। अब हमने दिल्ली के सारे स्कूल्स में इसको खोल दिया है और संभवतः इसी महीने मुझे जहाँ तक, अभी मेरे पास डेटा नहीं है पर लगभग–लगभग 6 सौ, 7 सौ एकेडमिज और इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ने अलग–अलग स्कूल्स लेने के लिए एप्लाइ किया है तो हमारी कुल मिलाके देखें तो अभी 750 के करीब बिल्डिंग हैं जिनमें डबल शिफ्ट मिला के 1000 से अधिक स्कूल चलाते हैं तो इन 700 बिल्डिंगस में से 600–650 बिल्डिंग को शाम को स्कूल के समय के बाद कोचिंग देने के लिए लोगों ने एप्लाइ किया है। उनमें से जो भी सुटेबल होंगे, जो भी पॉलिसी पे आते होंगे, उनको हम देंगे और वहाँ हमने कंडीशन यही लगाई है कि हम जिन बच्चों को भी ट्रेनिंग देंगे, वो कोचेज उनमें से 50 परसेंट बच्चे गवर्नमेंट स्कूलस से होंगे कम से कम, जिनको फ्री ट्रेनिंग देनी पड़ेगी 100 परसेंट हो जाएं बहुत अच्छी बात है पर अगर उन्हें मार्केट

से, प्राइवेट स्कूल्स से, कहीं से भी प्लेयर्स लेने हैं जिनसे वो फीस भी चार्ज करते हैं तो कम से कम 50 परसेंट पार्टिसिपेंट उनके उसमें, इससे होंगे और उनको फ्री होंगे। साथ में, अंत में स्पोर्टस के संदर्भ में क्योंकि आज तक बधाई देने की बात थी, बताऊँ कि अभी हाल ही में दो स्वीमिंग पूल्स का भी सरकार ने शुरूआत की है और जो बहुत वर्ल्ड क्लास स्वीमिंग पूल्स बनें है; गुलाब सिंह जी की विधान सभा में पहले से ही स्पोर्टस की, मतलब दिल्ली के अलग–अलग क्षेत्रों में जहाँ–जहाँ पॉसिबल है, दिल्ली सरकार की ओर से पिछले दो–तीन साल में काफी फैसिलिटीज डेवलप हुई हैं। ये खिलाड़ी इनका भी इस्तेमाल करें, जो छोटी स्कीम्स हैं, प्राइमरी लेवल की, बड़ी स्पोर्टस पर्सन की, एक्सीलेंस स्पोर्टस पर्सन की, इनका भी इस्तेमाल करें। सभी एमएलए साथियों को भी मैं कहूँगा कि आपके क्षेत्र में भी जो खिलाड़ी हैं, उनको भी प्रोत्साहित करें इन स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए क्योंकि उन तक भी ये सूचना ठीक से पहुँचे और उसका फायदा उठाएं, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। राजेश जी, हम सब चाहते हैं कुछ बोलें लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय कल रोका था वो फिर, बोलिए क्या बोल रहे हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, आप बोल चुके प्लीज, प्लीज हो गया, सारा।

श्री राजेश गुप्ताः सर, जिस तरीके से आपने अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बात कही कि जो ऐसे बच्चे जो अभी आ रहे हैं, शायद कल के बहुत होनहार बच्चे बन सकते हैं। उसी में मेरी विधान सभा के

अंदर दो बच्चे; एक का नाम निसार खान है जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि झुग्गियों में रहने वाला बच्चा, वो दिल्ली सरकार के सहयोग की वजह से पहले जमैका ट्रेनिंग के लिए गया और आज वो अमेरिका के अंदर है और उसको देखते हुए एक ओर बच्चा जो शिव कुमार है, वो भी इस वक्त जमैका ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है और पिछले अभी 3–4 महीने पहले जो अखबारों में आया था कि हिन्दुस्तान का दिल्ली का हुसैन बोल्ट... इस तरह की प्रतिभाएं दिल्ली सरकार के सौजन्य से और मेहनत करते हुए इस तरीके से निकल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से दिल्ली भारत का नाम ऐसे ही रोशन होता रहेगा, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः सभी सदस्य बोलना चाहेंगे, मैं फिर...

माननीय उप मुख्य मंत्रीः सिर्फ संज्ञान में दे रहा हूँ, सब मुद्दे पर सब बोलेंगे और फिर ये भी अपेक्षा है कि सैशन आज ही खत्म हो जाए तो इसको दोनों को देख लीजिए, कॉन्ट्राडिक्शन है।

माननीय अध्यक्षः भई अंतिम सिरसा जी और दलाल जी बस इसके बाद और नहीं, ये विषय अब यहीं समाप्त हुआ।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बहुत अच्छी बात डिप्टी सीएम साहब ने कही। बस, मैं एक बात इनके संज्ञान में लाना चाहता था कि जो एसोसिएशनस जैसे आप भी समझते हैं कि एसोसिएशन का काम ही यही है कि बच्चे आगे बढ़ के आते हैं, एक हम चैलेंज फेस कर रहे हैं अगर आप उसमें भी हमें कर दें राहत दें जो एसोसिएशनस हैं, जब हम स्टेडियम बुक करते हैं, अब उसके इतने ज्यादा पैसे बुक कर दिए कि हमारे वो बस में नहीं है, हमारी कैपेसिटी में नहीं है कि हम वो पे कर सकें। क्योंकि एसी चार्ज, सब कुछ मस्ट है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है जो इंडियन

ओलंपिक एसोसिएशंस के... जो एफिलेटिड ऐसासिएशन हैं, उनके लिए आप कम से कम इतनी राहत दे दें क्योंकि वही ये बच्चे वहाँ तक पहुँचाने का काम करती हैं कि उनके लिए ये कोई कन्सेशन कर दें 5 हजार फिक्स रेट कर दें ताकि हम स्टेडियम बुक करके... इन बच्चों ने खेलना है और हमने कुछ स्कूल का फंक्शन या ओर तो करना नहीं।

दूसरी सर, मेरी एक सब्मिशन ये है जो आपने स्वीमिंग पूल की बात कही, हमारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमैंट कमेटी का श्री गुरू हरकिशन पब्लिक स्कूल वसंत विहार इंडिया का, देश का पहला स्कूल था जिसके अंदर हमने इंटरनैशनल लेवल का स्वीमिंग पुल बनाया था और डिप्टी सीएम महोदय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे उसके कारण इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हैं, हमारे डॉयरेक्टर एजूकेशन रोज हमारा स्कूल बंद कराने पे जा रहे हैं कि आपका स्कूल बंद कर देंगे, आप ये स्वीमिंग पूल बंद करो और आपको शॉकिंग होगा ये।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, ये विषय, ये विषय व्यक्तिगत ले लीजिएगा। नहीं प्लीज, मैं इसमें, आपका हो गया, नहीं ये व्यक्तिगत विषय है, इनको आप अलग से लीजिएगा, सिरसा जी, बैठिए प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः सर, एक मिनट उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। स्वीमिंग पूल को ले लीजिए, एक सैकंड सर, मेरी सब्मिशन सुन लो। मैं ये चाहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय, अभी पानी नहीं भरा फिर भी हमें नोटिस दे दिया कि आप पानी भरो, आप जब सरकार ही चला रहे हैं, हम भी एक बैस्ट काम कर रहे हैं हमारा अपना तो है नहीं ये। दिल्ली सिख गुरूद्वारा मैनेजमैंट कमेटी की प्रॉपर्टी है अगर आप इसमें हमारा साथ देंगे तो बहुत मेहरबानी, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः हाँ दलाल जी, एक मिनट में पूरा।

श्री सुखवीर सिंह दलालः अध्यक्ष जी, हमारे उप मुख्य मंत्री जी ने बहुत बढ़िया बातें बताई। उसके साथ ही में मैं एक कड़ी जोड़ना चाह रहा हूँ। इन्होंने बताया कि बच्चे को 16 लाख भी मिलते हैं, सब चीज बहुत अच्छा है लेकिन मैं एक गुजारिश करता हूँ कि दिल्ली सरकार जैसे रेलवे में सब स्पोर्टस की भर्ती होती है लेकिन एक हमारी दिल्ली सरकार में पिछले 8–10 साल से कोई भर्ती नहीं हुई स्पोर्टस के नाम से जब कि उससे पहले मेरे गाँव से ही 8–10 बच्चे ऐसे हैं मेरे एरिया से जो स्पोर्टस कोटे से भर्ती हैं दिल्ली सरकार में। बड़े अच्छे काम करते हैं लेकिन 16 लाख रुपए तो एकदम खर्च हो जाएंगे, लेकिन उनकी लाइफ बहुत बड़ी होती है। जब तक वो खेलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उसके बाद वो बच्चे मैं देखता हूँ, एक फूल मुरझा जाता है। तो दिल्ली सरकार से गुजारिश करूँगा कि भई उनके स्पोर्टस कोटे से भर्ती कराई जाएं और उनको एक स्किल के तौर पे मतलब इग्जाम लें, कुछ भी करें एक ये भर्ती हो जाए तो बहुत अच्छा होगा।

दि.न.नि. की कार्यप्रणाली तथा विधायक क्षेत्रीय विकास निधि का दि. न. नि. के क्षेत्रों में उपयोग पर चर्चा

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद सभी का। अब दिल्ली नगर निगम की कार्यप्रणाली तथा विधायक क्षेत्रीय विकास निधि का दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में उपयोग पर चर्चा प्रारम्भ होगी।

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदन के समय के अधिकतम सदुपयोग को ध्यान में रखते हुए चर्चा के दौरान अपने भाषण को मूल विषय

तक सीमित रखें ताकि अधिक से अधिक सदस्य इसमें भाग लें सकें, अनावश्यक उसका विस्तार न करें। मेरी ये व्यक्तिगत प्रार्थना है, इसको सभी लोग ध्यान रखेंगे। कल जो नाम मैंने... मेरे पास जो स्लिप आई थी, मैं उनसे शुरू कर रहा हूँ, श्री शिव चरण गोयल जी। इसके बाद अनिल बाजपेयी जी तैयार रहें।

श्री शिव चरण गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक बापू ने पूछा अपने बेटे से कि बेटे पढ़ना–लिखना जानते हो? कहता है, ''नहीं, मेटना जानते हो? कहता है, ''दोनों हाथों से।'' तो हमारी एमसीडी के ऊपर ये बिल्कुल कहावत चरितार्थ है कि पढ़ने–लिखने में अर मेटने में पूरी तरह से आज कोई भी डॉक्यूमेंटस के नाम पर एमसीडी के पास, एमसीडी के पास कोई डाक्यूमेंटस नहीं, कोई सीलिंग का, कोई प्रोग्राम का, मेटना हो तो ये पूरे डाक्यूमेंटस हैं मेरे पास। एक डी ब्लाक, पार्क, डी ब्लॉक की सड़क बन रही थी मेरे क्षेत्र में, 15 जुलाई, 2017 को उसका उद्घाटन किया गया, सड़क तोड़ के डाल दी गई, सड़क को तोड़ के डाल दी गई उसमें जेई से मैंने पूछा था कि यदि आप इस सड़क को बना सकते हैं तो तोड़ें नहीं, तो उसको मत बनाएं। क्योंकि मुझे पता है इनकी स्थिति ठीक नहीं है। आज उस सड़क पर रोड़ी डाल दी गई और आज तक वो सड़क बनी नहीं है। तो जुलाई से लेकर अब तक आप देख लें कि करीब–करीब मेरे ख्याल नौ महीने हो चुके हैं, वहाँ पर लोग गिर रहे हैं कई हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी, मैं हर जगह इसकी गुहार लगा चुका हूँ डीसी के पास कमिश्नर के पास, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। ये डी... इसका मैं नंबर दे देता हूँ आपको। ये पूरे डाक्युमेंट्स हैं।

माननीय अध्यक्षः नहीं ये सदन पटल पर रख दीजिएगा और कोई है तो इसमें जोड़िए।

श्री शिवचरण गोयलः इसके अलावा 42 सड़कें मेरे एमएलए फण्ड से पेंडिंग पड़ी है, 28 नवम्बर 2016 से।

माननीय अध्यक्षः 28 नवम्बर 2016? एमएलए लेड दे दिया आपने?

श्री शिवचरण गोयलः हाँ जी, पैसे जा चुके हैं, आरडी जैसे जा चुकी है, पेमैंट हो चुकी है। 28/11/2016 से 42 सड़कें जिसके ऊपर कोई कार्रवाई एमसीडी नहीं कर रही। तो ये एमएलए का फण्ड इस जनता का फण्ड अब इस तरह से डेढ़–डेढ़ साल के बाद सड़के नहीं बनेंगी।

माननीय अध्यक्षः कितना अमाऊंट है ये?

श्री शिवचरण गोयलः ये करीब–करीब मेरे ख्याल से ये बनेगा 6 करोड़ के आसपास।

माननीय अध्यक्षः रखिए, सदन पटल पर रखिए।

श्री शिवचरण गोयलः छः करोड़ की अमाऊंट, ये भी मैं अभी पटल पर रख देता हूँ। इसके अलावा मैंने... एक संस्था मेरे पास आई कि दो झूले हमने पार्क में डोनेट करने हैं और वो दो झूले उसने पार्क में डलवा दिए गए और करीब सात महीने से वो दोनों झूले पार्कों में रखे हुए हैं। जब उसको लगाने लगे तो हॉर्टिकल्चर का इंस्पेक्टर आ गया। कहने लगा, ''जी, आप इन झूलों को लगाओगे नहीं।'' मैंने कहा, ''भई क्या दिक्कत है इसमें?'' कहने लगा, जी, कि ऊपर से हमें ऑर्डर आया है कि आप विधायक का कोई भी झूला पार्कों में नहीं लगायेंगे। जिसमें किसी का पैसा नहीं, कोई संस्था दान कर रही है, उसको भी लगाने में भी ऑब्जेक्शन है और वो

सात महीने से झूले उसी पार्क में पड़े हुए हैं। उसको लगने नहीं दिया जा रहा। जयदेव पार्क ये हमारे मोती नगर विधानसभा में दो झूले वहाँ रखे हुए हैं। हमारी पूरी विधानसभा में पिछले दो साल से जितने भी सीवर बने, जल बोर्ड की लाइनें पड़ी। उसके सारे आरआर के पैसे वहाँ जमा हो चुके हैं। उसके बावजूद भी सड़के वैसी की वैसी पड़ी है। वहाँ पर लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो जल बोर्ड को जो काम है, सीवर का जो प्रोग्राम है, उसकी भी सड़कें बनवाई जाएं और मेरी विधान सभा में करीब 300 पार्क हैं। 300 पार्क में 150 पार्क आरडब्ल्यूए ने लिए हुए हैं, वो तो पार्क मेन्टेन है। जो भी पार्क 150 बचे हुए हैं, वहाँ पर मिट्टी उड़ रही है। समरसिबल कोई काम नहीं कर रहा। मैं बार–बार लिखकर दे चुका हूँ कि यदि आपके पास फण्ड नहीं हो और समरसिबल के पैसे आप एमएलए फण्ड से ले ले ताकि पार्कों की दशा को सुधार लें। उसके बावजूद पता नहीं किसका एक निर्देश है कि आपने एमएलए के नाम पर कोई काम करना ही नहीं है। तो यदि पार्क ही नहीं रहेंगे, वहाँ पर दशा इतनी बदत्तर हो जाएगी। इनकी दुश्मनी किसी से भी हो लेकिन पॉल्यूशन जो सबको जरूरी है, उसके ऊपर भी काम नहीं कर रहे हैं। तो आज तो एमसीडी की दशा इस तरह से हो चुकी है कि जैसे सौतेला व्यवहार. छोड़ो, कि काम करना ही नहीं है। तो इनके ऊपर कोई न कोई सख्त लगाम लगाई जाए, सख्त निर्देश दिए जाएं और कोई ऐसी कार्रवाई जिससे काम पर ये बाध्य हो सकें। बस, यही बात थी, बहुत–बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। संक्षेप में रखते जाएंगे सब, तो सबके नाम आ जायेंगे। अनिल बाजपेयी जी। इसके बाद सही राम जी।

श्री अनिल बाजपेयीः मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं अपनी जो मेरे यहाँ ईडीएमसी है, मैं उसके लिए दो मिनट में ही अपनी बात को

रखूँगा, छोटे–छोटे प्वाइंट्स के ऊपर। सबसे पहले सर, जो एमएलए फण्ड है, मान लो हर दिल्ली का कोई भी हमारा, किसी क्षेत्र का विधानसभा का सदस्य है। वो अपने एमएलए फण्ड को लगाता है। मान लो, कहीं एक करोड़ रुपये की सड़क का बजट है, कहीं 20 लाख की सड़क है, कहीं 12 लाख की सड़क है। मान लो जब टेंडर और वर्क ऑर्डर सर, हो गया। मान लो अगर 10 लाख की कहीं सड़क है और टेंडर और वर्क ऑर्डर में साढ़े आठ लाख रुपये की आई तो डेढ़ लाख रुपये सर, उसका बच गया और इस तरीके से सारे विधायकों का पैसा एमसीडी के पास पड़ा हुआ है। आज तक वो पैसा न तो यूडी में वापस किया गया और न हमारे डूडा में वापस किया गया। आखिर एमएलए फण्ड का पैसा है, अगर वो पैसा वहाँ पर वापिस कर दिया जाए तो कम से कम उसका उपयोग एमएलए अपने–अपने क्षेत्र में लगा ले और सर, ये बहुत गंभीर मसला है। आपके भी क्षेत्र का मामला है। मंत्री जी बैठे हैं उनका भी सारे सभी दिल्ली के विधानसभा का है। तो मेरा अनुरोध है कि जो पैसा जहाँ–जहाँ एमसीडी में पड़ा हुआ है, उसको तुरंत यूडी में या वहाँ की जो है, उसमें वापस किया जाए उसको।

दूसरा सर, ये है कि हम लोग जैसे सब लोग सुरक्षा की बात करते हैं सर। सुरक्षा की दृष्टि से एमएलए... हम लोग जो आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर कालोनी में गेट लगवाना चाहते हैं और सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये हैं कि मेरे इलाके में राजगढ़ या कुछ ऐसी पास कालोनी थी या जो ऐसी कालोनी थी, जहाँ सर, हम लोग पैसा लगाना चाहते थे। और दो ईडीएमसी के के अंदर दो विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर एमएलए फण्ड से सुरक्षा की दृष्टि से आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर गेट लगा दिए गए। जब मैंने कहा कि मैंने चिट्ठी दी तो मना कर दिया कि जी, हाई

कोर्ट का ऑर्डर है। तो हमने कहा, जब वहाँ गेट लगा दिए हैं तो वहाँ भी तो हाई कोर्ट का ऑर्डर था। जब विधायक अपना फण्ड दे रहा है, आरडब्ल्यूए साथ मिलकर लगाने को तैयार है तो प्रॉब्लम क्या है सर? ये तो... जहाँ दो जगह अगर दो विधानसभा में लगाए गए तो और विधान सभा में मेरी ईडीएमसी के अंदर मेरी विधानसभा में मैं पैसा दे रहा हूँ। मेरे इलाके में इसको फण्ड को लगाया जाए।

नंबर–तीन सर, कि एमएलए फण्ड से जितनी भी लाइट लगी हैं, उनमें से 80 परसेंट सर, बंद हैं। कई जगह हाई–मास्ट लाइट लगी हुई हैं। कई बार हमने जो है, हमने ईडीएमसी के अधिकारियों से कहा कि ये कहा, कि ठीक है, ठीक कर जाएंगे जी। एकाध लाइट ठीक कर गए सर, ठीक कर गए, बाकी तीन दिन में ठीक हो जायेंगी। हमने अपने पैसे से लाइट लगवाई हैं और हम बीएसईएस वालों को कहते हैं तो कहते है कि जी, ये मेन्टेनेंस का काम तो ईडीएमसी करेगी।

मेरा अनुरोध है सर जवाबदेही तय की जाए। अगर एक एमएलए अपना पैसा देता है और उसके एमएलए फण्ड से लाइट लग रही है तो लाइट तो चालू होनी चाहिए। अब हमने वहाँ लाइट लगवा दी, 10 दिन बाद सर लाइट बंद हो गई। तो जितना हमने भलाई का काम किया, गाली का काम और दस गुणा हमको पड़ जाएगा। मेरा अनुरोध है कि कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हैं, इस संज्ञान को बहुत सीरियसली लें और जब पैसा एमएलए फण्ड से लग रहा है तो उसको सर, चालू कराएं इसको।

दूसरा सर, ये है मेरी विधानसभा में बड़ा दिलचस्प मामला आया अभी चार दिन पहले सर सड़क अगर हमारी बन रही है एमएलए फण्ड से। हमने साफ तरीके से कहा कि देखिए, सड़क का मकान नीचे नहीं होना चाहिए।

सड़क मतलब मकान के ऊपर सड़क नहीं होनी चाहिए। सड़क को टूटकर बनाया जाए। मैं साढ़े ग्यारह बजे रात को परसों वहाँ पहुंचा, जहाँ वहाँ सड़क बन रही थी। ठेकेदार ने क्या काम किया, बिल्कुल बगैर सड़क को तोड़े या खोदकर उसके ऊपर स्लिप डाल दिया। मैंने कहा, ''भई, ये क्या कर रहे हो?'' कह रहा, ''जी, जेई महोदय ने कहा है।'' मैंने कहा कि जेई को फोन लगाओ, जेई का फोन बंद। मैंने कहा कि काम रोक दीजिए। मैंने वहाँ काम रुकवाया है। जब हम जनता के बीच में जाकर ये कहते हैं कि साहब, ये देखिए हमारा ये काँग्रेस वाला राज नहीं है। जहाँ रात को 12 बजे के बाद सड़क बनती है। यहाँ तो सड़क जब हम खड़े होकर बनवाते हैं जब सड़क खोदकर बनवाने के लिए बोला है। तो कम से कम जिसके लिए सही काम के लिए है, वो काम उससे करा जाए और ये बड़ा सीरियस मामला है। इसकी सर, जाँच भी करानी चाहिए। कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हैं।

दूसरा सर, ये है कि मेरा 90 परसेंट काम एमसीडी से मैंने कराया है और संतोषजनक भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा है। लेकिन बहुत जगह प्रॉब्लम क्या आ रही है, बग्गा जी हमारे, यहाँ बैठे हुए हैं। एक सड़क जो मेरी विधानसभा में नहीं आती है सर, विधानसभा क्षेत्र बग्गा जी का है, नगर निगम में काऊंसलर बीजेपी का है। लेकिन जैन ढाबे से लेकर और ईस्ट आजाद नगर तक के लोग सबसे ज्यादा मेरे क्षेत्र में आते हैं। सबसे ज्यादा मैं एमसीडी के पहले कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करता रहा, बोले, ''जी, हम बनवा देंगे।'' नहीं बनी। अंत में हारकर हमने यमुनापार विकास बोर्ड से सर, एक करोड़ 38 लाख रुपये मैंने दिया है, प्रोजेक्ट वालों को। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप भी सर, जैन ढाबे की तरफ या कभी झील की तरफ जायेंगे...

माननीय अध्यक्षः किस डेट में, विकास बोर्ड में किस डेट में? विकास बोर्ड ने किस डेट में दिया है?

श्री अनिल बाजपेयीः एमसीडी को दिया है, हमने दिलवाया है।

माननीय अध्यक्षः नहीं किस डेट में दिया है, ऑन रिकॉर्ड डेट बताइए ना।

श्री अनिल बाजपेयीः ये डेढ़ महीना हो गया सर।

माननीय अध्यक्षः चलिए, ठीक है।

श्री अनिल बाजपेयीः बग्गा जी का क्षेत्र है, पूछिए। मैंने बग्गा जी से भी रिक्वेस्ट की है। 38 लाख रुपये इन्होंने दिया है और एक करोड़ 40 लाख रुपये मैंने दिया है। इसलिए कि ज्यादातर लोग सर, मेरी विधानसभा में आते हैं।

एक सर, मैं बताना चाहता हूँ; एलईडी की लाइट्स का था हमारे यहाँ, एलईडी लाइट्स का था। यहाँ पे मैंने डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से पूरी विधानसभा के सारे मेन रोड हैं, सब जगह एलईडी लाइट... हमने पैसा दिया और उसके बाद एमसीडी ने मेरा काम रुकवा दिया था सर, वहाँ पर। लेकिन कमिश्नर अच्छे थे वो, मैंने उनसे कहा। मैंने कहा 550 वॉट की लाइट है। मैं 120 वॉट की लाइट आपको लगवाकर दे रहा हूँ। उससे अच्छी रोशनी आती है, काम क्यों रोक दिया गया? स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमेन फ्लोर पर बैठ गए वहाँ भूख–हड़ताल पर कि जी, हम नहीं लगने देंगे। हमने कहा, ''साहब, बताइए, हम तो सरकार का भला कर रहे हैं। कहाँ 550–1000 वॉट की लाइट, कहाँ 120 वॉट की लाइट। हम तो पैसा सरकार का बचा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जब मैंने कहा कि मैं कल से मीडिया वालों को

बुलाकर... कहा कि मैं कल से बैठूँगा भूख–हड़ताल पे, तब जाकर पुराने कमिश्नर साहब ने बुलाकर स्टेंडिंग कमेटी को, उनको बहुत डाँटा चेयरमैन को। मेयर को डाँटा कि ये भलाई का काम है, इसको करने दीजिए।

माननीय अध्यक्षः हो गया ना वो काम? हो गया ना?

श्री अनिल बाजयेपीः एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जो मेरे यहाँ है। देखिए सर, एमसीडी कमिश्नर साहब बैठे हैं, मैं एक बात सर, आपके सदन के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, भेदभाव खत्म कर दीजिए। गाँधी नगर में सीलिंग का मसला बहुत सर जोरों से चल रहा है। सर, बहुत जरूरी है ये और जिन लोगों...

माननीय अध्यक्षः बाजपेयी जी, सीलिंग पे चर्चा हो चुकी है।

श्री अनिल बाजपेयीः नहीं सर, बहुत जरूरी है ये।

माननीय अध्यक्षः नहीं बाजपेयी जी, नहीं, मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूँ, बैठ जाइए। नहीं, ऐसे तो सदन चल ही नहीं पाएगा।

श्री अनिल बाजपेयीः सर, मेरा हाथ जोड़कर... सर, आधा मिनट।

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं बिल्कुल नहीं अलाऊ कर रहा।

श्री अनिल बाजपेयीः इतनी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, उनको भी नोटिस भेज दिए गए हैं। कम से कम जहाँ फैक्टरी है, वहाँ नोटिस भेजिए। जहाँ फैक्टरी नहीं चल रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, उन सबको नोटिस भेज दिए गए सर। ये कैसे चलेगा सर?

माननीय अध्यक्षः भई ऐसे तो फिर ये चर्चा नहीं हो पाएगी।

श्री अनिल बाजपेयीः ये कब सुनेंगे, बताइए? मैंने कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की है।

माननीय अध्यक्षः आप एक ओर तो कह रहे हैं, बहुत अच्छे हैं कमिश्नर साहब। एक ओर कह रहे हैं नोटिस भेज दिए।

श्री अनिल बाजपेयीः सर, सबको नोटिस भेजे हैं।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, अब बैठिए, प्लीज। बैठिए। श्री सही राम जी।

श्री सही रामः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आज पर्सनल अपनी बात न करके जो मैंने पिछले दो–तीन दिन में जबसे ये चर्चा पे विचार हो रहा है, तब से जो वर्क की है, वो ये है कि आज के समय में पिछले एक साल से जब से दिल्ली में दोबारा से निगम में ये आए हैं बीजेपी वाले, इनके बीच में और निगम कर्मचारियों के बीच में एक बहुत अच्छा कोर्डिनेशन बन गया है।

माननीय अध्यक्षः ये डाक्युमेंट्स सदन पटल पे रख दो आप भी। एक सैकण्ड... कहाँ गए, गोयल कहाँ गए? आप भी बाजपेयी जी अपनी डेटों के साथ रखो।

श्री सही रामः बड़ा अच्छा कोर्डिनेशन इनके बीच में चल रहा है। कमिश्नर महोदय भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको भी जानकारी होगी जिस तरह से हमारा एमएलए हेड प्रतिवर्ष चार करोड़ खर्च कर सकते हैं हम अपने क्षेत्र में। इसी तरह निगम के काउंसलर का भी एक बजट फिक्स है। 50 लाख हो, 60 लाख हो, 70 लाख हो, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन इन्होंने क्या एक षड़यंत्र किया है कि एमएलए के काम न हों। जब इनकी लिमिट ही 50 लाख से 80 लाख के बीच में है तो ये निगम कर्मचारियों

के साथ मिलके तीन–तीन चार–चार करोड़ के एस्टीमेट बना देते हैं निगम पार्षद। जब एमएलए कहता है कि भई इस रोड वे रोड की हालत खराब है इस रोड को एमएलए हैड से बना दो, तो कहते हैं, ''जी नहीं'', काउंसलर साहब ने इसका एस्टीमेट बनवा रखा है।'' ये समझ में नहीं आती मेरी में कैसा एस्टीमेट बना लेते हैं, जब उनकी लिमिट ही 50 लाख की या 70 लाख की है तो 3–3, 4–4 करोड़ रुपये के एस्टीमेट ये अधिकारी कैसे उनके बनवा लेते हैं और कैसे ये जवाब दे देते हैं एमएलए को? कहते हैं, जी नहीं, काउंसलर साहब ने इस हैड में ये अपने बना रखे हैं नम्बर एक। नम्बर दो अध्यक्ष महोदय, मैं अनऑथोराइज कालोनी के ऊपर चर्चा करूँगा। अनऑथोराइज कालोनी में जहाँ तक मेरी जानकारी है, हर जगह, हर गली, हर रोड ये नहीं बना सकती, नगर निगम नहीं बना सकती। कुछ ही जगह ये अपने विकास फण्ड लगा सकता है

काउंसलर। लेकिन मेरे यहाँ पे मैंने देखा है लाल कुआं पे प्रह्लादपुर, विश्वकर्मा कालोनी, प्रेम नगर वहाँ पे जब एमएलए हैड से या एससी/एसटी हैड से या अनऑथोराइज कालोनी के हैड से 50–50, 60–60 लाख के टेंडर लगे हुए हैं ऑलरेडी रोड बनने जा रहे है तो ये किस आधार पे डेलीवेज कर्मचारी किस आधार पे 4–4, 5–5 लाख के एस्टीमेट बनाके वहाँ बीच बीच में टैकली सी लगा जाते हैं जो कि मैंने कई बार इस बात चर्चा की लेकिन वो कहते हैं, ''जी, काउंसलर हैड का है।'' मैं मान रहा हूँ, उन्हें भी काम करना चाहिए, वो करें। हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक रोड को बनाने के लिए 70 लाख रुपये चाहिए, 80 लाख रुपये चाहिए उस रोड को बनाने के लिए। एमएलए हैड का, एससी/एसटी हैड का या अनऑथोराइज कालोनी हैड का उसमें टेंडर ऑलरेडी लगे हुए हैं तो उसके बाद ये कैसे 4–4, 5–5 लाख के टेंडर लगा आते हैं, ये मेरी समझ में आज तक नहीं

आया। कई बार मैंने ये जानकारी... क्योंकि मैं नगर निगम के जो हमारी विधान सभा की कमेटी है, उसका मेम्बर भी हूँ। वहाँ भी मैंने कई बारी जानने की कोशिश की। लेकिन इसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय एक ओर चीज है इमरजेंसी में जैसे कहीं पानी की लाइन लीक हो जाए, सीवर की लाइन लीक... कहीं ठीक करनी पड़े या बीएसईएस के छोटे छोटे कई फॉल्ट हो जाते हैं वो इमरजेंसी में कहीं गड्ढा खोदना पड़ता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि उस रिपेयर वर्क में भी इनके निगम कर्मचारी जो जई है या उसका जो मेट है, उस कॉन्ट्रेक्टर के उस ठकेदार को उस मेन्टेनेंस के लेबर के फावड़े उठा करके ले जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं साफ कहूँ तो यहाँ कमिश्नर महोदय बैठे हुए हैं पर्सनली मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि जी, आपका जेई, जेडी, एई एक्सईएन कोई भी आज तक एक साल से मेरे यहाँ नहीं आया। मुझे कुछ काम कराने को... जो रोड बनवानी है, आज तक कोई एस्टीमेट नहीं बनाया और पर्सनली मेरे सामने कमिश्नर महोदय ने डीसी को भी और एक्सईएन को फोन पे दो बार बोला। लेकिन बड़े दुःख के साथ यहाँ कहना पड़ रहा है कि जब कमिश्नर महोदय के आदेश के बाद भी इनके जेई, जेडी, एक्सईएन एमएलए के ऑफिस में लैटर लेने नहीं आ सकते, उसके साथ रोड नापने नहीं जा सकते तो इनसे हम आगे उम्मीद क्या करेंगे? मैं समझता हूँ कि ये बड़ा गलत तरीका अपना रहे हैं।

एक चीज ओर अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार हमारी सरकार ने ग्रामीण विकास बोर्ड बनाया है। पहले उसमें जो रूलर विलेज थे, उसी के लिए दो–दो करोड़ रुपये सालाना मिलता था। लेकिन काँग्रेस के समय में तो वो भी बंद कर दिया था। इसके बाद हमारी सरकार ने ये योजना लागू की। इसमें जो हमारे रूलर विलेज के साथ साथ जो दूसरे गाँव हैं, शहरीकृत

गाँव हैं, उनको भी उसमें मर्ज कर दिया, इसमें जोड़ दिया और उस बोर्ड का फैसला आया है कि इस हर गाँव में दो करोड़ रुपया जो दिए हैं, इसको जो एमएलए जिस एजेंसी से चाहे ये बोर्ड का फैसला है कि जिस एजेंसी से एमएलए चाहेगा चाहे, फ्लड से चाहे, डीएसआईआईडीसी से चाहे, एमसीडी से चाहे, उससे ये अपने दो करोड़ के काम उस गाँव में करा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम वहाँ काम कराने जाते हैं तो एमसीडी वाले आ जाते हैं कि जी, नहीं, ये तो हमारे एमसीडी के अधीन है, इसमें आप काम नहीं कर सकते। अब अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि काम कराएं तो फिर कैसे कराएं, किससे कराएं? आपने मुझे इस मौके पे बोलने का मौका दिया, तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद, जयहिन्द।

माननीय अध्यक्षः श्री सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद अध्यक्ष जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आज हमने दी है न आपको?

माननीय अध्यक्षः हाँ, आ गई है मेरे पास। सिरसा जी का कल नाम था, बीच में रुका था। हाँ, मुझे मालूम है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हमें चिंता हो रही है। हम गरीब लोगों को चिंता हो जाती है कि बाद में हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, अभी पूछ लो। कह रहा है इन पाँच करोड़ के चक्कर में अपना हमारा 100 का नोट बंद हो जाए।

माननीय अध्यक्षः उनको ये चिंता हो गई, नहीं–नहीं। उनको ये सिरसा जी, बात को समझ नहीं आया। मेरी भी सुन लो, उनको ये चिंता हो गई। उन्होंने जो दो नाम दिए थे, उनमें आपका नाम नहीं था।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः इन्होंने मेरे से पूछा न, मैंने उनको बताया, नाम गया हुआ है। मैंने बताया न, नाम गया हुआ है।

माननीय अध्यक्षः अच्छा कल का आया हुआ है। हाँ, तो आपको चिंता ही नहीं करनी चाहिए। चलिए, बैठिए। कल बोल चुके। थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए, आपको उठना ही नहीं चाहिए था। चलिए, सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम न इसलिए काफी कॉर्डिनेशन बना के आते हैं। हमें पता है विपक्ष के वार, इनके ऊपर ऐसे प्रहार होंगे हम अन्दर से काफी ट्रेनिंग ट्रूनिंग ले के, प्लानिंग व्लेनिंग करके आते हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इस गंभीर विषय के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष जी, जो मैंने पिछले कल भी ये सारा मसला देखा और हम प्रैक्टिकली इन चीजों को सबको फेस करते हैं। जो दो–तीन बड़ी प्रॉब्लम्स हैं; पहले तो ये काउंसलर... मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम जो है, ये पार्टी की नहीं है, पार्टी का नाम बार बार लिया जाता है। प्रॉब्लम है काउंसलर्स की और एमएलए की कोऑर्डिनेशन न होना। जिसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और वो उसके अन्दर सभी की है, चाहे वो किसी पार्टी से हो। जैसे कल बाजपेयी साहब ने कहा कि मेरे तो अपने काउंसलर भी मेरी अपनी पार्टी के हैं। यहाँ किसी ने भी कहा... मैं एक संक्षेप में बात कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, दिक्कत क्या आ रही है जो बड़ा चैलेंज है कि जब भी हमारे एमएलए लेड का फण्ड जाता है, उसके ऊपर हमें हर तरह से मार पड़ती...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भाई बाजपेयी जी, प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः नहीं किसने कहा हो। चलो, मैं माफी चाहता हूँ। आपने भी कहा होगा, किसी ने भी कहा हो। जिसने भी कहा है, नहीं, कोई अच्छा... अगर कोई दिल्ली में आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद नहीं है तो अच्छा है। मैं तो सोचा था है, पर आप बता रहे हो नहीं है तो धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि जो हमारे एमएलए लेड का पैसा जाता है अगर तो हम निगम पार्षद, निगम को देते हैं, एमसीडी को देते हैं तो पीडब्ल्यूडी से मुड़कर वापिस जवाब नहीं आता। कभी वो डूडा में फंस के रह जाता है, कभी वो पीडब्ल्यूडी में फंस के रह जाता है। मैं अपनी अगर मिसाल दूँ तो मेरे सारे के सारे पैसे मेरे रोज लड़ाई झगड़े करने के बावजूद वो सारे के सारे पीडब्ल्यूडी में पेंडिंग हैं। मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा उसके चलते। अब ये कोऑर्डिनेशन की कहाँ कमी है, पीडब्ल्यूडी की और एमसीडीज के काम की कोई कोई रेखा है जो हम नहीं खींच पा रहे। कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म बना नहीं है, बना नहीं पाए हम, जिसके कारण हमें ये रोज रोज चैलेंज फेस करना पड़ता है। सिचुएशन यहाँ तक, बस।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई सरिता जी, प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अच्छा, अच्छा अब हम गुमराह करने लग पड़े। नहीं, नहीं, हमें आरती दो, हम आरती करते हैं आम आदमी पार्टी की। आरती करते हैं यहाँ बैठके। नहीं आरती ले आओ, मैं आरती करता हूँ दीया दो मेरे को... अध्यक्ष महोदय, दीवे ला दो, मैं आरती करता हूँ, यहाँ आम आदमी पार्टी की आरती करनी चाहिए हमें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सरिता जी, बैठिए प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः भई मैं आरती करने के लिए नहीं आया, अपनी बात बताने के लिए आया हूँ। कमाल हो गई है! हमें अपनी बात भी नहीं करने देंगे आप, हमें यहाँ जो दिल करता है, आप बोले जाते हैं। कभी कोई मोदी को बोलता है, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर को गालियाँ निकालता है, कोई सीएस को। अरे भई! हम अपनी बात करते हैं, वो भी नहीं करने देते और फिर ये कहना... अच्छा, एक काम करना, मैं तो बैठ ही रहा हूँ, नहीं बोलूँगा।

माननीय अध्यक्षः मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये बोल रहे हैं मेरे को, ये मंत्री भी सफाई देते दिखा दूँगा।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः दिल्ली की सरकार अगर गलत है तो गलत न कहें हम वहाँ पे। कमाल हो गई है!

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये उन्हीं के हाथ में पैमाना दे दो, झूठ और सच तय करने का भी।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः दिल्ली की सरकार अगर गलत है तो गलत ना कहें, वहाँ पे। कमाल हो गयी है!

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ बैठें।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः माफी माँगो, गुस्सा है तो चंदा दो। नहीं ये कहते हैं, ''माफी मांगो।'' नहीं, गुस्सा है तो चंदा दो, ये बोले। नहीं, ये बोले।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी बैठिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः कमाल है!

माननीय अध्यक्षः बैठिए बैठिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः तुम ये कहो, गुस्सा है, तो चंदा दे दो।

माननीय अध्यक्षः मैं कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, बैठिए। बैठिए प्लीज, सही राम जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः माफी माँगो। हम कुछ बोलें तो चुप कर जाओ। आरती ले आओ आरती। इनकी आरती कर देते हैं यहाँ पे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ये सारी चर्चा रह जाएगी, आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं।

श्री जगदीश प्रधानः चर्चा कराना ही नहीं चाहते, कराना नहीं चाहते।

माननीय अध्यक्षः नहीं, ये चर्चा सारी रह जाएंगी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मकसद इनका ये है कि चर्चा न हो।

माननीय अध्यक्षः जो सदस्य तैयारी करके लाये हैं, अरे! मुझे करने तो दोगे। जो कुछ करना है, आप लोगों ने करना है, कर लीजिए फिर।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः सरकार का काम तो स्पीकर कर रहे हैं और स्पीकर का काम तुम कर लो।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ठीक हो जायेगा।

माननीय अध्यक्षः बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई सौरभ जी मैंने, मैंने गोयल साहब से कहा न पेपर रखो, अनिल बाजपेयी जी से कहा है न, पेपर रखो, अब वो स्टेटमेंट उनको पूरा होने दें। मैं बोलूँगा अगर पीडब्ल्यूडी का कोई पैसा रूका है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बिल्कुल।

माननीय अध्यक्षः कम से कम बैठ के सुन तो लें।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः कहने दो बात को, पेपर भी रखेंगे, अमाउंट भी बतायेंगे और सारे के सारे पीडब्ल्यूडी में ही रुके हुए हैं, ये भी बताएंगे और एक बार नहीं।

माननीय अध्यक्षः भई सिरसा जी, देखिए।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अरे! अपनी बात करूँगा मैं।

माननीय अध्यक्षः ऐसे नहीं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं करूंगा।

माननीय अध्यक्षः मैंने...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः कैसे करूँ?

माननीय अध्यक्षः ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः तो फिर कैसे करूँ?

माननीय अध्यक्षः आप चिल्लाइये मत।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः नहीं कैसे करूँ?

माननीय अध्यक्षः पहले शांति से बात करिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः इसमें शांति क्या करूँ?

माननीय अध्यक्षः नहीं एक बार शांति...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः वो चिल्लायें तो चिल्लायें, हम बोलें, कुछ तो शांति...

माननीय अध्यक्षः नहीं, रोक रहा हूँ सबको।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम बात कर रहे हैं ना।

माननीय अध्यक्षः आप शांति से एक बार बात...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम क्यों नहीं बात कह पा रहे हैं?

माननीय अध्यक्षः आप शांति से एक बात... मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं शांति से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बात को समझ लीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जी।

माननीय अध्यक्षः हमने एमएलए लैड कॉरपोरेशन पर चर्चा का ये विषय रखा है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जी, बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः एमएलए लैड...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जी।

माननीय अध्यक्षः कॉरपोरेशन से रिलेटेड है, फिर भी अगर आपकी पीडब्ल्यूडी से आपने बात उठाई, मैं रोक नहीं रहा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं एमसीडी से बात बता रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः नहीं, आपने पीडब्ल्यूडी भी कहा अपने भाषण में।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं एमसीडी से कैसे कहें, मान गये। एमसीडी के थ्रू काम करा रहा हूँ। मैं एमसीडी की बात कर रहा हूँ। आप एक काम करिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपने पीडब्ल्यूडी का नाम लिया। भई अगर सौरभ जी, आप बोल लेंगें, तो ठीक है, फिर बोल लीजिए। सौरभ जी, ऐसे नहीं। मैं बात कर रहा हूँ न।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः झूठा तो ये है, जो भाग जाता है यहाँ से।

माननीय अध्यक्षः आप बात...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः न मुख्यमंत्री है, झूठा है मुख्यमंत्री है जो हाउस में नहीं घुसता, झूठा वो है। मैं झूठा नहीं, झूठा वो है, जो फेस

नहीं कर पा रहा है पब्लिक को। झूठा वो है जो पब्लिक को फेस नहीं करते। मैं झूठा नहीं हूँ। मैं झूठा नहीं हूँ तो मैं... कैसे झूठा कहा मेरे लिए?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी, ऋतुराज जी बैठिए प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः झूठा उसको बोलते हैं, जो पब्लिक से भागता है।

माननीय अध्यक्षः बैठिए प्लीज, ऋतुराज जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम सामने खड़े होके बोलते हैं। हम खड़े होके फिर भी बोलते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए ऋतुराज जी। सौरभ जी, ये ठीक नहीं, चर्चा का स्टैण्डर्ड नहीं है ये। हम चर्चा को खत्म कर रहे हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः कर दो चर्चा, कर तो लो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मनोज जी बैठिये, बाजपेयी जी। ऋतुराज जी प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मुख्यमंत्री है झूठा।

श्री सौरभ भारद्वाजः नरेन्द्र मोदी झूठा नहीं है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः झूठा है मुख्यमंत्री, भागता है विधान सभा से, इसीलिए विधान सभा से भागते हैं इसलिए झूठा है क्योंकि पब्लिक को फेस नहीं कर सकता। हाँ, देखिए...

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः देखिए, कितनी थड़थड़ी मच जाती है। हम सच बोलेंगे, ट्विस्ट करायेंगे।

माननीय अध्यक्षः एक सेंकण्ड। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर ये सार्थक चर्चा करनी है और ये चर्चा बाद में बार बार कहते हैं, एमसीडी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। 15 मिनट वेस्ट कर लिए हमने। अगर वो पीडब्ल्यूडी पे आरोप लगा रहे हैं, लगा लेने दीजिए, तथ्य देंगे अपने आप सामने। मुझे समझ नहीं आया। 15 मिनट वेस्ट हो गये फिर बार बार मेरे पास चैम्बर में आयेंगे जी, एमसीडी ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। हमारा लैटर वहाँ भेज दीजिए। आप लोग समझ नहीं रहे हैं बात को। वो ट्रेप करना चाहते हैं सदन को, हम ट्रेप हो रहे हैं। कमिश्नर आये हुए हैं चर्चा होने दीजिए।

श्री ओमप्रकाश शर्माः ट्रेप कब हो रहा है?

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, प्लीज। चलिए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी का नाम लिया, उन्होंने पीडब्ल्यूडी का नाम लिया है, उन्होंने नाम पीडब्ल्यूडी का लिया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, पीडब्ल्यूडी का नाम लिया। नहीं, ओम प्रकाश जी, पीडब्ल्यूडी का नाम लिया। आप नहीं चर्चा चाहते। करिए, सरदार जी। आप जिसका मर्जी है नाम लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप पीडब्ल्यूडी का लीजिए, जल बोर्ड का लीजिए, जो मर्जी है, लीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः वही लेंगे जो सच होगा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमने माफी नहीं माँगनी।

माननीय अध्यक्षः ओमप्रकाश जी कल ठीक बोल रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः तो हम बात बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः मैं एमसीडी की बात कर रहा हूँ। आज की चर्चा केवल एमसीडी पर है।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अरे! ये कौन सी बात है?

माननीय अध्यक्षः नहीं, ये हो रहा है ये।

श्री ओम प्रकाश शर्माः नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः करिये। मैं उनको बोल रहा हूँ आपको नहीं बोल रहा हूँ।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, न, हमें ट्रेप करने की जरूरत है, न हम ऐसा काम करेंगे।

माननीय अध्यक्षः अब आप तो ये लिए दिये डिस्टर्ब...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम अपनी बात करेंगे।

माननीय अध्यक्षः अब ये डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः भाया, हम अपनी तथ्यों के साथ कर रहे हैं, हमने आपको ये बताया कि मेरा एमसीडी को, मैंने सारे काम दिये। मेरे पैसे एमसीडी के काम कराने के जो मैंने पैसे दिये, वो सारे तो मैं ऑन

द रिकॉर्ड कह रहा हूँ और उल्टा कमिश्नर यहाँ बैठे हैं एमसीडी का, आपको उनको पूछना भी चाहिए कि मेरे सारे के सारे पैसे जो हैं, वो पीडब्ल्यूडी से नहीं रिलीज हो रहे हैं, तो मैंने कोई गलत बात क्या कही है। इसमें कोई गलत बात तो नहीं हैं। या गलत बात है कोई? कोई गलत बात है इसमें? नहीं, आप बतायें तो कोई गलत बात तो नहीं है?

माननीय अध्यक्षः मैं ठीक कर रहा हूँ। मैं ठीक करवा रहा हूँ। ऐसा है, सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अब पीडब्ल्यूडी के पास आ गया है ना।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः यूडी, फिर पीडब्ल्यूडी–यूडी। यूडी कहा, पीडब्ल्यूडी गलत कह गया, यूडी, यूडी। वो मैं डिपार्टमेंट का नाम ले रहा है, पीडब्ल्यूडी बोल दिया।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः तालियाँ बज गयी देखो। मंत्री जी की कमजोरी। मंत्री जी, फिर मैं बोलूँगा, कमजोरी मंत्री की, तालियाँ बजा रहे हैं आप, तालियाँ लौट रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः आपके मुंह से यूडी की बजाय पीडब्ल्यूडी निकल गया, बस उसको खत्म करिए आप। आप आगे बढ़िये सिरसा जी, आइये प्लीज। चलिए, अब शांत हो जाइये प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, पीडब्ल्यूडी शुड बी रेड ऐज यूडी।

माननीय अध्यक्षः यूडी दैटस आल।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः पीडब्ल्यूडी शुड बी रेड ऐज यूडी।

माननीय अध्यक्षः यूडी और डूडा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः डूडा जो फेल हो चुकी है, जो बंद हो चुकी है।

माननीय अध्यक्षः चलिए, हाँ।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः इसको ताला लग गया, ठीक है। जो इस सरकार ने बनाई थी, अब नहीं चल पा रही है, ठीक है। तो डूडा, जो इस सरकार ने बनाई, नहीं चल पा रही है। पहले उसमें हमें तबाह किया, अब यूडी डिपार्टमेंट जो है, वो हमें...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, जनरैल जी, ऐसा नहीं चलेगा, कमाल है!

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है और उसके बाद अगर हम सच बोलते हैं तो ये हमारे द्वाले हो जाते हैं। अरे भाई, हम तो अपने बजट की ही बात कर रहे थे, एक बात। चलो दूसरी बात, मेरा अध्यक्ष जी, इसमें कहना है कि जो हमारा पैसा एमएलए लैड से जाता है, एमसीडी के कामों के लिए, पार्क के लिए, सड़क के लिए कोई भी जाता है, उसकी ये सीमा जरूर तय होनी चाहिए। अगर जेई कहता है कि हम इसकी एनओसी नहीं दे पा रहे हैं, एक्सीईएन कहता है कि मुझे इसकी एनओसी नहीं देनी है, काम की जरूरत है, नहीं होगी, ठीक कह रहा होगा वो। पर कम से कम फिर वो काम यहाँ पर एमसीडी अपनी रिस्पॉन्सिबिल्टि लेके करे, नहीं तो ये सीमा तय की जाये कि क्या वो काम जो एमएलए

कराना चाहता है, एमसीडी की रोड हो, पार्क हो, कुछ भी हो, क्या उसमें अगर वो काम कराना चाहता है और वो जेई या एक्सईन एनओसी नहीं दे रहा है तो फिर इसका मतलब तो है कि उनके पास सफिशिएंट फण्ड हैं, वो अपना काम करके दें, इसकी कोई सीमा तय कराई जाये ताकि हमारे पास जो एनओसी का ये लफड़ा है, दिल्ली जल बोर्ड की कटिंग को लेके लफड़ा है, ये रोज की प्रॉब्लम्स जो हैं, इसकी कोई सॉल्यूशन... एक रेखा तय होनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, दूसरा हमारा जो बजट है, पैसा है हमारा। मैं आपके एक संज्ञान में बात लाना चाहता हूँ जो आप भी पिछले दिनों में से कई जगह आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, उसके कारण दिल्ली के अंदर हम एक अच्छा काम कर पायेंगे, जो एक आजकल वर्टिकल और पिलर्स बनाये जा रहे हैं, ग्रीन पिलर्स जो मैट्रो को चारो तरफ से कवर करते हैं ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। अगर हमारा पैसा एमएलए लैंड फण्ड का हमें अलाऊ कराया जाये और हम वो मैट्रो पिलर्स के ऊपर ग्रिनरी वेल करने के लिए हम वो जो पिलर्स हैं, उसका वर्टिकल गार्डन बनाने के लिए अगर हम अपना पैसा लगा सकें, तो अध्यक्ष जी, हर एमएलए के एरिये में मैट्रो तो निकलती है, तो उससे कम से कम एक बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के ऊपर कंट्रोल होगा। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि अगर इसमें कोई बहुत तुम्हारा पैसा लगना नहीं, चैक–वेक फिक्स मोड भी कर दें कि इससे ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन दिल्ली के अंदर हम वर्टिकल गार्डन्स बना सकें, मैट्रो पिलर्स के साथ अपना पैसा लगा सकें, इसकी अगर आप हमें इजाजत लेंगे तो दिल्ली के लिए एक बहुत भले का काम होगा। और एनडीएमसी ऐसा काम कर रही है गुड़गांव भी कर रहा है, दिल्ली करेगा तो दिल्ली में पोल्यूशन पर भी कंट्रोल होगा, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत धन्यवाद, श्री एस.के. बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गाः अध्यक्ष जी, एमसीडी के कार्य प्रणाली से दिल्ली के सभी विधायक पीड़ित हैं। एमसीडी के अधिकारी किसी दबाब में कार्य कर रहे हैं। एक पार्षद के कहने पर जेई ठीक काम कर रहा होता है तो उसकी ट्रांसफर कर देते हैं। बिना विधायक... कार्यों को नहीं किया जाता, एमएलए लैड फण्ड देने के बाद भी विधायक एमसीडी के जेई के पीछे भागता रहता है काम के लिए। ये चाहते हैं कि दिल्ली के विधायक काम न कर सकें। ये कौन इनको दबाब में कह रहा है कि काम नहीं करें, दिल्ली का विकास रोकने के लिए, ये पब्लिक का पैसा है। एमएलए लैड फण्ड यूज कर लिया हमने, उसके बाद जो पैसा बचता है, वो पैसा वापस देने का नाम नहीं लेते हैं ये लोग। दो–दो साल, ढ़ाई–ढ़ाई साल से पैसे पेंडिंग पड़े हैं। आपके विधान सभा के केस, 21 लाख 97 हजार 2015–16 से पड़ा हुआ है वापस। अभी तक इन्होंने वापस नहीं किया। सभी विधायक पीड़ित हैं। इनसे पूछा जाये कि पैसा अगर रखते हैं अपने पास, उसका ब्याज कौन देगा। ये पब्लिक का पैसा है, जो भी आफिसर इसमें कोताही करता है, उसकी सैलरी से विद इंटरेस्ट काटी जानी चाहिए। इनको पता लगे कि पब्लिक के काम नहीं हो रहे हैं और पैसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ ये पार्षद सभी जगह पर ऐसा काम कर रहे हैं कि विधायक के कामों को रोक रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एमएलए लैड फण्ड वापस, सेविंग का पैसा है, वो वापस हो, उस पर ब्याज ली जाये इनसे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मैं दो तीन बात आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से भी और हमारे तीनों एमसीडी कमिशनर्स यहाँ मौजूद

हैं। कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो एमसीडी काम करती थी, मैं यमुना पार की पहले बात कर रहा हूँ और यमुना पार में पहले से ही विकास की कमी है और फण्ड की भी कमी रही हैं। जैसे मेरे यहाँ एक करावल नगर रोड था। 2006 में हमने एमसीडी से उसको चौड़ा करने का प्रपोजल तैयार कराया और यमुनापार विकास बोर्ड ने उस समय 27 करोड़ रुपया उस रोड को चौड़ा करने के लिए दिया। उसमें से तीन–चार साल लगने के बाद 2011 या 12 के अन्दर वो रोड चौड़ा होना शुरू हुआ। उस समय तक आधा पैसा उस पर खर्च हुआ। उसके आधे पैसे का ये मालूम नहीं पड़ा आज तक कि वो पैसा गया कहाँ। उसमें एक करोड़ रुपया लैड एण्ड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में था जो मुआवजे के लिए आगे के लिए दिया गया था। वो पैसा एमसीडी को वापसी आ गया, जो वहाँ जमा किया था, 27 करोड़ में से। तो सर, मैं इसमें आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो एमसीडी से हम काम कराते हैं। एमएलए लैड फण्ड से या यमुनापार विकास बोर्ड की बात न करूं तो इसमें एक समय सीमा तय कर दी जाए कि यदि आज बजट दिये हैं, हमने किसी भी विधायक से कि हमारा ये रोड बनाना है, ये पार्क में झूले लगाने हैं या पार्क को डेवलप करना है तो उसमें दो महीने, तीन महीने, चार महीने की कोई डेट तय कर दी जाए और यदि उसके बाद तय समय सीमा के अन्दर काम शुरू नहीं होता है तो फण्ड वापसी वहाँ से हो और फिर जिस एजेन्सी से आप यहाँ एक ऐसा प्रस्ताव रखें, जो भी एजेन्सी और हैं दिल्ली में पीडब्ल्यूडी है, फ्लड डिपार्टमेण्ट है, डीएसआईआईडीसी और बहुत सारी एजेन्सी हैं, उनसे किसी से भी काम करने के लिए आजादी हमको मिलनी चाहिए। न कि एक जगह हम बन्दिश में रहें क्योंकि बार–बार यही आरोप आ रहा है यहाँ कि हम काम की बात कम, आरोप–प्रत्यारोप यहाँ ज्यादा हो रहे हैं। ईस्ट एमसीडी में पैसा नहीं है और एसडीएमसी की बात करते हैं, साउथ दिल्ली की, तो

वहाँ कहते हैं, जब एमएलए ने फण्ड दिया तो उसका काम यह कहके रोक दिया जाता है कि काउन्सलर अपने बजट से बनवा रहा है। तो यदि काउन्सलर के बजट से बनवाना तो बहुत अच्छी बात है और विधायक का फण्ड वहाँ नहीं लग पा रहा है तो उसको किसी दूसरी एजेन्सी में तय. कमिश्नर साहब यहाँ बैठें हुए हैं, इसमें एक रेजल्यूशन आप यहाँ से पास करें कि तीन महीने, चार महीने का टाइम बाउन्ड कर दें। उसके अन्दर काम नहीं होता है तो दूसरी एजेन्सी से हम काम करा लिया जाए।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि साठ फीट से ऊपर जो रोड है, जो एमसीडी के पास पहले होते थे, दिल्ली सरकार के गाइडलाइन्स के अनुसार 60 फीट से ऊपर का कोई भी रोड है, उसकी मैंन्टेनेंस का काम पीडब्लूडी करेगी। मेरे यहाँ रोड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 80 फीट का रोड है... 82 फीट का। उसमें मैं पीडब्लूडी मिनिस्टर को तीन बार लैटर लिख चुका हूँ कि ये रोड आप एमसीडी से पीडब्लूडी को आप दिला दें, ताकि हमारे रोड बन जाए। तो साहब ने एक दिन मुझसे कहा कि भई, हम एमसीडी का कोई रोड नहीं लेंगे क्योंकि वो हमें पूरी उसकी वो नहीं देते। मुझे आप डिप्टी सीएम से कहलवा दो या सीएम से कहलवा दो। मैं रिक्वेस्ट करने गया डिप्टी सीएम साहब के पास की जी कि मेरे रोड की हालत बहुत खराब है। इसको आप साहब से बोल दो, जैन साहब से, वो हमारा रोड पीडब्लूडी को दे देंगे हमारा रोड बन जाएगा। आज तक वो हमारा रोड पीडब्लूडी को नहीं दिलवाया गया। मैं बहुत दुःख की बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ आरोप–प्रत्यारोप ज्यादा है। पार्टीबाजी की बात ज्यादा है। मैं दिल्ली का हित अगर सरकार चाहती है तो हमें एलजी साहब के साथ भी और जितने भी हमारी हाई अथॉर्टीज एजेन्सी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके साथ हमें तालमेल बना के, क्योंकि अब चुनाव में केवल दो साल बचे हैं और दो साल में भी अगले साल

पाँच–चार महीने चुनाव में निकल जाएंगे पार्लियामेण्ट में। वो तालमेल बगैर दिल्ली की जनता को हम कैसे सुविधा दे सकें, कैसे अच्छे काम कर सकें, इस पर हमें एक तालमेल करके और जो भी एजेन्सी हैं, उनके साथ तालमेल बनाके अच्छे से दिल्ली का विकास करें मैं इतना ही कहूंगा, धन्यवाद, जयहिन्द।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

माननीय लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने कल भी प्रस्ताव रखा था, मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री हूँ। अक्सर मेरे पास सारे एमएलए आते हैं कि जी, अनऑथराइज कब्जा हो गया, कब्जा हटवा दो। प्रधान जी, मेरे पास आये थे। मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैंने इनसे एक ही बात कही थी कि सड़क लेने को मैं तैयार हूँ अगर वो सड़क दे रहे हो तो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सड़क उन्हीं की रहेगी और बनाऊँगा मैं। गालियाँ मुझे मिलेगी और क्रेडिट वो लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों काम नहीं चलेंगे कि अगर एमसीडी सड़क देगी। पहले जो आ गयी है, आ गयी है। नई सड़क मैं तभी लूँगा कि अगर उस सड़क के ऊपर एन्क्रोचमेण्ट हटाने की पॉवर भी मेरी होगी। उस सड़क की रिपेयरिंग की पॉवर और ओनरशिप भी मेरी होगी। वरना मैं लेने को तैयार नहीं हूँ।

माननीय अध्यक्षः नहीं जगदीश जी, अब ये बात ठीक है। इसमें जायज बात... एमसीडी हैण्डओवर करे, एन्क्रोचमेण्ट हटाये। चलिए, हो गया। तो वो भी नार्म्स की कह रहे हैं। उस सड़क को...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सैकण्ड, मेरी बात सुनिए, एक सैकण्ड जगदीश प्रधान जी, बैठिए। विजेन्द्र जी, कोई भी एजेन्सी। एक सैकण्ड, जगदीश जी,

ऐसे नहीं प्लीज, आप समझदार हैं। कोई भी एजेन्सी... मैं पीडब्ल्यूडी की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी चीज को टेकओवर अगर करेगी उसकी डेफिसिएंसी पहले काउन्ट होगी। उस डेफिसिएंसी को पूरा करने के लिए कितना पैसा चाहिए। चलिए, वो पीडब्ल्यूडी दे देगी। जो भी डेफिसिएंसी है, उस रोड पर कोई एन्क्रोचमेण्ट है या उस बिल्डिंग में कोई एन्क्रोचमेण्ट है, उस लैण्ड में कोई एजेन्सी ले रही है, कोई एन्क्रोचमेण्ट है तो उस चीज को टोटल को खाली करके देना उस डिपार्टमेण्ट का काम है, जो उसको हैण्डओवर कर रही है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लोग परेशान हो रहे हैं। 60 फीट एण्ड अबव की रोड हैं।

माननीय अध्यक्षः हाँ तो, यही तो कह रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः तो अगर दिल्ली सरकार से छूट गयी लेते वक्त उस समय।

माननीय अध्यक्षः एमसीडी हैण्डओवर करेगी तभी तो टेकओवर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उसको एन्क्रोचमेण्ट हटा दे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, तो वो तो जो भी स्टेटस था, पहले भी 60 फीट एण्ड अबव रोड का। पीडब्ल्यूडी ने टेक ओवर किए हैं। और दिल्ली सरकार का जो आदेश है, वो निकाल के पढ़ लो आप।

माननीय अध्यक्षः देखिए, उन्होंने बिल्कुल अगर कानूनी तौर... हम अगर आरोप–प्रत्यारोप करें तो ठीक नहीं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन एमसीडी उसके एन्क्रोचमेण्ट हटाने की ड्यूटी जिन एजेन्सीज की है वो हटाएंगे। नहीं विजेन्द्र जी प्लीज। बैठिए। जो कानूनी बात है, उसको पूरा करिए। श्री राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष जी, आपने आज एमसीडी के मुद्दे पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, हम लोग एमएलए फण्ड अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगाते हैं और हमारे यहाँ स्थिति ऐसी हो गयी है कि हमने एक वार्ड के अन्दर तो इतनी बार लैटर लिखके दिये, उस काम कराने के लिए, कोई काम नहीं हुआ। मैंने पुनीत गोयल जी को 14/10/2016 को जिम लगाने के लिए दिया था, उसका कोई जवाब नहीं आया, कोई एस्टीमेट नहीं आया। मैंने चीफ इन्जीनियर को अपने यहाँ पर पार्कों में जिम और झूले लगाने के लिए 30/6/2017 को पत्र दिया, आज तक उसका पता नहीं है जी। आज तक उसका कुछ भी नहीं आया। मैंने कई बार इनके मिस्टर बैनर्जी को फोन करते रहे कि हमारा एस्टीमेट? ''वो जी, हमारा अभी फाइनल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ'' और जिम लगातार ये अपने लगाते रहे और केवल एमएलए फण्ड इनको यूज नहीं करना था। एक मेरे यहाँ सी और डी ब्लॉक हैं, उसके लिए मैंने चीफ इन्जीनियर साहब के पास एक लैटर भेजा क्योंकि पहले मैंने एक्सईएन को दिया था। उसने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने चीफ इन्जीनियर साहब को लैटर दिया, ये रिसीविंग हैं मेरे पास 7/7/2017 की कि इनकी दीवारें टूटी हुई हैं इस कालोनी की, इसको बनाया जाए। इसकी सड़कों की हालत खराब है, इसको बनाया जाए। मैं एमएलए फण्ड देने को तैयार हूँ। उसके बाद कई बार मैंने इनके जेई... वहाँ पर जेई थे, उनको मैंने कई बार फोन किया। वो फोन नहीं उठाते थे। एस्टीमेट आज तक मुझे नहीं मिले। मैं अभी भी उनको नये जो... सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि बहुत जल्दी–जल्दी जेई बदल दिए जाते है। वो जेई से कान्टेक्ट करो, वो एस्टीमेट दे रहा हूँ दे रहा हूँ पता चलता है नया जेई आ गया। फिर उसके बाद फिर नया जेई आ गया पता नही क्या कारण है कि ये काम ही नही करना चाहते। तो ये लैटर देने के बाद मैंने एक 4/8/2017 को डेन्स कारपेटिंग कराने के

लिए दिया कि सी–2... मेरे यहाँ एक बहुत बड़ी कालोनी है जिसकी बहुत बुरी हालत है, सड़कों की। मेरे जनकपुरी में डेन्स हर जगह होनी है लेकिन न तो डेन्स करने को तैयार हैं और न ही एस्टीमेट देने को तैयार हैं। मैंने कहा कि मेरे पास फण्ड पड़ा है। मै आपको फण्ड दे देता हूँ। आप इसकी डेन्स कारपेटिंग करा दीजिए। ये लैटर 4/8/2017 को मैंने दिया, फिर प्रपोजल मैंने इनको फिर दिया कि सी–2 में स्वर्ण चौधरी स्मृति वाटिका है, इसके अन्दर पेपर ब्लॉक लगने हैं। वाकिंग ट्रैक बहुत बुरी हालत में है। या तो आप लगा दीजिए या फिर हमसे पैसा ले के लगवा लीजिए। पूरी आरडब्ल्यूए बार–बार मेरे को लैटर देती है। उसका आज तक एस्टीमेट नहीं मिला जी। मैं कई बार उसको फोन कर चुका हूँ जेई को भी। वो कहता है, ''मैंने बना लिया है, मैं दे जाऊँगा, मैं दे जाऊँगा।'' एक–एक साल बिता दिया इन्होंने, कुछ नहीं किया। फिर मैंने इनको इल्लीगल... पुनीत गोयल जी को 14/10/2016 को इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन जो हो रहा था, उसके खिलाफ मैंने इनको एक लैटर दिया। वहाँ पर क्या था कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो हरिजन बस्ती है, उसमें लोगों को छोटे–छोटे प्लाट दिये गये थे। किसी बिल्डर ने चार, पाँच, दस प्लाट खरीद के बिल्डिंग बनाई गई। बेसमेण्ट बनाया जो एलाउड नहीं था। बकायदा बेसमेण्ट बना। पूरी बिल्डिंग बनी। आरडब्ल्यूए ने मुझे लैटर दिया कि एन्क्रोच कर गया, ये एरिया एन्क्रोच कर दिया, इसने गली एन्क्रोच कर दी। मैनें लिखके दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अध्यक्ष जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लिख के मैंने एलजी साहब को भी भेजा। एलजी साहब के यहाँ से भी इनके पास इंक्वायरी आई। इन्होंने कुछ नहीं किया। दो बार वो बिल्डिंग सील हुई, फिर खुल गई और आज बिल्डिंग दनादन चल रही है। मैंने एलजी साहब को भी लिखकर दिया

कि यह बिल्डिंग बार–बार सील हुई है, उसके बाद पैसे ले लेते हैं, फिर खुल जाती है। फिर सील कर जाते हैं, फिर करते हैं। एलजी साहब के ऑफिस में मैंने उनकी जो एमसीडी देख रही है स्वाति जी, उनको मैंने कई बार फोन किया कि मेरे यहाँ पर यह आरडब्ल्यूए मुझे रोज तंग कर रही है, यह इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, केवल भ्रष्टाचार होता रहा। बार–बार लैटर के ऊपर ये जाकर पैसे ले आते रहे, यह होता रहा वहाँ से।

अध्यक्ष जी, मैं आपको और दिखाता हूँ मैंने इनसे इन्फॉर्मेशन माँगी कि मेरे क्षेत्र में कितने आपने सील किए हैं। इन्फॉर्मेशन मैंने अपने लैटर हैड पर माँगी, जब कि मैंने क्वेश्चन जो हमने विधान सभा में लगाए थे, उसमें भी मैंने वही इन्फॉर्मेशन मांगी थी। न तो इन्फॉर्मेशन मेरे लैटर पर दी, न ही क्वेश्चन जो मैंने लगाए उसमें दी गई। उसका मैंने आपको लैटर दिया हुआ है, क्वेश्चन कमेटी में लगाया हुआ है। वो अभी तक मेरा लगा नहीं है। इन्होंने मेरे को कोई जानकारी नहीं दी। मेरे क्षेत्र के अंदर वार्डों में बूथ लगे हुए हैं हैंडीकेप्ड बूथ। दो वार्डों की मेरे को जानकारी दी कि एक–एक बूथ है इसमें। दो वार्डों की जानकारी इसलिए नहीं दी कि वहाँ पर इन्होंने अनाप–शनाप लगा रखे हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंटर भरा पड़ा है बूथों से। जिस बूथ से 20 हजार रुपये मंथली एमसीडी वसूलती है और इल्लीगल लगे हुए हैं सारे रोड के किनारे, पीडब्ल्यूडी की रोड के ऊपर। पीडब्ल्यूडी वालों को कई बार बोला हटाने के लिए, बोले, हटाने नहीं देते। हटाने का काम एमसीडी का। जो जैन साहब बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि सारा घेर रखा है, पूरा एरिया।

अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर इन्होंने साइकिल पथ पर ढलाव बनाए हैं जो मैंने परसो भी बात रखी थी। उनको बनाने के लिए

इन्होंने जो बात करी थी कि हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, वो चार–चार गुने बड़े बना दिए। साइकिल ट्रैक पूरा गायब कर दिया जी। साइकिल ट्रैक बनाने लायक जगह ही नहीं बची उसके ऊपर। जिस ठेकेदार ने ठेका लिया हुआ है साइकिल ट्रैक बनाने का, वो बेचारा रोता है कि मैं बनाऊँ कहाँ पर! अब तो ये कूड़े के घर बना दिए बीच में। इसके अलावा आज मैं जब वहाँ से आ रहा था तो मैंने देखा कि पूरे जो साइकिल ट्रैक की जगह बाकी बची हुई है खाली, उसके ऊपर कूड़े के ढ़ेर लगे हुए हैं। पता नहीं, कहाँ से लाकर कूड़ा डाल दिया है वहाँ पर। जो ढलाव बनाए हैं, उसके अंदर कूड़ा नजर नहीं आता, वो सारा बाहर ही नजर आता है। ढलाव बनाने का फायदा ही क्या, इतने बड़े–बड़े ढलाव बनाने के बावजूद भी कूड़ा बाहर है। उसके बाद स्थिति यह है कि इनकी जेसीबी लगती है कूड़ा उठाने के लिए। उन्होंने पंखा रोड नाले की दीवार को तोड़कर अंदर तक पहुँचा दिया है और स्थिति यह हो गई है कि अब कूड़े को धीरे–धीरे करते–करते उन्होंने नाले के अंदर डालना शुरू कर दिया है कूड़े को। पंखा रोड इतनी सुंदर रोड बनी हुई थी, आज उस रोड की दीवारों को जगह–जगह से तोड़ दिया है एमसीडी ने और रोड को तोड़ने के बाद कूड़ा भर दिया है। अब लोगों ने उस कूड़े के ऊपर ले जाकर अपनी पार्किंग शुरू कर दी है, यह स्थिति हो गई है वहाँ।

वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पशु। इतने जानवर हैं वहाँ पर, कम से कम... आप दोपहर में चले जाओ 100–150 जानवर आपको वहाँ खड़े नजर आएंगे। पुनीत जी से मैं कहूँगा एक बार जाकर देखकर आएं। मैंने कई बार कोशिश की है डीसी को ले जाने की, वो हमारे साथ चलने को कभी तैयार नहीं होती। उनको पता है, ये वहाँ ले जाकर खड़े कर देंगे, जहाँ इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है। वहाँ पर 100–150 पशु पंखा रोड के

ऊपर नजर आएंगे आपको और उससे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। कई बार बोला गया, कभी नहीं हटाए गए। अब तो जो पंखा रोड ड्रेन है हमारी, उस ड्रेन के अंदर सुअर पालन शुरू हो चुका है। उसके अंदर लोगों ने सुअर पालने शुरू कर दिए हैं। अध्यक्ष जी, यह स्थिति है। मैं सारे डॉक्युमेंट लेकर आया हूँ जो–जो मैंने इनको लैटर दिए हैं। बहुत सारे लैटर दिए हुए हैं, कुछ लैटर तो मुझे मिले भी नहीं।

अध्यक्ष जी, कहानी है अब इनके वेटेनरी डिपार्टमेंट की। मैंने उनसे एक बार पूछा कि मेरे यहाँ पर कितनी मीट की दुकानें हैं, कितनी मच्छी वालों को आपने लाइसेंस दिए हुए हैं? लाइसेंस तो गिने–चुने हैं, उंगली पर गिन जाते हैं और दुकानें ऐसे लगी हुई हैं भयंकर तरीके से। मैंने इनसे पूछा, ''इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं?'' ''जी, हम हटा रहे हैं, हम यह कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं।'' कुछ नहीं कर रहे।

अभी चल रहा है गन्ने का सीजन। गन्ने की जूस की दुकानें लगी हुई हैं। खूब लग गई रोड के ऊपर। अनाप–शनाप जगह पर खड़ी की हुई है और डायरेक्ट कनेक्शन लगा कर चल रही है। कंप्लेंट करो, कुछ नहीं होता, यह तो पार्षद की लगी हुई है। वो पार्षद की लगी हुई है, वो उसके मंडल अध्यक्ष है, उसने लगा रखी है। इस तरीके से पूरी रोड के ऊपर जगह–जगह... मिलाप नगर वार्ड में कम से कम 22–23 तो मैं अपनी आँखों से देखकर आया हूँ लगी हुई हैं, रोड के ऊपर और गैर कानूनी लगी हुई हैं। किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है, यह स्थिति है वहाँ पर।

हैंडीकेप्ड बूथ की मेरे को जानकारी नहीं दे पाए। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर काम करने होते हैं; सीवर की लाइन डालना, पानी की लाइन डालना, उसकी परमिशन अब इन्होंने ऑनलाइन तो कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी यह देने को तैयार नहीं होते। वहाँ काम

करने जाओ तो रोक देते हैं। कई जगह पर तो हमने जहाँ पर सीवर की लाइन डालनी थी, वहाँ इन्होंने सड़कें बना दी हैं। मना करने के बावजूद बनाई। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि हमें पार्कों के अंदर काम करने के लिए एनओसी दें क्योंकि इनके कंस्ट्रक्शन का बहुत बुरा हाल है। ये सड़कें बना रहे हैं; नीचे कच्ची रोड़ी डालते हैं ऊपर एम–20 डालते हैं। एम–20 थोड़ी सी बरसात पड़ते ही गायब हो जाती है। बहुत सारी सडकें इनकी ऐसी हालत में हैं कि एम–20 नजर ही नहीं आती कि कहाँ गई। कच्ची रोड़ी डाली, उसके ऊपर एम–20 डाली, काम खत्म। क्योंकि इनका साफ सोचना है कि दो साल, तीन साल रोड चलनी चाहिए। हमने अभी डीएसआईआईडीसी से सड़कें बनाईं, हम गारंटी ठोक कर कहते हैं कि पन्द्रह साल से पहले सड़कें नहीं टूटेंगी क्योंकि एम–30 से बनी है। मैंने चीफ इंजीनियर से मीटिंग की। मैंने कहा, ''सर, ऐसा है कि मैं एमएलए फण्ड देने को तैयार हूँ, मेरी रोडस बने लेकिन एम–10 नीचे डालेंगे और एम 30 ऊपर डालेंगे।'' उन्होंने एस्टिमेट देने से मना कर दिया कि नहीं जी, हम यह नहीं करेंगे। हमारा तो यही प्रोसीजर है। हम तो घटिया माल बनाएंगे देश की जनता का पैसा लूट कर खाएंगे। वो कर रहे हैं ये। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि हमें एनओसी दे दें, हम किसी भी एजेंसी से काम करा सकें। पुनीत जी हँस रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ पुनीत जी, आपका डिपार्टमेंट सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है और आप उसके मुखिया हैं इसलिए आपके ऊपर भी आती है यह...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप इधर बात करें। अधिकारी का नाम लेकर न करें प्लीज।

श्री राजेश ऋषिः मेरा यही कहना है आपसे कि हमें एनओसी दिला दी जाए..

माननीय अध्यक्षः आपने जो बात करनी है, मुझसे करें।

श्री राजेश ऋषिः हम काम करें, उसके अंदर काम करा सकें, किसी और एजेंसी से करा सकें। हमारे पार्कों की स्थिति बहुत खराब है, वहाँ पर मैन्टेनेंस नाम की चीज नहीं है। माली आते नहीं। आज सुबह मेरे पास कुछ आरडब्ल्यूए वाले आए हुए थे कि हमारे यहाँ झाड़ू लगाने वाले नहीं आते। वार्ड–120 है, जो पुराना हमारा 120 था, अब 17–एस है, उसके अंदर गलियों में झाड़ू लगाने आते नहीं। स्थिति यह है कि 2019 में मेरे पास 270 आदमियों की लिस्ट थी कि 270 आदमी इन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं लेकिन जब ढूँढो तो कोई नहीं मिलता है।

मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि इनसे कहें कि यह भ्रष्टाचार कम करके अपने एरिया में काम कराना शुरू करें और एनओसी दें, हमारे यहाँ पार्कों में काम कराने के लिए। बहुत–बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का समय दिया।

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविंदः अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। एक बहुत गम्भीर मसला है कि. अध्यक्ष महोदय, मैं अनऑथोराइज्ड कालोनी का रिप्रजेंटेटिव हूँ। अनअथोराइज्ड कालोनी के अंदर एमसीडी का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि सेनिटेशन से लेकर के जितने भी एमएलए लैड तक का जो काम हम लोग देते हैं, उसमें जो इनका रिलक्टेंट बिहेवियर है, उसकी वजह से बहुत समस्याएं आती हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि 2015 में जब यह

सरकार चुनकर के आई, मेरे क्षेत्र में जहाँ पर 5 लाख लोग रहते हैं, अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर आज तक एमसीडी एक कूड़ाघर नहीं बना पाई। जहाँ पर कि जो सफाई कर्मचारी हैं, वो कूड़ा इकट्ठा करके कूड़ा फेंक सके और वहाँ से जो गाड़ी है वो ले जा सकें खत्ते की तरफ। जिसके चलते हमारे क्षेत्र के अंदर जितने भी खाली प्लॉट हैं, वो सब के सब कूड़ाघर, खत्ता बना हुआ है। इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि जहाँ इंसान नहीं रह सकते हैं। जब मैं एमएलए बना तो लोगों के डिमांड के अनुसार तीन कूड़ाघर बनाने के लिए एमएलए फण्ड से 12/10/2015 तारीख के साथ है यह, 12/10/2015 को इनको चैक मिला था एमएलए फण्ड से कूड़ाघर बनाने के लिए, जिसका एमाउंट था अध्यक्ष महोदय, 29 लाख 8 हजार रुपया और ये लोग 75 परसेंट पैसा लेते हैं, बाकी सब एजेंसी 50 परसेंट लेती है काम करने से पहले। यह एमसीडी वाले सब 75 परसेंट लेते हैं और 75 परसेंट पैसा 22 लाख 35 हजार रुपया इनको पेमेंट भी मिल गया चैक के थ्रू। आप एक चीजे देखिए, कि 12/10/2015 को मिला था और आज तारीख है लगभग तीन साल से, ढ़ाई साल से ऊपर हो गया और इन्होंने काम क्या किया। ये देखिए, ये फोटो लेकर आया हूँ मैं, सारे सदन को दिखाने के लिए लाया हूँ सब को दिखाने के लिए लाया हूँ। यह ढ़ाई पिलर भी नहीं है। ढ़ाई साल में इन्होंने ढ़ाई पिलर खड़ा किया है। तीन कूड़ाघर ढ़ाई साल में नहीं बना पाए अध्यक्ष महोदय।

इसके साथ–साथ हमने हॉर्टिकल्चर का भी कुछ काम दिया था। वो भी नहीं किया है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महादेय, आपके माध्यम से कि जहाँ पर पाँच लाख लोग रहते हैं; कूड़ाघर बनाने की जिम्मेदारी एमसीडी की है लेकिन आज तक एमसीडी ने एक कूड़ाघर नहीं बनाया। जब एमएलए फण्ड से हमने पैसा दिया तो ढ़ाई साल के अंदर ढ़ाई पिलर

खड़ा किया इन्होंने। फ्लड एण्ड इरिगेशन की जमीन दी, जो नाले की जमीन थी। फ्लड एण्ड इरिगेशन ने तुरंत एनओसी दिया ताकि जनहित का यह कार्य तुरंत हो सके लेकिन ढ़ाई साल के अंदर इन्होंने काम नहीं किया और ऊपर से वो पैसा भी वापस नहीं दे रहे ताकि हम किसी और एजेंसी से बनवा लें। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर पाँच लाख की आबादी रहती है, गरीब लोग रहते हैं जब वो बीस गज का छोटा सा मकान बनाने का प्रयास करते हैं तो सूंघते हुए चौबीस घंटे के अंदर पहुँच जाते हैं। लेकिन ढ़ाई साल के अंदर पैसा देने के बावजूद इन्होंने तीन साल के अंदर तीन कूड़ाघर नहीं बनाकर दिया। छोटे–छोटे... जब लोग घर में जुराब बनाते हैं, सिलाई मशीन लगाते हैं तो वहाँ पर ये एमसीडी वाले सूंघते हुए पहुँच जाते हैं पैसा मांगने के लिए, गरीबों के परेशान करने के लिए लेकिन ये साफ सफाई की जिम्मेदारी जो इनकी है, वो साफ सफाई नहीं करते हैं। 800 सफाई कर्मचारी हमारे क्षेत्र में बिल्कुल पेपर पर हैं लेकिन आते 200 भी नहीं हैं। आप एक बार क्षेत्र में जाकर के देखेंगे अध्यक्ष महोदय, हर प्लॉट कूड़ाघर बना हुआ है, हर गली की नालियाँ बह रही हैं। वहाँ से सिल्ट नहीं निकलता है। साफ सफाई नहीं होती है लेकिन कोई गरीब अगर 20 गज का मकान बनाता है तो वहाँ 24 घंटे के अंदर पैसा लेने के लिए पहुँच जाते हैं। कोई अगर जुराब बनाता है कोई छोटी सी मशीन लगाकर घर में अपना काम करता है, अपना पेट पालने का प्रयास करता है तो वहाँ ये पहुँच जाते हैं। ये इनका एटीट्यूड है। तो हम ये कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि भइया, ये पैसा अगर तुम्हें कूड़ाघर नहीं बनाना है जो कि काम तुम्हारा है लेकिन पैसा एमएलए फण्ड से दिया है तो कम से कम ये पैसा वापिस कर दो ताकि किसी और डिपार्टमेंट्स से हम कूड़ाघर बनवाएं ताकि कोई वहाँ पर जनता के हित के लिए वो काम हो सके। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः ये पेपर सारे ऑन रिकॉर्ड रख दीजिए, सदन पटल पर रखवा दीजिए। महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

दर्द सभी का एक है कि एमसीडी के द्वारा आज जो बुरी हालत हो रही है, लोगों की... कुछ मैं जगदीश प्रधान जी का भी दर्द को सुन रहा था, सिरसा साहब के भी और सभी को देख भी रहे हैं हम कि कहीं पर काम नहीं हो रहा है और यहाँ तो काम पैसे देने के बावजूद नहीं हो रहा। एमसीडी में तो कह देते हैं भई, हमारे पास फण्ड नहीं है इसलिए हम काम नहीं कर सकते। अरे भई, ये पैसा दे रखा है तो ये तो काम कर लो कम से कम। मैंने जनवरी, 2017 के अंदर एक पार्क बनवाने के लिए फण्ड दिया। उसकी चारदीवारी और उसके अंदर जिम लगाने के लिए, वो काम नहीं हुआ आज तक और 2016 नवंबर के अंदर फण्ड दिया तकरीबन 50 लाख रुपये का, पार्कों के अंदर जिम लगाने के लिए, वो काम आज तक नहीं हुआ। दो दो बार एमएलए लैड से फण्ड देने के बावजूद काम नहीं होता। दर्द बहुत आता है और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर आज के दिन का आपने सदन बढ़ाकर, इस पर चर्चा करने का जो सभी विधायकों को मौका दिया कि कितने आप गंभीर हैं इस मसले को लेकर और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि शायद ये काम हो जाए। ऋतुराज भाई ने जैसे अपना दर्द बयान किया कि 20 गज का, 25 गज का या 50 गज का कभी भी कोई गरीब आदमी मकान बनाता है तो वहाँ पर पैसे लेने के लिए एक मिनट में आ जाते हैं। मैं आपके माध्यम से आज ये जानना चाहूँगा कि जब कच्ची कालोनियों के अंदर अनऑथोराइज्ड कालोनियों के अंदर एमसीडी कोई अपना फण्ड नहीं लगा सकती लेकिन

वो पैसे कैसे इकट्ठा कर सकती है, ये जानने का भी हक हम लोगों को है आज। नेता विपक्ष से भी ये सवाल करना चाहूँगा कि क्योंकि वो काफी समय तक मेयर भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं कि जब जिस काम के लिए आप काम करने के लिए ऑथोराइज्ड नहीं हैं; वहाँ पर नाली आप नहीं बना सकते, गली आप नहीं बना सकते। पैसे इकट्ठे करने के लिए आप लोग. ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और जहाँ पर 20–25 गज के मकान को पैसे लेके बनवा देते हैं, नहीं देता तो उसको तोड़ देते हैं। ये एलजी साहब को अनिल बैजल साहब को भी और माननीय जो हमारे पुराने एलजी साहब थे, नजीब जंग साहब ये 4–4, 5–5 लैटर ये लिखे हुए हैं कि यहाँ पर एन्क्रोचमेंट हो रही है सरकारी जमीनों के ऊपर उसको आज तक नहीं रुकवाया गया। सेक्टर–26 का मैंने लिखकर दिया, सेक्टर–11 के लिए मैंने लिखकर दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बन जाती हैं बिना नक्शे के लेकिन 20 गज का, 30 गज का, 25 गज का, 50 गज का यदि कोई मकान बनाता है, उसके साथ इतना अन्याय होता है, इतना अन्याय होता है और उसकी बिल्डिंग को एक मिनट में गिरा देते हैं जो अपने जीवन भर की पूंजी मजदूरी करके पैसों को इकट्ठा करके जब वो लगाता है लेकिन जहाँ पर जोड़ों के मकान बन रहे हैं, विजेन्द्र गुप्ता जी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत से इनकी निगाह के अंदर भी हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, उनके ऊपर तो कभी आज तक खरोच नहीं आई और 20 गज के, 25 गज के, 30 गज के मकानों को एक मिनट में धराशायी कर दिया जाता है। मैं दो लाइनों में कहना चाहूँगा, 'न करो कुछ काम ऐसा, न करो कुछ काम ऐसा दिन के उजाले में, न सो सको चैन से रात के अंधेरे में और न करो कुछ काम ऐसा रात के अंधेरे में कि मुँह छिपाते फिरो दिन के उजाले में, मुंह छिपाते फिरो दिन के उजाले में' तो अध्यक्ष जी, यदि आपके माध्यम से कहीं पर किसी को सुध आ जाए और ये सब ये रिमाइंडर लैटर भी, ये मेल भी

कमिश्नर साहब को भी लिखी हुई हैं, एलजी साहब को भी लिखी हुई हैं, मैं आपके सदन पटल पर भेज रहा हूँ, कार्रवाई हो सके तो इसको कार्रवाई को करवाने के लिए अंजाम पूरा दें, मेहरबानी, शुक्रिया, जयहिन्द, जयभारत।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, तीन साल से ऊपर हो चुके हैं विधायक बने हुए। पहले साल में ही एक उप–चुनाव आ गया। उसके बाद में एमसीडी के चुनाव आ गये। फिर डिस्क्वालिफाई कर दिया गया तीन महीने के लिए। दो महीने उसमें खराब हो गये। पहले ही इतना टाइम खराब होता जा रहा है और मुझे बड़ा अचंभा हो रहा था... क्योंकि अभी सिरसा साहब हैं नहीं, वो कह रहे थे कि बहुत पैसे थे मगर लगे नहीं। उन्हें विधायक बने हुए अभी एक साल हुआ है तकरीबन। उनके कह रहे हैं बहुत सारे पैसे अटके हुए हैं तो हमारे तो तीन साल हो गये हैं। तीन साल पहले जो एमसीडी को पैसे दिये, गलियाँ बनाने के अभी पांच दिन पहले इसी सत्र में किसी ने मुझे मैसेज भेजा कि जी, अभी एक गली पूरी हो गई है। तीन तीन साल फिर पैसे को अटकाये वहाँ पर खड़े रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। पाँच–पाँच साल से एमसीडी की पेमैंट नहीं हुई है जो एमसीडी के ठेकेदार एमसीडी का काम करते थे लेकिन अगर विधायक फण्ड के काम लगे होते हैं तो सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ठेकेदार बहुत जल्दी इंटरेस्ट दिखाते हैं उसके अंदर कि इसमें तो बहुत जल्दी पेमैंट हो जाएगी और कमीशन–वमीशन की भी सरदर्दी नहीं है तो वो फटाफट उसको लगाते हैं लेकिन उसके बावजूद न तो इनसे एस्टिमेट बनते। एस्टिमेट बन जाएं तो वो पहले डूडा में या अब यूडी के अंदर नहीं पहुँचते। वहाँ पहुँच जाएं तो

रिलीज कराने के लिए कौन आएगा? कहते हैं, ''जी, आप जाओ।'' मतलब विधायक जाए वहाँ पर, वहाँ जाकर कहे, ''जी, हमारे पैसे रिलीज कर दो।'' वहाँ से हो जाए तो फिर वर्कऑर्डर कराने के लिए एक्सईएन के पास में जाओ लेकिन हमारा काम है क्या! यही काम है कि हम पहले एक्सईएन को रिक्वेस्ट करें फिर जेई को रिक्वेस्ट करें फिर डूडा में रिक्वेस्ट करें फिर ठेकेदार को भी एक फोन करें कि भइया, वर्कऑर्डर हो गया था, तुमको इसका टेंडर मिला है कि तुम इस गली को पहले बना दो। गली बनाते रहेंगे... तोड़कर छोड़ देते हैं छह महीने के लिए फिर इसको रिक्वेस्ट करते रहो और भगवान न करे बीच में कोई चुनाव आ गया तो वो बननी नहीं है। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, उसके बाद वो बननी नहीं है। जो अभी राजेश भाई एम–30 के बारे में बात कर रहे थे, उसमें मैंने भी बात करी थी। काम करना तो दूर, मैं कुछ गलियाँ फ्लड से बनवा रहा था, उप–चुनाव बीच में आ गया, उसको भी रुकवा दिया गया कि नहीं, एमसीडी की एनओसी दिखाओ। चार गलियाँ बन गई थी, उप–चुनाव जब तक घोषणा नहीं हुई थी, घोषणा होते ही उस काम को रुकवा दिया गया। वजीरपुर गाँव की वो जगह थी और वो गलियाँ रोक दी गई। फ्लड ने नहीं बनाई। उसमें से कुछ...

माननीय अध्यक्षः नहीं, उसमें वर्कऑर्डर पहले हो गया था?

श्री राजेश गुप्ताः वर्कऑर्डर सब हुए, हुए थे जी उसके बावजूद भी फ्लड से रोक दिया गया उसको।

माननीय अध्यक्षः ये लिखके दीजिए सारा।

श्री राजेश गुप्ताः जी, उसी तरीके से आर आर चार्जेज का सभी भाइयों ने बता ही दिया। एक सहीराम जी ने जो बताया कि कुछ सड़के... बल्कि

बहुत सारी सड़कें ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं हमारे फण्ड से बना दो। तो ये कहते हैं, ''नहीं जी, काउंसलर ने बुक करी हुई हैं ये तो काउंसलर बनाएंगे। डेढ़ करोड़ की सड़क है, दो करोड़ की सड़क है और अभी मैंने दो दिन पहले एक एक्सईएन को इसीलिए फोन किया कि भई, आप आके मुझे बताओ, कब तक बनाओगे। लेकिन अभी तक तो वो मेरे पास आए नहीं हैं। एक दिन पहले उन्होंने कहा सिविक सेंटर में हैं। अब देखिए, अगर आज आएं या कल आएं, वो जब भी आएंगे... अध्यक्ष जी, मेरी इसके बारे में 5–6 चीजें जो सभी ने बात करी है, तो मैं इसके समरी के तौर पर कहना चाहता हूँ, एक तो क्योंकि ये जो फण्ड है, ये विधायक का जो फण्ड है जनता के लिए है और मेरा मानना है विधानसभा को इसके लिए एक समय निर्धारित करना पड़ेगा कि आप एक तो जो हम चिट्ठी देते हैं, उसके बाद में समय निर्धारित कीजिए, विधान सभा करे कि चिट्ठी देने के बाद में कितने समय में वो रोड बन जाएगी। कंप्लीशन का जो सर्टिफिकेट है कि ये कंप्लीट हो गई है, ये एमसीडी कितने दिनों में दे देगी, मेरी चिट्ठी देने के बाद में ये आप निर्धारित कीजिए यहाँ से। तीन–तीन साल, जनता का पैसा है, जनता परेशान हो रही है फायदा क्या है उसका, बात नंबर एक।

दूसरा, कि जो उसको बनाते हैं ठेकेदार, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि वहाँ पर बोर्ड लगाया जाए; कौन बना रहा है, ठेकेदार का नाम, कितने का बना रहा है, किसके फण्ड से बनाया जा रहा है। कोई बोर्ड लगाने को ही राजी नहीं है। कोई बताकर राजी नहीं है कि वो गली... जो जिसका मन करता है, कांउसलर कहता है, ''मैंने बना दी गली।'' आरडब्ल्यूए वाला कहता है, ''मैंने बना दी।'' विधायक कहता है, ''मैंने बना दी।'' अरे भई, जिसका है, उसका लगा दो। लेकिन ये लगाते नहीं हैं। और उसका भी

एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मेरे यहाँ पर... वो भी चुनाव की ही बात थी कि दो जगह के पार्क के अंदर वॉक प्लेस बनने थे। एक पर किसी वजह से कुछ पब्लिक ने कहा, इसे रोक दो, दूसरे ने कहा, इसे रोके रखा। चुनाव होने के बाद में वहाँ पर काउंसलर आए। उन्होंने कहा कि जी मैं बनवा रहा हूँ। उन्होंने एक बहुत बडा बोर्ड लगवा दिया। जब मैंने शिकायत की तो शिकायत के बाद तो नहीं हटाया जब हल्ला हुआ पब्लिक से जब इन्होंने जरूर हटा दिया।

तीसरी बात, मैं कहना चाहता हूँ कि बोर्ड लगाएं... तीसरी चीज जो इसके अंदर है कि जो सेविंग्स होती है इसके लिए भी समय निर्धारण है। जब आपने टेंडर कर दिया, टेंडर ले लिया गया, टेंडर सेल हो गया, ऑब्वियेसली सेविंग आपको तभी पता लग जाती है कि सेविंग क्या है। तो उसके बाद में विधायक को क्यों बार–बार कहना पड़े कि सेविंग वापिस दे दो। आप यहीं से समय निर्धारित कीजिए और उसके बाद में ये नहीं देते उस पैसे को। तो ये निर्धारित होगी जब एमसीडी के अंदर अगर पैसा जाता है विधायक का और उसके ऊपर काम नहीं होता है या ये पैसा रखा रहता है तो उसका ब्याज दिया जाए। क्योंकि इतना ब्याज इनके पास में बच गया होगा इसी विधान सभा का जो छठी विधान सभा चल रही है कि अब लगभग तीन चार विधान सभाओं की गलियाँ तो फ्री में ही बनवानी है। ये पाँच छः चीजें यहाँ पर निर्धारत कीजिए और क्योंकि यहाँ पर सारे कमिश्नर आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, ये भी निर्धारत हो कि कम से कम... कमिश्नर क्वार्टरली... कम से कम वीकली नहीं कर सकते तो। कम से कम यहाँ पर अपने साथ में विधायकों के साथ में एमएलए फण्ड को लेकर मीटिंग्स करें। हम यहाँ पर गाल बजाने के लिए नहीं आते। हम यहाँ शोर मचाते रहें, रिक्वेस्ट करते रहें, यहाँ पर रोज की रोज एक ही ड्रामा. एमसीडी काम नहीं कर रही है, एमसीडी काम नहीं कर रही है...

मैं एमसीडी की, विधान सभा का भी मेम्बर हूँ। जो वहाँ पर एमसीडी का हाउस लगता है, उसका भी मनोनीत सदस्य हूँ। उसके बाद में वहाँ पर भी वो ही ड्रामा होता रहता है। और यहाँ सिर्फ बोलते रह जाते हैं, कोई काम नहीं होता। यहाँ पर या तो निर्धारित कीजिए जो पांच छः चीजें जो मैंने आपको बताई है कि ये निर्धारित करें और इसका जवाब दिया जाए, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंहः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, कल से मैं अपने काफी सारे साथियों को सुन रहा हूँ। विपक्ष के साथियों ने भी इस मसले पर अपनी बात रखी। एक तरफ तो अध्यक्ष जी, वो लोग हैं जो कहते हैं कि चाहे हमारा नाम मत लिखो, चाहे हमारे से उद्घाटन मत करवाओ। पर जनता के हित के लिए यहाँ पर काम करो और एक तरफ वो लोग है जिनकी सोच में कूड़ा भरा हुआ है। जो कहते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए, ये काम नहीं होना चाहिए। तो इस जगह पर इन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें क्या फैसला करना चाहिए। बहरहाल जो मसले आपने यहाँ लाने का आदेश दिया था, वो कुछ मसले मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूँ।

अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं ये लैटर जिसके पीछे 54 कामों का एस्टीमेट बनाने के लिए बोला गया था। ये लैटर 29/2/1016 को एमसीडी से रिसीव कराया हुआ है। आज तक इसका कोई रिप्लाई ही नहीं आया है। 54 काम इनको वार्ड वाईज लिस्ट दी थी, पिछले तीन पेजों पर और इनके एस्टीमेट बनाने का एमसीडी को कहा गया था। आज तक इस लैटर के ऊपर कोई रिप्लाई एमसीडी की तरफ से मेरे को नहीं आया है।

दूसरा मसला अध्यक्ष जी, मोहल्ला सभा मेरी विधान सभा में पॉयलेट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी। उस मोहल्ला सभा के अंदर बहुत सारे काम एमसीडी ने अपनी जिम्मेवारी पर लिए थे। और क्या–क्या रीजन देकर वो काम रोके गए हैं, आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे अध्यक्ष जी। सत्रह ब्लॉक तिलक नगर के अंदर एक बैडमिंटन कोर्ट बनना था। तो इसके स्टेटस पर लिखा है, *'इन 17 ब्लॉक, तिलक नगर, वर्क कम्पलीटेड एज पर एमसीडी ऑन 2/3/2016'* जबकि आज तक अध्यक्ष जी, वहाँ पर कोई बैडमिंटन कोर्ट नहीं बना। तो गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी ये आगे लैटर आपको फारवर्ड कर रहा हूँ इसमें तय होना चाहिए। दूसरा लिखा था जी, 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन ब्लॉक 16' तो इन्होंने इसका आन्सर दिया जी, अनअवेलेबिल्टी ऑफ लैंड। जबकि 21 ब्लॉक में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगी है, एमसीडी ने बनाई है। सेम वैसे ही ये ब्लॉक है। काम न करने के बहाने क्या–क्या हैं अध्यक्ष जी, वो दो चार मैं ये बता रहा हूँ।

तीसरा था जी, ***contruction of road between 18 and 23 Block already being in the plan of the other agencies. Ye MCD ne likhkar diya ji. Uske baad, Repairing of road various location of F Blcok Khyala. To ye bolte hain ki 'not part of AC-29.'*** अब इनको गलती लग सकती है कि एसी 29 का क्या पार्ट है, क्या नहीं हमको नहीं लग सकती अध्यक्ष जी। क्योंकि ये दफ्तरों में बैठकर काम करते हैं, हम ग्रांउड में काम करते हैं। एफ ब्लॉक ख्याला, एसी 29 का ही एक पार्ट है जिसको इन्होंने लिखकर दिया है कि पार्ट ही नहीं है आपकी विधान सभा का।

अगला था जी, ***'Contruction of D Block street Khyala work as of now not feasible as per site report.'*** ऐसे–ऐसे बेहिसाब इन्होंने बहाने मार कर और काम रोक दिये जो आज तक नहीं हो पाये।

अध्यक्ष जी, 48 काम ये, 2016 से अब तक जो पेंडिंग रखे हुए हैं। अडतालिस काम ये हैं, 54 काम ये हैं जो इससे पहले वाले लैटर में है। इसके बाद कुछ एमसीडी ने किए भी हैं।

माननीय अध्यक्षः ये सब एमएलए लैड से हैं?

श्री जरनैल सिंहः इसमें एमएलए लैड की ये 54 वाले और 48 मोहल्ला सभा के हैं। तो इनको तो फण्ड से मतलब है अध्यक्ष जी। मतलब काम कहाँ का कैसे कैसे रोका जाता है, ये इसका ब्यौरा है।

तीसरा, ऐसा नहीं कि काम बिल्कुल ही नहीं करती, एमसीडी थोड़ा बहुत काम करती भी और पहले जो 49 दिन की सरकार थी जो एक साल लगभग हमने काम किया था, उसमें एमसीडी ने काम किए भी थे। पर इस सरकार के साथ पता नहीं क्या, इतना ज्यादा बैर हो गया है। कुछ काम किए तो अध्यक्ष जी, उनका काम पूरे होने के बाद जैसे ये दो सड़के बनीं तो सड़क तीन महीने बाद ही उसके कंकर बजरी निकलना बाहर शुरू हो गया। उन कामों का दो ये लैटर एमसीडी कमिश्नर को दोनों लैटर रिसीव करवाएं हैं, एड्रेस इनके आफिस में किए हैं। एक लैटर है जी, 10/5/2016 का दूसरा लैटर 7/12/2017 का। दोनों लैटर्स पर ये है कि अगर सड़क सही तरीके से नहीं बनी, सडक बनने के कुछ महीने बाद टूट गई तो उस पर किस की जवाबदारी है। क्या जवाबदारी है, क्वालिटी कन्ट्रोल डिपार्टमेंट क्या करता है, उसका आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब एस्टीमेट बनने से लेकर और काम हो जाने के बाद तक किसी भी चीज पर कोई जिम्मेवारी एमसीडी अपनी नहीं ले रही है।

इसके बाद अध्यक्ष जी, कुछ ये मसले हैं जिनके एस्टीमेट के लैटर मैंने अलग से दे रखे हैं एमएलए लैड फण्ड से। ये अलग हैं क्योंकि वो 2016

का लैटर था, ये 2017 का लैटर है। किसी मामले पर कोई सुनवाई नहीं होती। हम जल बोर्ड में काम देते हैं, पीडब्ल्यूडी में काम देते है, फ्लड इरिगेशन में काम देते हैं, दिल्ली सरकार के विभागों में भी काम देते हैं। तो एक्सईन साहब आते हैं नहीं, तो जेई को भेज देते हैं। जेई आ जाता है आके और काम समय सीमा में करके दे जाता है। थोड़ा बहुत डिले चलो, कहीं भी चलता रहता है। पर यहाँ पर तो एक्सईन से ज्यादा जेई के नखरे हैं अध्यक्ष जी, और आकर अध्यक्ष जी, कई बार जेई ने बोला भी है, ''आपको मालूम है कि हमें तो काम करने के लिए हिदायतें दे रखी हैं। निगम पार्षद जी नाराज हो जाते हैं, जो आपके काम करते हैं। तो इन चीजों के ऊपर इनको सबसे पहले तो विधान सभा की कमेटी जो आप बना रहे हो, संज्ञान ले, समय काफी हो चुका है, आप भी इशारा कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, ये मैटर सारा का सारा दे रहा हूँ, साथ में ये कवर लैटर भी लगा कर दे रहा हूँ। तो इनके ऊपर संज्ञान लिया जाए और तय समय सीमा के अंदर इस पर कार्रवाई हो। इनकी समय सीमा तय हो कि एस्टीमेट बनने की समय सीमा क्या है। अध्यक्ष जी, आगे भी काम करवाने हैं इनसे। इनसे ही करवाने पड़ेंगे, मजबूरी है। अगर हम एस्टीमेट का लैटर दे रहे हैं तो एस्टीमेट कितने दिन के अंदर प्रेपेयर हो, ये हमारे पास भी गाइड लाइन आए कि इतने दिन के अंदर अगर एमसीडी एस्टीमेट प्रेपेयर नहीं करती तो जिम्मेवार अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। एस्टीमेट बनने के अंदर हमने सेंक्शन का लैटर दे दिया, फण्ड सेंक्शन हो गया तो टेंडर क्यों नहीं लग पाया, उसमें भी इनके पास 36 बहाने होते हैं। टेंडर होने के बाद अध्यक्ष जी, एक मिसाल आखिरी आपके सामने रखना चाहता हूँ। टेंडर हो गया था, मतलब फण्ड अप्रूव हो गया, काम का नाम था 'प्रोवाइडिंग

रेट्रो–रेफ्लेक्टिव लाइन्स फॉर कार पार्किंग।' अब इसमें ये कह रहे हैं जी, पुटिंग लिख दिया हमने प्रोवाइडिंग की जगह। तो ये पुटिंग को प्रोवाइडिंग करना... दो साल से ये काम रूका पड़ा है अध्यक्ष जी। पैसा ले चुके हैं आधा, वहाँ तिलक नगर के बाजार के अंदर लाइनें डालनी हैं। तो कह रहे हैं, कह रहे है जी, वो पुटिंग की जगह हमने प्रोवाइडिंग लिखना है, उस वजह से दो साल से काम को रोक रखा है। मतलब कोई भी बहाना, कैसा भी बहाना, कुछ भी बोल दो कि जवाब तो देना ही नहीं है। ऐसा ही मसला एक हाई कोर्ट के अंदर लेकर गया हूँ। कमिश्नर साहब को मालूम है, वहाँ जी भर के खिंचाई हो रही है। हाई कोर्ट ने नोटिस किया है कि अगली डेट पर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देकर राजी। ऐसा नहीं अध्यक्ष जी, विधान सभा की कमेटी से काफी उम्मीदें है, आपसे काफी उम्मीदे हैं। तो ये क्वालिटी कन्ट्रोल वाला मसला भी हाई कोर्ट के अंदर जाकर रिट लगाएंगे।

आपने इतने गम्भीर दिल्ली की जनता से जुड़े मामले पर बोलने का समय दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः ये इस पर आपने एसी नम्बर लिख दिया है ना सब पेपरों पर? धन्यवाद। सरिता सिंह जी। जो कल बोल चुके हैं, आज उनका रेपिटेशन नहीं होगा। हाँ, मैंने लिखा हुआ है नाम। भई मैंने सुरेन्द्र जी नाम लिखे हुए है। हम ही समय को खराब करेंगे तो क्या होगा?

श्रीमती सरिता सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे एक ऐसे विषय पर बोलने का मौका दिया जिस पर बहुत ही ज्यादा शायद हम जितने भी विधायक यहाँ बैठे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। मैं पहले यह समझना चाहती हूँ कि एमएलए फण्ड का मतलब क्या होता है। ह्वाट डज एमएलए लैड मीन्स? जब दिल्ली में सरकार है और सरकार के पास अपना फण्ड

है तो सरकार तो काम करती ही है। तो अलग से एमएलए लैड क्यों बनाया गया, इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा। इसके पीछे लॉजिक ये था कि अगर क्षेत्र के छोटे मोटे काम हैं जो तुरन्त करवाने हैं, एक महीने दो महीने के अंदर करवाने हैं, तत्काल प्रभाव में करवाने हैं तो वो एमएलए लैड के थ्रू करवाएं जा सकें। इस लिए एमएलए लैड एक अलग से फण्ड एमएलएज को दिया गया था। एमएलए लैड की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आज जो सुनने को मिल रहा है कि तीन साल तक एमएलए लैड यूज नहीं हो पा रहा है तो फिर एमएलए लैड का कोई मतलब नहीं बनता है।

मैं भी अपने यहाँ की बिल्कुल जनरैल भाई की तरह पूरी एक फाइल ले के आई हूँ। 2015–16 का बजट हमें विधानसभा से मिला, हम खूब खुश हुए। पहली बार मैं विधायक बनी थी, खूब खुश हुए कि इस बार पैसा मिला है खूब सारा काम करेंगे अपनी विधान सभा में और मेरी विधान सभा 95 परसेंट या 99 परसेंट आप कहिए ऑथोराइज विधान सभा है, रेगुलराइज विधान सभा है। इसलिए पूरा का पूरा काम मेरे एमसीडी करती है, दुर्भाग्यपूर्ण! शायद ये काम फ्लड या डीएसआईआईडीसी करती तो शायद मेरे पास भी कुछ कहने को होता कि मेरे यहाँ पे ये काम हुआ है। 2015–16 का जब बजट आया तो मैंने कुछ गलियों को ये टोटल 121 वर्क हैं जो हमने एमसीडी के द्वारा करवानी थी। इम्प्रूवमेंट ये अगर मैं एमसीडी की भाषा में बोलूँ तो ज्योति नगर की गली है और अगर आम भाषा में बोलूँ तो और अगर एमसीडी की भाषा में बोलूँ तो इंप्रूवमेंट एण्ड डेवलपमेंट ऑफ रोड हाउस नंम्बर इतना इतना... ज्योति नगर। इसका पैसा एलॉट हो गया जी यूडी से। उस समय यूडी हुआ था, उस समय डूडा था नहीं। यूडी से वो पैसा एलॉट हो गया, ये रिपोर्ट है, देखिए सर जी, ये मेरा कोई कहानी नहीं, कुछ भी नहीं है। इसमें लिखा है वर्क डन– जीरो परसेंट– 2015–16, उसी तरह वेस्ट रोहतास

नगर में गली नं. 4 है मकान नं. 1/91 टु 1/91 58–ए। पैसा एलॉट हो गया, 17 लाख रुपये का, वर्क डन–परसेंट, उसी तरह वेलकम कालोनी द वेलकम रोड में सप्तऋषि मार्ग है, ये तो पता नहीं, इसमें क्या हो गया, कैसे हो गया। 13 लाख का बजट एलॉट हुआ, टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया, मैं बार बार पूछती रही, ''जी, ये सड़क क्यों नहीं बन रही, ये सड़क क्यों नहीं बन रही, ये सड़क क्यों नहीं बन रही, बता दो जी, सड़क क्यों नहीं बन रही?'' लैटर पे लैटर, एक्सईएन को लैटर, एई को लैटर, जेई को लैटर पूरी पत्राचार कर दी और आज भी इसका स्टेटस रिपोर्ट जीरो परसेंट। उसी तरह 2016–17 का बजट आया। 2016–17 में फिर क्योंकि मजबूरी है भई, एमसीडी को ही काम देना है कोई और डिपार्टमेंट ही नहीं है और मैं पहले साल ये समझ गयी थी कि अगर एनओसी के चक्कर में पड़े तो न ये एनओसी देंगे, खुद तो ये काम करते नहीं और एनओसी ये देने से रहे तो एनओसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए जितना काम एमसीडी के थ्रू एमसीडी के ही जमीनों में हो सकता है, उतना ही काम करवा लो बाकी तो ये करने से रहे। न एनओसी होगा और न ही प्रवीण की तरह हालत हो जायेगी, प्रवीण भाई की तरह कि मैं आज बोलूँगी कि मेरे पास इतना सारा एमएलए फण्ड बचा रह गया। 2016–17 में नत्थू कालोनी गली 16–17 मतलब पिछले साल का फंड। उसमें वर्क डन–50 परसेंट, वो भी 2–4 पिलर ऋतुराज की तरह ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, वो 50 परसेंट लिखा है बस उसमें। उस तरह से कई सारे काम हैं जो मैंने इस फाइल में लिख के लाई हूँ। एक एक करके पढ़ना शायद पॉसिबल नहीं हो पायेगा। मैंने पिछले साल और उसके पिछले साल सब को ये पता है कि मैं थोड़ा पिछले साल थोड़ा अस्वस्थ थी तो जब 2015–16 का बजट आया तो मैंने कुछ लाईटों की रिक्वायरमेंट ईडीएमसी को दिया, वो लाइटें ऐसी लगी, ऐसी लगी, ऐसी लगी कि मुझे लगा ईडीएमसी

अहसान कर रहा है मुझ पर, लाइटें लगा के। और वही सेम बात जो अनिल बाजपेयी जी ने बताया कि उस समय मैंने केवल सौ लाइटें दी थी, ये देखने के लिए कि कैसे लगती हैं, कितना फास्ट काम होता है, उन सौ लाईटों को लगाने में ईडीएमसी ने एक साल से ऊपर का समय लिया और वो सारी की सारी लाइटें आज खराब पड़ी हैं क्योंकि ईडीएमसी ने बीएसईएस को हैंड ओवर नहीं किया अभी तक। वो पेपर चल ही रहा है। उसी तरह 2016–17 में लाइटों की रिक्वायरमेंट इनको दी गयी लगभग 600 लाइटों की। वो 600 लाइटों का स्टेटस आज 2018 में मैं खड़ी हूँ और वो लाइटें आज तक नहीं लग पाई हैं। और उनके वर्क उसपे ये लिखा हुआ है कि *'वर्क हैज बीन कम्पलीटेड।'* उसी तरह *'कंस्ट्रक्शन ऑफ खजूर वाली गली'* ये नवीन शाहदरा की है, *इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड',* ये वेलकम कालोनी की फोटो, चौक वाली रोड है। उसी तरह मोती राम रोड, जायसवाल मार्किट, सारी लाइटें ये लैटर है 2017 जून का, ये लैटर है 2017 जून का। इन दोनों का फण्ड फतेह सिंह जी ने खूब मेहनत करके हम लोगों ने जबर्दस्त मतलब खूब मेहनत ट्रांस यमुना के सारे विधायकों ने करी और ट्रांस यमुना को चालू करवाया और ट्रांस यमुना से सारे बजट अलॉट हो गये। लगभग पाँच महीने हो चुके हैं इनका कुछ नहीं पता। ईडीएमसी के पास पैसा जा चुका है पर ये गलियाँ कब बनेंगी कुछ नहीं पता। उसी तरह पार्कों में काम के लिए ये सात काम हैं। उसके अलावा और 14 काम हैं जो पार्कों के लिए दिया हुआ है। ये लैटर भी जून 2017 का है, इसमें अभी तक कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो ये मैं समझना चाहती हूँ कि एमएलए लैड का इतना ज्यादा दुरूपयोग जो एमसीडी कर रही है... या तो ये एमएलए लैड का सेंसिटिविटी नहीं समझ रही है। एमएलए लैड मींस कि वो काम तुरंत किया जाए। हम जब क्षेत्रों में जाते हैं तो लोग हमें छोटी छोटी समस्या बताते हैं कि मैडम, ये सड़क बिल्कुल टूटी है, बारिश से पहले बनवा दो,

नहीं तो पूरा पानी भर जाएगा और हमें पता है किसी कीमत में एमसीडी बारिश से पहले वो सड़क बनाएगी ही नहीं। हम जैसे विधायक बिल्कुल मजबूर हैं कि हमारे पास न पीडब्ल्यूडी, न हमारे पास फ्लड है, न हमारे पास डीएसआईआईडीसी है। आखिरी चारा, एमसीडी बचता है हमारे पास में। एमसीडी काम करने को तैयार नहीं है, पैसा देने के बावजूद, एक तरफ से तो ये लोग रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, फण्ड नहीं हैं। एमएलए अपना पैसा दे रहा है, अपना पैसा ब्लॉक कर रहा है, अपना पैसा फंसा रहा है, उसके बावजूद भी एमएलए का काम नहीं होता है। जो सेविंग की बात है, बिल्कुल वाजिब है कि अगर कोई किसी टेंडर अमाउंट कोई पैसा सेंक्शन हुआ है दो करोड़ का, उसमें टेंडर अमाउंट साढ़े सात करोड़ जो डेढ करोड़ गया, वो गया कहाँ? नो एकाउन्टबिल्टी एट ऑल। तो ये सारी चीजें और एक चीज जो मैंने देखी थी, जब हम विधायक बन के आये थे तो 2015–16 में ही दिक्कत नहीं आयी थी, 2016–17 में जब हमने एमसीडी को एस्टीमेट बनाने की बात करी तो एस्टीमेट इनसे पता नहीं, क्यों नहीं बनता? क्या पढ़ाई करी है इनके जेई ने, क्या पढ़ाई करी है इनके एई ने, क्या पढ़ाई करी है इनके एक्सईएन ने, कुछ समझ नहीं आता। मतलब अगर एस्टीमेट बनाना है तो एस्टीमेट बनाने में छः महीने कैसे लग जाते हैं, समझ नहीं आता! 6–6 महीने में एस्टीमेट मिलता है, छः महीने बाद एस्टीमेट बनता है और जब तक डूडा उस समय थी, दो महीने एक महीने के अंदर डूडा से पैसा इनको एलॉट हो गया, छः महीने बाद जाके टेंडर लग रहा है। टेंडर के बाद में दो महीने बाद, तीन महीने बाद वर्क ऑर्डर हो रहा है। गली खुद गयी जी, 9–9 महीने तक चंद्रलोक, गली नं. –दो, न्यू मॉडल शाहदरा गली नं.–आठ, जगतपुरी गली नं.–चार, ऐसी कितनी सैंकड़ों गलियाँ हैं जो क्षेत्र की जनता आपको बताएगी अगर हम वहाँ पे

विधान सभा की कमेटी वहाँ पे विजिट करने जाए। 6–6 महीने, 8–8 महीने गली खुदी पड़ी थी पर कोई सुध लेने वाला नहीं था।

माननीय अध्यक्षः सरिता जी, करिए, कन्क्लूड करिए।

श्रीमती सरिता सिंहः नहीं, बिल्कुल आज अगर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं इसका, इस पर नहीं पहुंचे तो ये चर्चा व्यर्थ हो जायेगा। समय सीमा तय करनी पड़ेगी कि अगर एमएलए लैड सेंक्शन होता है तो उसके दो महीने या तीन महीने के अंदर काम जमीन पे खत्म हो जाना चाहिए। समय सीमा बिल्कुल तय होनी चाहिए क्योंकि अधिकारियों को कोई कुछ नहीं बोलता। जब हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता हमसे जवाब मांगती है कि विधायक जी आपने गली खुदवाई थी, गली नहीं बनी अभी तक। हमने ये गली बोली थी बनवाने के लिए, अभी तक ये गली नहीं बनी। ये लाइट आप ने लगवाई थी, ये लाइट खराब क्यों पड़ी है? सारी चीजों पे समय सीमा तय होनी चाहिए। और दूसरी बात जब हम 2016–17 जब हमने बजट बनवाया, हमने एस्टीमेट बनवाया तो हमसे ये कहा गया कि पाँच परसेंट एक्स्ट्रा लगेगा। आपकी विधान सभा में भी ये आया होगा। हम से पहले भी दिल्ली में जो विधायक थे, हम कोई पहली बार विधायक चुन के नहीं आये हैं, तो वो 5 परसेंट कमीशन एमसीडी उन विधायकों से नहीं लिया, तो हम से क्यों लिया? ये कौन सा चार्ज है जो एमसीडी हम से ले रही है? हमने अगर हम पैसा दे रहे हैं एमएलए लैड दे रहे हैं तो हमें हर चीज जानने का अधिकार है।

माननीय अध्यक्षः चलिए, अब कन्क्लूड करिए, सरिता जी।

श्रीमती सरिता सिंहः इनकी नीयत नहीं है, काम करने की। तो अध्यक्ष महोदय, तो इसलिए समय सीमा बिल्कुल तय होनी चाहिए, और सर जी,

ये एक बात और बता दूँ मैं एक बात और बता दूँ किसी भी वर्क ऑर्डर में लिखा रहता है अपर लिमिट 90 डेज तीन महीना। एमएलए लैड का काम है, अगर वो 90 डेज में पूरा नहीं होता है तो उससे एमएलए से पूछोगे कि न उसको एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है। डिपार्टमेंट अपनी इच्छा से उस काम को एक्सटेंड करता है 120 डेज। हू *हैज गिवन देम द अथॉरिटी टु एक्सटेण्ड दैट पीरिएड?* अगर 90 दिन में काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? 120 का एक्सटेंशन का पॉवर इनको किसने दिया? एमएलए फण्ड का पैसा है वो, एमएलए लैड है वो हमारा। हमने जनता को अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ एलएलए लैड। हम क्यों यूज कर रहे हैं एमएलए लैड को? दिल्ली सरकार तो खूब पैसा दे रही है, खूब काम करवा रही है। हम अलग से एमएलए लैड क्यों लगा रहे हैं? तो इसकी अकाउंटिबिल्टी बिल्कुल तय होनी चाहिए और अगर आज इस चर्चा के बाद में इसपे कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो मैं बिल्कुल बता दूँ सर जी, कि फिर सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। ये लोग और चौड़े होकर घूमने वाले हैं।

माननीय अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सरिता सिंहः धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः प्रमिला टोकस जी, इसके बाद टी ब्रेक रहेगा फिर आधा घंटे के बाद बैठेंगे। हाँ इसी पे होगी, इसी पे पूरी कहाँ हुई है अभी।

श्रीमती प्रमिला टोकसः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मैंने ये लैटर एमसीडी को लिखे हैं।

माननीय अध्यक्षः एक सैकण्ड, बंदना जी कल बोल चुकी थी लेकिन काफी एस्टीमेटस, लैटर्स जो भी हैं, इनके आये हैं मेरे पास। हाँ, प्रमिला जी, शुरू करें।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, मैंने ये इतने लैटर एमसीडी को लिखे हैं, टेण्डर लगवाने के लिए लेकिन एक भी टेण्डर अभी तक नहीं लगा क्योंकि मेरा ऐसा एरिया है... या तो एमसीडी का है या सीपीडब्ल्यूडी का है। एमसीडी के पार्कों में झूले लाइटें, उसमें डस्टबीन, उसमें जिम सभी अपने पूरे विधानसभा में हमने लिखे लेकिन कोई भी अभी तक एस्टीमेट नहीं बनाया। अध्यक्ष जी, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे एमएलए की कोई भी शिकायतें नहीं होती। ज्यादातर जो शिकायत होती हैं, वो एमसीडी से रिलेटेड शिकायतें होती हैं और जो एमसीडी बिल्कुल करती नहीं हैं। अध्यक्ष जी, आज भी हम अभी मीटिंग करके आये, उस मीटिंग में भी उनकी जो शिकायतें थीं; न कहीं पर लाइटें हैं, पोल लगाने हैं, वो पोल नहीं लगाये जा रहे और जो लाइटें लगाई हुई हैं, वो उन्होंने छत पर या कहीं दीवार पर लगी हुई हैं, कोई पोल पर नहीं लगाते। अध्यक्ष जी, ये जो पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है। ये हमारा कोई पैसा नहीं है और जो पब्लिक ने हमें चुना था तो हमें इसीलिए चुना था जो उनकी प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करें और जो भी हम एरिया में जाते हैं तो हमारी शिकायतें सारी एमसीडी की होती हैं। तो हम जब पब्लिक को भी जब ये बोलते हैं, ये हमारा काम नहीं है, एमसीडी का काम है तो उनको भी बुरा लगता है और पब्लिक भी ये जानती है कि वो काम एमसीडी के काऊंसलर नहीं करेंगे, आप ही करायेगें। अध्यक्ष जी, इसलिए मैंने ये इतने लैटर एमसीडी को लिखे हैं, अब तक कोई भी टेण्डर नहीं लगाया और टेण्डर लगाया, अभी तक काम शुरू नहीं किया। मैंने 25 गलियाँ अपने मुनिरका गाँव की लगवाई, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैंने सैक्टर चार में पर्वतीय कैम्प है, उसमें से नाला जाता है, वो पक्का कराने के लिए पैसे दिये, अभी तक वो नाला पक्का नहीं किया गया। मैंने मोहम्मद पुर में पार्क है एमसीडी का, उस पार्क में झूले लगाने के लिए, जिम लगाने के लिए, उसमें दीवार करने के लिए उसके लिए पैसे

दिये, आज तक वो काम नहीं किया गया। अध्यक्ष जी, जब मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठाता और न मीटिंग के लिए आते हैं और न ही देते हैं। फोन नहीं उठाते तो टाइम भी नहीं देंगे, आयेंगे भी नही। तो ये अध्यक्ष जी, आज ये सुनिश्चित करें, ये ऑर्डर करें कि जो भी... क्योंकि वो भी पब्लिक के नुमाइंदे हैं, वो भी पब्लिक के लिए आये हैं, उन्हीं के पैसों से उनको तनख्वाह मिलती है और हम भी पब्लिक के लिए हैं। जब हम इतनी भाग दौड़ करते हैं तो वो क्यों नहीं करते और हम कोई अपने लिए काम नहीं बता रहे, हम जनता के काम के लिए इनके पास जाते हैं। कई बार हम भी गये हैं कमिश्नर के पास भी और मैंने अभी भी टाइम लिया है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमारे क्षेत्र में सारी ज्यादा से ज्यादा समस्याएं सीपीडब्ल्यूडी की हैं, उसमें सारी एमसीडी की दिक्कते हैं चाहे वह नालियों की हों, अभी बरसात शुरू होने वाली है सारी नालियाँ टूटी पड़ी हैं, न उन पर कवर हैं, अभी बारिश होगी, फिर मच्छर पैदा होंगे, फिर मलेरिया बीमारियाँ शुरू हो जायेंगी। फिर कहेंगे कि दिल्ली सरकार के ऊपर ठीकरा रखेंगे कि वो नहीं कर रहे और पिछली बार दिल्ली सरकार ने ये मुहिम चलाई थी, मलेरिया या डेंगू पिछली बार हमने सुना था कि बहुत कम डेंगू के ऐसे केस देखे हमने क्योंकि वो हमने पहले से ही कार्रवाई शुरू की। इसलिए दिल्ली में डेंगू के जो केस थे, वो कम थे और मुझे लगता है कि एमसीडी भी अपना कार्य अगर सुचारू रूप से करे तो कहीं पर भी दिल्ली में कोई भी शिकायत नहीं हो सकती क्योंकि अपना कार्य हम अपनी ईमानदारी के साथ करें और...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, एमसीडी से नहीं हैं, ऐसा नहीं है।

श्रीमती प्रमिला टोकसः एमसीडी से रिलेटिड है।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, वो अपने पूरा मेहनत करके आई हैं, पूरा लैटर ले के आई हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, चलिये, एक महिला कभी कभी बोलती है। तो डेंगू एमसीडी का विषय नहीं है? नहीं सिरसा जी, अब आप ये एक महिला को आप... ये ठीक नहीं है, सिरसा जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, ये सिरसा जी, ठीक नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है। चलिए, ठीक है। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। प्रमिला जी, विषय हो गया पूरा?

श्रीमती प्रमिला टोकसः नहीं, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः मैं करूँगा, अभी करूँगा, चिंता मत करिए।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, जब ये बोलते हैं, तब हम बोलते हैं, आप तुरंत बिठा देते हैं। ये आधी बात झूठ बोलते हैं। हम तो सच्चाई बोलते हैं। ये सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। दिल्ली की जनता के लिए जब भी हक की बात होती है, तब तब ये ऐसे ही करते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः छोड़ दीजिये। हाँ, चलिए।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, दिल्ली की भलाई के लिए जब हम हाऊस में काम करते हैं, जब ये यही काम करते हैं ये सुनने के लिए

तैयार नहीं हैं दिल्ली की जनता के विरूद्व हैं। भाजपा पार्टी... अभी हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ उस पर भाजपा के साथी क्यों नहीं बोले थे?

माननीय अध्यक्षः प्रमिला जी आप अपने ये पेपर रखिये सारे। प्रमिला जी, आप पेपर रखिए। सदन पटल पर रख दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया आपका विषय? हो गया। सदन आधे घंटे के लिए सदन स्थगित किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही चायकाल के लिए आधे घंटे के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 5.00 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः बैठिए। चलिये, सुरेन्द्र सिंह जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसा है, विजेन्द्र जी...

श्री सुरेन्द्र सिंहः श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अति गंभीर विषय के ऊपर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एक सैकण्ड सुरेन्द्र जी। सौरभ जी, देखिए, ऐसा है. विजेन्द्र जी, मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ, इसको शांति से सुन लीजिए। अगर इस तरह से सदन का समय खराब करना है... ये तो उनसे पूछिये ना विधायकों से जिनकी पीड़ा है। नहीं जिनकी पीड़ा है। आपको चारों सदस्य.

ऐसा है सिरसा जी, ये आपके तीन सदस्य बोल चुके, तीन सदस्य आपके बोल चुके और वो बोले नहीं। वो अपनी बात नहीं रखें? किसका, अब ये तो वो बतायेंगे ना। कोई इलाका नहीं है उनका।

... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंहः अरे! मेरा इलाका है सिरसा जी, एमसीडी के कमिश्नर यही बतायेंगे। मेरा इलाका है। एमसीडी के अंदर मेरा इलाका है। मुझे फंड नहीं मिलता क्या?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अगर यही रवैया है, मैं चर्चा नहीं करवा रहा। अगर यही रवैया है आपका तो मैं चर्चा नहीं करवा रहा। आपका यही रवैया है। आप छोड़ दीजिए। नहीं मैं नहीं करवा रहा आप करिए। आप बैठिये, आप बैठिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जरनैल जी, जगदीप जी आप चलिए वहा?। आप वहाँ चलिए। जगदीप जी आप चलिए वहाँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप चलिए वहाँ। आप बैठिए अपनी जगह। आप बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, करवायेंगे हम बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंहः महिला का अपमान कर रहा है, अध्यक्ष जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी, मैं, मेरी बात सुन लीजिए एक बार, जिस ढंग का रवैया है ना, ये चर्चा का, ये चर्चा करवाने का नहीं है। ये रवैया, ये रवैया सदन को डिस्टर्ब करने का है। ये चर्चा करवाने का रवैया नहीं है। न मैं रिक्वेस्ट करके... एक महिला बोल रही है, उस महिला सदस्य को बोलते–बोलते डिस्टर्ब कर दिया आपने। कोई मुसीबत आ रही थी?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैंने मना कर दिया, नहीं करवाना। हाँ, कर दिया मैंने मना। मैं चर्चा मना कर रहा हूँ। नहीं, मैं मना कर रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप कह रहे हैं... आप कह रहे हैं मना कर दीजिए। मैंने कर दिया मैंने।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जब आपका रवैया ही ये है।

... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंहः खुद भरके ला रहे सीवर में से ये। एक हमारा कार्यकर्ता बता रहा था, सीवर का पानी भरने लग रहे। बोला, वहाँ बैठे–बैठे एमएलए. रोज भर लाते हैं सीवर का पानी, ला रहे इकठ्ठा करके। कल बताया था प्रधान जी, प्रधान जी, आप तो बढ़िया आदमी हैं कल सीवर से लेना।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं चर्चा अभी नहीं करवा रहा हूँ। ये पूरी करके प्रस्ताव आ जाये, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। लेकिन ये चर्चा करवाने का तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ये चर्चा करवाने का तरीका नहीं है। आज पूरी दिल्ली एमसीडी से त्रस्त है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः जानबूझ के सीवर का पानी भर–भर के ला रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, प्लीज बैठिए। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, सिरसा जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, सिरसा जी, मैं जी कहके बोल रहा हूँ। न, आप अंगुली दिखाके बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं प्रार्थना कर रहा हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंहः सारी पेंशन खा गये एमसीडी की। एमसीडी की सारी पेंशन गुम कर गये। जानबूझ के फर्जी पानी लेकर आ रहे हैं, फर्जी... फर्जी पानी लेके आ रहे हैं नाले का भरके। रोज भर लाते हैं और कल ओम प्रकाश जी वो हाजमें वाली बोतल ले रहे थे, हाजमें की दवाई की बोतल।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन के वेल में आये)

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, जो महिलाओं का हाल इन्होंने किया है, विपक्ष के साथियों ने, पहले निंदा प्रस्ताव लाया जाए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए प्लीज, आप करिए सदन का समय खराब।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष महोदय, कल ये झुग्गी–झोपड़ी की चर्चा से भागे हैं, आज ये दिल्ली नगर निगम की चर्चा से भागना चाहते हैं, इन्हें बहाना चाहिए, दिल्ली परेशान है, कल झुग्गी–झोपड़ी की चर्चा से वाक–आउट करके भाग गए, विपक्ष के नेता ने चर्चा की।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैंने चर्चा करवाई है। कल झुग्गियों पर मैंने चर्चा करवाई है।

श्री सही रामः विपक्ष के नेता ने चर्चा की गुहार लगाई और जब चर्चा हुई, झुग्गी–झोपड़ी पे तो खुद चर्चा से भाग गए, आज ये दिल्ली नगर निगम की चर्चा से भी भागना चाहते हैं, इन्हें बहाना चाहिए, ये बहाना ढूँढ रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः जब तक एमसीडी पर चर्चा नहीं हो जाती, एमसीडी की चर्चा पूरी नहीं हो जाती जब तक मैं चर्चा नहीं करवा रहा हूँ। नहीं, एमसीडी की चर्चा होने दीजिए पहले।

... (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के भी कई माननीय सदस्य सदन के वैल में आ गए)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, सिरसा जी, आज आपने ज्यादती की है, ये महिला कभी नहीं बोलती। ये आज पहली बार बोलना शुरू किया, आप बीच में खड़े हो गए, आपने ज्यादती की है इनके साथ, बहुत ज्यादती की है इनके साथ, मुझे पसंद नहीं आया, ये बात पसंद नहीं आया मुझे, ये सीधी लड़की है कभी–कभी बोलती है, आपने टेढ़ापन दिखाया, आपने मतलब... एक महिला बोल रही है, उसको मान नहीं दिया आपने, आपने बाँध दिया उसको।

... (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं 5.30 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्रवाई 5.30 बजे तक स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 5.30 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय विजेन्द्र जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, एक बार मैं ये जल्दी पूर्वक कर रहा हूँ, देखिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, देखिए आपने खुद तीन से चार कहा था।

माननीय अध्यक्षः हाँ मैंने कहा था। मैं अभी मुकर नहीं रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं इसको एक बार कर... मैं इसको एक बार कम्पलीट कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं आपने क्या क्या कहा, मैंने कह दिया उस वक्त। अगर आपका ये रवैया रहेगा। मैं नहीं चर्चा करवाऊँगा भई। मैंने ये कहा है। नहीं बैठिए, आप। बैठिए अभी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः श्री सुरेन्द्र सिंह जी।

... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय...

माननीय अध्यक्षः आप शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंहः आपने मुझे इतने गंभीर इश्यू के ऊपर बोलने का मौका दिया क्योंकि एक ऐसा इश्यू है, इससे सभी विधायक दुःखी हैं और मैं तो खासकर जो है ना, चारों एमसीडी कहूँगा। दिल्ली कैंट बोर्ड, एनडीएमसी और नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी; ये चारों से मेरा वास्ता पड़ता है।

माननीय अध्यक्षः मैं विजेन्द्र जी...

श्री सुरेन्द्र सिंहः और जिस तरह से सिरसा जी कह रहे थे। मुझे लगा जैसे सावन के महीने में कोई आदमी ऐसा अंधा हो गया था तो उसको जब भी दिखाई देता था, हरा हरा दिखाई देता था।

माननीय अध्यक्षः बहुत अच्छा माहौल था। मैं चाहे आठ बजे तक सभा

समाप्त करता हूँ। लेकिन कल भी सदन का सारा समय खराब करा दिए। मैं नहीं करवाऊँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं प्लीज बैठिए। प्लीज बैठिए आप।

श्री सुरेन्द्र सिंहः वो एक दिन मेरे ऑफिस आ गया एनडीएमसी के में, तो इसको खाली ये ही दिखाई दे रहा है कि एनडीएमसी खाली। तो कैंट बोर्ड के अन्दर जो है मैंने 2013–14 के अन्दर फण्ड दिया; ढ़ाई करोड़ रुपये फण्ड दिया जो कि जिम लगवाए मैंने और वो जिम जो है, आज भी उन्होंने जिम लगा दिए पर उनको रन आज तक नहीं किया है। उनमें किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। मैं डीडीसी की मीटिंग में कई बार इस मुद्दे को लगाया पर डीडीसी की मीटिंग के बाद भी उसका कोई समाधान भी नहीं निकला है।

साथ ही मैंने मेहराम नगर के अन्दर बारात घर के लिए 54 लाख रुपये का फण्ड 2014–15 में दिया जो कि आज तक वो बारात घर नहीं बनाया है। उस पैसे से उसका जो है, टेंडर लगा दिया। उसका वर्क ऑर्डर नहीं दिया है और उस वर्क ऑर्डर को अभी लगातार घुमा रहे हैं। उसके बाद मैंने झुग्गी क्लस्टर के अन्दर दो जगह स्कूल बनाने के लिए प्राइमरी स्कूल के लिए पैसा दिया, 50 लाख रुपये जिसका 2013–14 का ये मेरा विधायक निधि कोष से दिया था फण्ड, वो स्कूल जो है ना, अब बनते हुए... इस दुष्टों ने मैं कहूँगा जो पार्षद हैं, वो क्या करते हैं अधिकारी के रूम में पहुँच जाते हैं, अधिकारी के घर पर पहुँच जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि अगर आपने बना दिया तो... अब तो जो बीजेपी जो तीन आदमी जीते थे फर्स्ट में स्कूटर की सवारी थी। हमारा काँग्रेस से भी बुरा हाल हो जाएगा।

इनके पार्षद ऐसी ऐसी दुहाई देते हैं वहाँ जा के और उसके बाद जो है अध्यक्ष जी, मैंने झुग्गी के अन्दर बोरवेल लगाने के लिए पैसा दिया, पानी के लिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठ जाइए।

श्री सुरेन्द्र सिंहः 2013–14 का विधायक निधि कोष से मैंने 15 लाख रुपया दिया पर जो है, बीजेपी के काउंसलर हैं आप, बीजेपी की सत्ता है। आज तक जो है उन बोरवेलों को नहीं लगाया गया जब कि दिल्ली सरकार ने हर तरह की परमिशन दी, हर तरह की इजाजत दी। आज तक वो बोरवेल नहीं लगे। गरीब आदमी वहा पानी के लिए त्रस्त है परन्तु जो बीजेपी के विधायक, पार्षद हैं, वहाँ पे और जो काँग्रेस के दो वहाँ पर पार्षद हैं, ये लोग वहाँ पर...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः ये राक्षस की तरह, दुष्टों की तरह काम कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बैठ जाइए, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंहः लोगों से जो इनको वोट नहीं दिए तो उसका वो गुस्सा ये निकालने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं मना कर रहा हूँ?

श्री सुरेन्द्र सिंहः इस तरह की घटनाएं लगातार हो हैं। न मैं वहाँ क्षेत्र के विकास के लिए 60 लाख रुपये पोर्टा केबिन बनाने के लिए वहाँ पे 60 लाख रुपये का फण्ड मैंने विधायक निधि कोष से पैसा दिलाया। परन्तु वो आज तक उसका टेण्डर कर दिया गया परंतु वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया है। जिस तरह से ये विधान सभा के अंदर गरीबों की आवाज के अंदर बाधा बनते हैं, उसी प्रकार ये यहाँ भी बाधा बने रहते हैं। साथ ही अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अंदर एनडीएमसी का क्षेत्र भी है। एनडीएमसी के क्षेत्र के अंदर मैं पूरे क्षेत्र में एरिया के बोर्ड लगाने के लिए तीस लाख रुपये का विधायक निधि कोष से फण्ड दिया। उस पैसे से बोर्ड लगाये गये, परंतु बोर्ड 10 दिन के अंदर ही उन बोर्डों को वापस उतार लिया गया और दोबारा से इन बोर्डों को अभी तक नहीं लगाया गया है। वहाँ पर झुग्गी केन्द्र और गलियाँ बनाने के लिए मैंने विधायक निधि कोष से पैसा दिया 2015–16 का, आज तक वो गलियाँ नहीं बनी है और जो वहाँ पर जिस तरह से ये लोगों के साथ बीजेपी कॉंग्रेस के पार्षद दुर्भावना से उनका काम रोकते हैं...

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अधिकारियों के साथ साथ...

माननीय अध्यक्षः सुरेन्द्र जी, कन्क्लूड करिए।

श्री सुरेन्द्र सिंहः जल बोर्ड ने मेरे क्षेत्र के अंदर एक एमजीडी पानी दिया। मैं जल बोर्ड का तहेदिल से धन्यवाद करता हूँ। 98 लाख रू. का वर्क आर्डर, 98 लाख रुपये विधायक फण्ड से वर्क ऑर्डर दिया गया, परंतु बीजेपी कॉंग्रेस के पार्षद जब निकम्मे, निठल्ले और रिश्वतखोर और कमिशनखोरी

के चक्कर में उन्होंने 98 लाख रुपये का वर्क ऑर्डर को रुकवा दिया और वो पानी के काम में लोगों को परेशानी हो रही है और क्षेत्र के अंदर पानी नहीं आ रहा है। ये जो लोग हैं, ये इस तरह से काम करते हैं, जनता से दुर्भावना का काम करते हैं।

साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि मैंने एक करोड़ छब्बीस लाख रुपये ओपन जिम लगाने के लिए...

माननीय अध्यक्षः मैं चारों सदस्यों को...

श्री सुरेन्द्र सिंहः दिल्ली कैण्ट बोर्ड को दिया।

माननीय अध्यक्षः आज की सदन की कार्यवाही से आज के सदन के लिए बेदखल कर रहा हूँ। मैं चारों सदस्यों को आज की बाकी समय की कार्यवाही के लिए बेदखल करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंहः और पुलिस कॉलोनी और राम नगर, पूरे एक क्षेत्र क्षेत्र पर और क्षेत्र के अंदर हम पार्कों के अंदर अभी तक वो जिमों का पता नहीं चल रहा है, कहाँ पे जिम लगे हैं, कहाँ नहीं लगाये गये हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है एमसीडी के अंदर नॉर्थ एमसीडी को...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं क्या करूँ? मैं चर्चा करवाऊँगा।

श्री सुरेन्द्र सिंहः नॉर्थ एमसीडी को मैंने...

माननीय अध्यक्षः कोई बात नहीं।

श्री सुरेन्द्र सिंहः नारायणा गाँव के अंदर टॉयलेट बनाने के लिए अनुरोध

किया। नारायणा गाँव के अंदर सीवी नारायणा के पुल के नीचे जन सुविधा के लिए टॉयलेट बनाये जायें, परंतु वो टॉयलेट अभी तक नहीं बना है।

साथ ही मेरे क्षेत्र के अंदर साउथ एमसीडी ने धौलाकुंआ के ऊपर बेहतरीन टॉयलेट बनाये हैं, परंतु उन टॉयलेट का अभी तक कोई उद्घाटन नहीं किया गया। मैं चाहूँगा उनका भी आपके माध्यम से हम... टॉयलेट का उद्घाटन किया जाये।

माननीय अध्यक्षः सुरेन्द्र सिंह जी कन्क्लूड कीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।

माननीय अध्यक्षः सुखवीर सिंह दलाल जी। ... भई राजेश जी हो गया प्लीज।

... (व्यवधान)

माननी अध्यक्षः नहीं, मैं राजेश जी, कुछ नहीं अलाऊ कर रहा हूँ। बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

श्री राजेश गुप्ताः राज्य सभा में संजय सिंह जी लिख के दे चुके हैं। इनके सांसद ने लिख के दिया, ये खुद कहते हैं कि जो चलने न दे संसद को उसकी सैलरी काटी जाये, उसका करा दिया तो यहाँ पर क्यों न कर लिया जाये?

माननीय अध्यक्षः बैठिए, प्लीज बैठिए।

श्री राजेश गुप्ताः सर, मेरा ये प्रस्ताव है, अगर इनसे पूछ लो आप कि जो ऐसे रोके, उसकी सैलरी रोक ली जाये। ये प्रस्ताव है, आप सारे

सांसद जो हमारे सदस्य हैं, उनके पूछ लें कि जो लोग इस तरीके से आके बार बार पंद्रह... एक महीना हो गया चलते हुए और रोज इसके अंदर कुछ चीजें एजेंडे लगे होते, जिसके ऊपर बात नहीं हो पाती। रोज तैयारी करके सदस्य आते हैं, उसमें बात नहीं कर पाते। ये बोलते रहे किसी ने सुना नहीं ढंग से कोई सुन नहीं पाया। जो बार बार विपक्ष के नेता या विपक्ष के सदस्य इस तरीके से करे, जो भी करे, उनकी तनख्वाह काटी जाये।

माननीय अध्यक्षः दलाल जी को अपनी बात रखने दें। सुखवीर सिंह दलाल जी। दलाल जी, बहुत कम समय में रखिये।

श्री सुखवीर सिंह दलालः मैं बोलूँगा ही नहीं, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः टू द प्वाइंट रखिये, टू द प्वाइंट।

श्री सुखवीर सिंह दलालः मैं अध्यक्ष जी, अब नहीं बोलूँगा। अध्यक्ष जी, पहले तो आपका धन्यवाद, पर सही बात आपने कहा दो टूक के मेरे पास दो वर्ड भी नहीं रहे। बताऊँ क्यों? मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा नंबर आये, मेरा नंबर आये, कुछ तो विपक्ष वाला ही टाइम खराब कर देते हैं, कुछ हमें मिलता नहीं।

माननीय अध्यक्षः चलिए, अब रखिये, आप बात रखिये।

श्री सुखवीर सिंह दलालः लेकिन बाय गॉड मुझे शर्म आ रही है। एक बुजुर्ग आदमी का इतना तो ख्याल कर लो, अभी आगे से मैं थोड़ा हाथ करूँ तो मेरे को बोलने दिया जाये। ये छोटे छोटे बच्चे के तरह...

माननीय अध्यक्षः करिये, करिये, जल्दी करिए।

श्री सुखवीर सिंह दलालः अध्यक्ष जी, मैं एक ऐसी विधान सभा से आता हूँ जिसका एरिया बहुत लंबा है और मैंने एमसीडी में है ना, कम से

कम 16 करोड़ रुपये जमा कराये होंगे पिछले तीन साल से लेकिन वहाँ काम के नाम पर मेरे पास पूरी डिटेल है, मैं इसको पढ़ के सुनाऊँगा तो आपको पता लगेगा, अभी वहाँ कितना पैसा जमा होने के बाद भी मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता।

माननीय अध्यक्षः इसको दो तीन आइटम पढ़ दीजिए। बाकी सदन पटल पर रख दीजिए।

श्री सुखवीर सिंह दलालः अध्यक्ष जी हमने, दो जगह किया हुआ है। नौ करोड़ और मैं इसलिए बोलने से वो हूँ...

माननीय अध्यक्षः वो देखेंगे, कोई बात नहीं अभी।

श्री सुखवीर सिंह दलालः अध्यक्ष जी, जो मैं मना कर रहा था बोलने के लिए, मैं वही मेरा आता है... न तो यहाँ कोई कमिश्नर बैठा, तो हम अपने वो चिल्लाके चला जाऊंगा तो मैं इससे अच्छा आपको चुप–चाप दे ही देता हूँ वो बहुत बढ़िया रहेगा। बस। नहीं तो अध्यक्ष जी, हम...

... (व्यवधान)

श्री सुखवीर सिंह दलालः बोलूँ या ना बोलूँ कुछ भी?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नरेश जी, भई, दलाल जी को...

श्री सुखवीर सिंह दलालः अध्यक्ष हेतु क्या बोलूँगा? अब कोई सुनने वाला भी नहीं। मेरे साथ तो ये हो गया अध्यक्ष जी, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई दलाल जी को बोल लेने दें। सोमनाथ जी, उनको तो बात तो रखने दीजिए।

श्री सुखवीर सिंह दलालः अध्यक्ष जी, मैं एक आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मेरे गाँव में रोड मैंने बनवा रखे हैं, सब कुछ मैंने खुद फ्लड डिपार्टमेंट से बनाया, लेकिन जब पानी की बारी आई तो एमसीडी का एक जेई आ जाता है और वो काम को रोक देता है। मैंने उनसे पूछा, ''भई, आपने यहाँ कोई काम नहीं करा रखा है, तो आप किस बात के वो है'' लेकिन फिर भी हमने आर आर जमा कराये हुए हैं। 16 करोड़ रुपये रुपये जमा कराये हुए हैं। पाँच करोड़ पीडब्ल्यूडी के, पीडब्ल्यूडी ने अपना काम कर दिया है, लेकिन एमसीडी का काम आज तक भी नहीं हुआ। मुझे अपनी 17 साल पुरानी बात याद आ रही है।

अध्यक्ष जी, मैं एक बार बीमार हो गया था बहुत सख्त और मैं हॉस्पिटल में था राजीव गांधी में।

माननीय अध्यक्षः दलाल जी, विषय को रख लीजिए।

श्री सुखवीर सिंह दलालः हाँ विषय को ही, वही रख रहा हूँ। उसी से रिलेटेड बात है।

श्री सोमनाथ भारतीः विषय तो अपनी बारीक ठीक हो।

श्री सुखवीर सिंह दलालः मैं बताऊँगा डाक्टर साहब, तो जब मेरा ऑपरेशन हुआ, तो डाक्टर साहब ने मुझे पूछा, मेरे पिताजी की दुआएं देकर अक भाई मतलब ये बताओ आप कोई नेता हो या मंत्री हो? मैंने कहा, ''क्या हो गया डाक्टर साहब?'' कहता है, ''भई, जब से आपका ऑपरेशन हुआ है, हर तीसरा आदमी लड़ने वाला सुखवीर दलाल का रिश्तेदार है।''

मैंने उनको समझाया, ''जी, मैं कोई मंत्री–वंत्री नहीं हूँ मैं तो एक सरकारी ऑफिसर हूँ पर गाँव में रहता हूँ जहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं। दस दस किलोमीटर तक जानते हैं कि मैं किसका लड़का हूँ'' चालीस की उम्र में उसको कैंसर हो गया, ये मेरी दुआएं हैं, लेकिन आज सत्तरह साल बाद मेरा पिताजी शोक में है... मुझे इस एमसीडी की तरफ से गालियाँ मिलती हैं। उसके लड़के ने या हमारी नाली खुदवा दिये हैं और कुछ नहीं हैं पानी की लाइन तो बिछवाने का भला दूर गया, लेकिन एमसीडी के तौर पे मेरे पिताजी को गालियाँ मिलती है। अक भई विधायक ऐसे फलाने का लड़का है, उसने साले ने वो बिछवा दिये हैं, सड़के पड़वा दिया, मैं इसलिए शर्म आ रही है अक एमसीडी के काम न करने की वजह से मुझे 17 साल पुरानी बात याद आ रही है। एक बार दुआएं मिल रहीं थीं, उसी बाप को आज गालियाँ मिल रही हैं, तो मैं एमसीडी से ये गुजारिश करूँगा कमिश्नर साहब से अक भई, मुझे एक बार बताया जाये कि ये मेरा पैसा कहाँ पे है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से करूँगा, एक मीटिंग कराई जाये कमिश्नर के साथ जो मुझे बताया जाये ये पैसा कहाँ पे है, कहाँ लगाया गया है।

माननीय अध्यक्षः दीजिए।

श्री सुखवीर सिंह दलालः इसके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः पवन कुमार जी।

श्री पवन कुमारः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग से अधिकारियों द्वारा जानबूझकर या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विधायक फण्ड से किए जाने वाले कार्यों को लंबित रखने या

करवाने संबंधी मामले पर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा में विधायक फण्ड से करवाने हेतु अनेक कार्य उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता के स्तर पर विगत दो तीन वर्षों से फाइलों में ही अटके पड़े हैं। कुछ गलियों के पुनर्निर्माण हेतु एस्टिमेट बनवाने के लिए मैंने 28/4/2017 को जेई को पत्र लिखा। उसके पश्चात् कई बार मौखिक रूप से बोला गया, किंतु आज तक नगर निगम के जेई महोदय ने एस्टिमेट जो है, नहीं बनाया।

ऐसे ही हमारे विधान सभा क्षेत्र में जनता द्वारा लगातार माँग करने पर विधायक फण्ड से छः ओपन जिम का जो है, प्रस्ताव किया 19/1/2017 को ये प्रस्ताव किया गया और 16/2/2017 को एस्टिमेट स्वीकृत भी कर लिया तथा स्वीकृत धनराशि अलॉट भी कर दी गयी। इसके बावजूद आज तक किसी भी पार्क में कार्य शुरू नहीं हुआ। पैसा स्वीकृत होने के पश्चात् जहाँ कार्य का टेंडर होना चाहिए, वहीं फाइल इस विभाग से उस विभाग के चक्कर काट रही है।

इसी प्रकार अम्बेडकर आवास, एमसीडी कालोनी में जहाँगीर पुरी में समुदाय भवन बनवाने संबंधी फाइल निगम विभाग, सिविल लाइन जोन में लम्बित पड़ी है। गौरतलब बात ये है अध्यक्ष जी, कि उपरोक्त सभी कार्यों को करवाने हेतु उपायुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कार्यालय में सभी सम्बन्धित अधिकारियों की उपस्थिति में मीटिंग भी हो चुकी है, डीसी साहब से। डीसी साहब, जगदीप छिल्लर जी से मीटिंग हुई परन्तु कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी। ऐसे मेरी विधान सभा में बहुत लम्बी लिस्ट है अध्यक्ष जी। तो इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत 35 से 40 काम कोई सड़क का निर्माण है। जैसे छः ओपन जिम हो गये। ऐसे बहुत काम लम्बित पड़े हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि महीने में कम से कम एक बार कमिश्नर

साहब... प्रत्येक, मेरे सभी साथी विधायक इस पर पीड़ित हैं, इस समस्या से... कमिश्नर साहब कम से कम महीने में प्रति विधान सभा एक बार एक घण्टा विधान सभा की समस्याएं देंख लें। विधायक के साथ एक बार बैठ लें। ये मैं आपसे जो है, अनुरोध करता हूँ।

और एक और मैं आपके ध्यान दिलाना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, कि गाँधी नगर की एक पार्षदा हैं जिसने अपनी गाड़ी नगर निगम के स्कूल में परमानेन्ट पार्किंग बनाके खड़ी कर रखी है। अपनी गाड़ी वो स्कूल में खड़ी करती हैं और लोगों की गाड़ियाँ जो हैं, गलियों से उठवा देती हैं। तो अध्यक्ष महोदय, ये तो काम का तरीका था। दूसरा मेरी विधान सभा में बहुत से जो है, अवैध निर्माण हो रहे हैं। कम्प्लेन्ट आती है लोगों की हमारे पास कि भई, पैसे माँग रहे हैं। बुढ़िया एक दिन आई। उसने 22 गज का अपना मकान कहीं से तीस हजार रुपया कर्जा ले के बेचारी ने एक कमरा बनाया और वो रोने लग गयी जो है आके कि मेरे से जो है, पचास हजार रुपया जो है जेई माँग रहा है। तो ये समस्या बहुत आ रही है और हम कहीं पत्र भी लिखते हैं, लैटर लिखते हैं कमिश्नर के नाम। मैंने एलजी साहब के नाम, कमिश्नर के नाम, एक्जिक्यूटिव इन्जीनियर के नाम लैटर लिखे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती।

तो अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया ये समस्याएं हमारी सुलझायी जाएं, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री जगदीप सिंह जी। अभी हैं तीन–चार बाकी हैं। मैं दे रहा हूँ।

श्री जगदीप सिंहः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। सर छः बातों में अपनी बात खत्म करूंगा।

सबसे पहली बात कि पूरी विधान सभा लगी हुई है। दिल्ली के महामहिम अध्यक्ष महोदय आप हैं। यूडी मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन बिना अनुमति के कमिश्नर और उनके ऑफिसर्स यहाँ से चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा अपमान है।

दूसरी बात कि एमसीडी बहुत बढ़िया काम करती है जी। ये लोग गलत कह रहे हैं। बहुत फर्स्ट क्लास काम करती है। ऐसी बात नहीं है लेकिन वो काम करती है सिर्फ पार्षदों का। वो विधायक के काम नहीं करती। ये जो गन्दी राजनीति का खेल है। ये जो गन्दी राजनीति का ये लोग खेल खेलते हैं, इस पर एक अंकुश लगाना पड़ेगा। एक बड़ी मीटिंग कि किस तरीके से हमें किस लिटीगेशन के अन्दर इनको लाना पड़ेगा ताकि ये ढंग से इसको काम कर सकें। क्योंकि आज से पहले ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से काम करते थे। जबसे आम आदमी पार्टी आयी है, इनको पता नहीं कौन सा साँप या बिच्छू काट गया है।

दूसरी बात, तीन करोड़ पन्द्रह लाख रुपये हमारे रोड रिपेयर चार्जेज हम लोग ने दिये हुए हैं सर। तीन करोड़ पन्द्रह लाख रुपये जहाँ पर पानी की लाइनें डालके उन रोडों को रिपेयर करना है, वो अभी तक रिपेयर नहीं हुई। तीन करोड़ पन्द्रह लाख रुपये इनके पास ये पड़ा हुआ है। ये पूरी रिपोर्ट है उसकी और ये मेरी विधान सभा के एमएलए फण्ड के काम हैं सारे जो कि 2016 से पेन्डिंग पड़े हैं। इनके ऑफिसर्स को बुला–बुला के हम लोग थक जाते हैं, वो आते नहीं हैं। दस तरह के बहाने मारते हैं और सबसे इम्पोर्टेन्ट और लास्टली एक जो बात है कि ये लोग डीडीए के पार्क, डीटीसी की जमीन, पीडब्लूडी के लैण्ड पर जो पैसा खर्च देते हैं डीडीए के पार्क में, इनको कौन अनुमति दे देता है? चार करोड़ रुपया मेयर ने अपने घर के सामने डीडीए के पार्क में खर्च दिया जिसके लिए हमने

एफआईआर भी करनी चाही लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया और उस पर बात करते हैं, एक्सईएन से, कोई जवाब नहीं है उसके पास। ये आप इसके ऊपर एक बारी आप गौर फरमायें।

दूसरा, लास्ट एण्ड फाइनल इम्पोर्टेन्ट थिंग इज कि हर साल जो डेंगू फैलता है, उसका अल्टरनेटिव ईयर जो है, वो बहुत भयानक होता है। एक साल हल्का रहता है डेंगू। एक साल डेंगू बहुत ज्यादा फैलता है। पिछले साल हल्का रहा है। इस साल डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा रहेगा। मेरा आपसे आग्रह है कि किसी तरीके से आप इनको बोल के, एक भी नाली इन लोगों ने अभी तक साफ नहीं की है। प्लीज दिल्ली की नालियाँ जरूर साफ कराएं ताकि किसी बच्चे के ऊपर आँच न आये, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, जगदीप जी। सुश्री अलका जी।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। आपने एक दिन का सदन बढ़ाकर नगर निगम और हमारे एमएलए लैड फण्ड से जो काम होने हैं, नहीं हो पा रहे हैं। उसे लेकर जबसे चर्चा शुरू की है, पूरा आपने एक और धन्यवाद कि लाइव जब से प्रसारण हो रहा है, हमारी क्षेत्र की जनता को भी समझ आ रही है कि क्यों हमारे विधायक पैसा देने के बावजूद भी एमसीडी से जो है, वो काम नहीं करवा पा रहे हैं। क्योंकि साफ है कि इसमें राजनीति आ रही है। जैसे अभी जगदीप जी ने बताया है कि अब कमिश्नर होते तो अच्छा था पर हो–हंगामा भाजपा के नेताओं ने किया कि किसी तरह एमसीडी के मुद्दों पर चर्चा न हो सके। सदन का समय बर्बाद हो। अन्तिम दिन है। आज दस मिनट के बाद अगर आप इजाजत देंगे तो सदन को कुछ घण्टे बढ़ाकर हम इस पर चर्चा कर पाएंगे, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः नहीं, लम्बा नहीं अलका जी, जो टू दि पॉइन्ट विषय रखिए।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, मैं छोटा ही बोलूंगी सिर्फ। जामा मस्जिद, मेरे वार्ड के आरडब्ल्यूए बहुत सक्रिय हैं और लगातार नगर निगम की समस्याओं को लेकर ही मुझे लिख रहे हैं। मैंने भी उन्हें लिखित में जानकारी दी है कि एमएलए का जो लैड फण्ड है, हमारे फण्ड से न तो स्कूल बनते हैं और न ही अस्पताल बनतें हैं। न पीडब्लूडी की सड़कें बनाती हैं। एमएलए लैड फण्ड सारा का सारा नगर निगम को हम लोग देते हैं। उनकी गली बनाने में, उनकी सड़कें बनाने में, स्ट्रीट लाइट लगने में, हाई मास्ट लगने में। मेरे यहाँ पर सबसे बड़ा उदाहरण है इनकी नाकामी का रानी झांसी फ्लाईओवर, 170 करोड़ से... 170 करोड़ में बनना था, आज बीस साल हो गये। 724 करोड़ लग गया। अध्यक्ष जी, मैं इसका जिक्र क्यों कर रही हूँ? एमएलए लैड फण्ड कहाँ से आता है? अध्यक्ष जी, इसके आस और पास जो रानी झांसी फ्लाईओवर के दोनों तरफ की सड़क है, वो नगर निगम के अधीन आती है। वो बीस साल से फ्लाई ओवर नहीं बना तो बीस साल से वो सड़क भी है, वो खुदी हुई हैं। लेकिन मैंने इन्हें 25 लाख दिया विधायक फण्ड से। एक साल तक अध्यक्ष जी, एक तरफ की तो सड़क इन्होंने दबाव में बना दी। दूसरे तरफ की सड़क आज तक नहीं बनाईं। अब ये मुझे कहते हैं कि फ्लाईओवर जब पूरा हो जाएगा, उस फ्लाईओवर में इस सड़क के दोनों तरफ का फण्ड लिया गया है। इसलिए हमें एमएलए लैड फण्ड से नहीं बनानी यानि कि दूसरी तरफ की सड़क बनायेगी। 25 लाख रुपये वापिस कर दीजिए और इस तरफ की सड़क का जो 25 लाख लिया है, वो रखकर ब्याज खा रहे हैं और अब ये कहते हैं कि अगर मैं दबाव दूंगी उस तरफ की सड़क बनाने के लिए... क्योंकि

मैं, हमारे लोग फ्लाईओवर का इन्तजार नहीं कर पा रहे हैं तो कहते हैं बजट दुबारा बनाना पड़ेगा। अब जो हैं, वो खर्चा ज्यादा आएगा। 25 लाख से ज्यादा का पैसा लगेगा। आप देख रहे हैं, इनकी हेराफेरियाँ। जिस तरह से कर रहे हैं। दूजाना हाउस में नगर निगम का पार्क है, अध्यक्ष जी। वहाँ के पार्क के लिए इन्हें झूले लगाने के लिए, पार्क कां सही करने के लिए दूजाना हाउस के लिए कहा, नहीं कर रहे हैं। पटौदी हाउस में अवैध पूरी तरह से रिक्शे, बिल्डिंग मैटीरियल, अवैध सारा अतिक्रमण है। एमएलए लैड फण्ड देने को तैयार हैं, अध्यक्ष जी, लगाने को तैयार नहीं हैं। वहीं सिविल लाइन में इनके जो भाजपा के जत्थेदार अवतार सिंह, पार्षद जीतकर आए हैं, अपने दफ्तर के बाहर उन्होंने एमसीडी से बेन्च और कुर्सियाँ लगवा ली है। बिल्कुल गली में सड़क पर कुर्सियाँ लगाई हैं, अपने दफ्तर के सामने। लेकिन जब मैं पार्कों में एमएलए लैड फण्ड के पैसा देकर हम कहते हैं कि एमसीडी के पार्कों में आप लोगों के बैठने के लिए उससे बेन्च लगाइए। वो हमें ये इजाजत नहीं दे रहे हैं। बरसों से हमारे लैटर जो जो हैं, वहाँ पर पड़े हुए हैं। कुछ सड़कें इन्होंने अवैध रूप से बन्द की हुई हैं। इसमें मैं आपको अध्यक्ष जी, उस सड़क का नाम आपको... जगत सिनेमा हाल से लाल किला एक सड़क जाती है। जिसको नगर निगम ने बन्द करके रखा है। मैं एमएलए लैड फण्ड देने को तैयार हूँ कि सड़क को खोल दीजिए लेकिन वहाँ अवैध अतिक्रमण करवाकर इन्होंने रेहड़ी–पटरियाँ लगाके पुलिस के साथ मिलकर एमसीडी ने उगाही का धन्धा बना लिया है।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करूँगी जामा मस्जिद वार्ड के आरडब्ल्यूए ने बहुत सी समस्याएं भेजी हैं। अगर हम यही कह रहे हैं, एमसीडी नहीं कर पा रही तो कृपया हमें इजाजत दें कि एमएलए लैड फण्ड से हम उन गलियों को जो है, दुरुस्त करा पाएं। हम डस्टबिन लगवा पाएं।

हम गलियों में स्ट्रीट लाइट लगवा पाएं। हाईमास्ट बन्द है, उसे लगवा पाएं। आपसे इजाजत यही है। मेरा ढ़ाई से तीन करोड़ रुपया सिर्फ जामा मस्जिद वार्ड का नगर निगम के पास पड़ा है। काम नहीं कर रहे हैं। सर सैयद अहमद रोड, बिल्कुल मेन रोड से अन्दर जाता है बाजार पूरा, खुदी पड़ी हैं। रोज रिक्शे पलट रहे हैं। पैसा दिया हुआ है, अध्यक्ष जी। जेई कहता है मेरे ऊपर पार्षद का दबाव है या नगर निगम का। काम नहीं हो पा रहे।

अध्यक्ष जी, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे इसका रास्ता, इस सदन में, इस सत्र में ही खोजने की कोशिश करिए। आगे बारिशों का मौसम आ रहा है, गड्ढे भरे पड़े हैं और बहुत बुरा हाल इलाकों का है। मच्छरों के छिड़काव के लिए भी हमने अपनी मशीनें खरीदीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने सौ–सौ रुपया मिलाकर एक टाइम पर एक हजार रुपया खर्च करते हैं और मच्छरों के छिड़काव का उपाय कर रहे हैं। आरडब्ल्यूए माँग कर रहा है लेकिन नगर निगम और डीसी मैडम से, कमिश्नर ने कभी समय नहीं दिया। बहुत बार उनके दफ्तर में फोन लगाया। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था; नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर हैं कौन? अगर उन्होंने समय दिया होता तो बाइ–फेस मिलकर यहाँ पर भी पहचान लेती, दूसरों से पूछना नहीं पड़ता। नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर कौन हैं लेकिन डीसी रुचिका कत्याल जी को बहुत बार फोन, मैसेज किए कि एमएलए लैड फण्ड का तीन से चार करोड़ रुपया नगर निगम को हम लोगों ने सड़कों, गलियों के लिए दिया हुआ है, खर्च क्यों नहीं हो रहा है, जवाब दीजिए। अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद, जयहिंद।

माननीय अध्यक्षः श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे एमसीडी के मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब यह डिस्कशन

एमसीडी के मुद्दे पर हो रहा है और कमिश्नर्स असेम्बली छोड़कर चले गए हैं। उनका यहाँ पर होना अनिवार्य था। ... (व्यवधान) अब यह छुट्टी उनके समय से थोड़े ही होगा। जब यह सदन पिछले 16 मार्च से चल रहा है और आज इतने सदस्यों ने अपने दुःख एमसीडी के ऊपर रखा है सदन के अंदर तो उनकी जिम्मेदारी थी कि सदन में होते।

अध्यक्ष महोदय, यह एमसीडी के ऊपर जो चर्चा चल रही है, उसका संवैधानिक रूप देखना बहुत जरूरी है। पार्ट 9–ए जो हमारे संविधान का है, उसके अंतर्गत म्यूनिसिपेलिटीज के ऊपर जो प्रोविजन्स हैं और साथियों को बता दूँ कि आर्टिकल 243 जेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत फाइनेंशियल एकाउंटबिलिटी एमसीडी की दिल्ली असेम्बली के प्रति है। कितना पैसा मिले, कहाँ खर्च करे, कैसे खर्च करे, एक–एक पैसे का ब्यौरा, एक–एक पैसे का दायित्व दिल्ली असेम्बली के प्रति है। तो क्या यह असेम्बली एमसीडी को पूछ नहीं सकती, क्यों नहीं हमारे काम कर रहे?

अध्यक्ष महोदय, ***Article 243(w) read with 12th schedule of the Constitution of India, categorically states, 'All those functions which are supposed to be done by MCD.'***

लेकिन जब हम कहते हैं और बाकायदा लिखकर कहते हैं, चिट्ठी भेजकर कहते हैं, मेरे पास भी चिट्ठियाँ हैं, लेकर आया हूँ आज। अध्यक्ष महोदय, मैंने आठ महीने पहले एक चिट्ठी भेजकर पूछा, ***"Kindly provide status of all the works against which funds from MLA LAD fund were paid to SDMC during my tenure as MLA, Malviya Nagar urgently."*** आठ महीने बाद भी चिट्ठी का जवाब तक नहीं आया, काम क्या करेंगे ये! मैंने पूछाकृ चूँकि हो क्या रहा था क्षेत्र के अंदर, सभी साथियों को इससे पीड़ित होना पड़ा होगा, हम स्ट्रीट लाइट लगाना चाह रहे हैं, बीएसईएस स्ट्रीट लाइट

लगा रही थी लेकिन वहाँ पर एक ईटीसी होता है। अब ईटीसी सदस्य एग्जिक्यूटिव इंजीनियर है। अब वो साइन न करे कि हम तो लगाएंगे स्ट्रीट लाइट एसडीएमसी के फण्ड से। हमने कहा, ''चलो, वही से लगा दो।'' ''तो वहाँ से तब तक नहीं लगेगा जब तक कि वहाँ के क्षेत्र के पार्षद की परमिशन न मिल जाए।'' सब कछ राजनीतिक हो रहा है, क्षेत्र के लोग कहते हैं विधायक को कि हमें स्ट्रीट लाइट चाहिए। ये कह रहे हैं, ''जी, हमें तो परमिशन नहीं है।''

अध्यक्ष महोदय, तो हमने बाकायदा पूछा कि यह बताओ, ***'Request for street lights pending with your office for over a year and against which fund from MLA LAD fund is already with you, why has it not happened?' To mujhe unofficially adhikari bolata hai ki because it has been rejected by Standing Committee.*** स्टेंडिंग कमेटी क्या है, स्टेंडिंग कमेटी एक पॉलिटिकल आर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल कमेटी है। तो यह जो जनता की पीड़ा को न देखते हुए जो जनता की समस्याओं के ऊपर राजनीति करते हैं, गली में अंधेरा रहे, महिलाओं के साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, वो एक्सेप्टेबल है, लाइट न लग जाए, सोमनाथ भारती के नाम से, लाइट न लग जाए विधायक के नाम से। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, अध्यक्ष महोदय। मेरे पास जो चिट्ठियाँ हैं, 361 लैटर्स हैं जो मैंने 05 मई, 2016 से यह लिखा है दिसम्बर, 2016 तक ***and none of the letters have been responded. Forget about acting upon each other letter.*** यह है हाल। उस दिन सौरभ भाई बता रहे थे, इस सदन के अंदर कि इनके पास एक ऑर्डर है, ऑफिस ऑर्डर जिसके तहत् सभी अधिकारियों का दायित्व है कि हमारी भेजी गई चिट्ठियों का जवाब दें तो इसमें से तो एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। तो क्या एक्शन लें इनके खिलाफ?

अध्यक्ष महोदय, हमने कुछ नहीं तो पिछले तीन साल में, जब से जनता ने हमें विधायक बनाया है, मोर देन थाउजेंड लैटर्स मैं सेंड कर चुका हूँ लेकिन चिट्ठियों का जवाब तक नहीं आया तो हम जनता को क्या जवाब दें? मुझे इसे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि कारण एक है, एमसीडी के अंदर भाजपा का राज है। दुर्भाग्यवश भाजपा दो बार दिल्ली को नरक बनाने के बावजूद तीसरी बार भी भाजपा एमसीडी में आ गई।

इनफेक्ट वो मैं साथियों को बताना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाई कोर्ट ने चूंकि कई बार सदन में चर्चा उठी, हमने कहा कि अगर प्रॉपर्टी विभाग एमसीडी से ले ली जाए तो कोई भी आदमी काउंसलर नहीं बनना चाहेगा। सारा माल तो प्रोपर्टी विभाग में है। कितने फ्लोर बने, कितने लाख आए, कितने लाख लेने हैं, पूरी दिल्ली जो नरक बनाया है जिसके कारण आज ट्रेडर्स को भुगतना पड़ रहा है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन्स हुआ है और जिसके तहत् काउंसलर जो साइकिल पर आए थे और मर्सिडीज पर निकले हैं, उनके खिलाफ संज्ञान में लेने के लिए कोई भी नहीं है। अगर आज एसीबी होती, अगर एंटी करप्शन ब्रांच होती, हमारे गृह मंत्री यहाँ बैठे हैं तो मुझे लगता है कि 60–70 परसेंट काउंसलर इनके जेल में होते। उसी डर के मारे इन्होंने हमसे एसीबी छीन लिया। हाई कोर्ट का आब्जर्वेशन है, कहते हैं, हाई कोर्ट ने एक पीआईएल के दौरान कहा, ***'Delhi High Court today directed Municipal Corporation to give details of the number of properties in the jurisdiction date Of sanction of building plans and the date when completion certificate were issued for each one of them.' Aur kab kaha yah, bench of acting Chief Justice Geeta Mittal, Justice C Hari Shankar issued directions while observing that***

Municial Corporations were responsible for allowing illegal constructions to reach such a stage where nothing can be done about it. Aur court ne poocha hai, "Can you demolish all the unauthorized constructions in entire Delhi? The bench asked and added that the area was located in sensitive seismic zone where an earthquake of even five magnitude on the richer scale could cause huge loss of life and widespread damage."

लेकिन इनको शर्म नहीं आती। कोर्ट कह रहा है, आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं, सब कह रहे हैं लेकिन इनको शर्म नहीं आती। इनको शर्म कैसे आए, यह समझ में नहीं आ रहा, अध्यक्ष महोदय। दिल्ली के अंदर चिकनगुनिया फैलता है, डेंगू फैलता है लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, स्ट्रीट लाइट के ऊपर इतनी राजनीति की है इन लोगों ने, मेरे क्षेत्र के अंदर डेढ़ साल हो गया है हम स्ट्रीट लाइट के लिए लिखे जा रहे हैं कि हमारा स्ट्रीट लाइट लगा दो। फण्ड भी ले लिया है। लिखित में मेरे पास सारे डाक्युमेंट हैं अध्यक्ष महोदय। फण्ड भी ले लिया है, क्षेत्र के अंदर लोग त्राहि–त्राहि कर रहे हैं कि उनको स्ट्रीट लाइट चाहिए लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं लगा रहे और करते क्या हैं! मेहनत करते हैं हम, लोकेशन्स इकट्ठा करते हैं हम और ये उन स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर काउंसलर का नाम लिखना चाहते हैं। मुसीबत यह है। क्षेत्र के अंदर डस्टबिन्स की डिमांड है उस पर हमने फण्ड दे रखा है, बेंचेज की डिमांड है, उस पर फण्ड दे रखा है। ड्रेन्स को साफ करना है हमने लिखित में अध्यक्ष महोदय, जो चिट्ठियाँ दी हैं... अभी बारिश का सीजन आने वाला है, लिखकर दिया है कि ***In furtherance to my oral and written requests that the mess during***

rainy season gets created because of intermixing of severage and drainage and there is no proper drainage system across my constituency particularly in the areas inside the colonies due to which rainy water get severely inserted into the available sevage lines.

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, अब कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, ***It is on only in violation of various laws and guidelines but is also detrimental to long term interest of underground water level.*** लेकिन चिट्ठियाँ लाख लिख दो, एमएलए लैड फण्ड लाख दे दो लेकिन ये काम करके राजी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके थ्रू कमिश्नर को बताना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र के अंदर एक रोड है; निरंकारी स्कूल से लेकर गोल चक्कर तक। अब यह रोड पिछले तीन साल से नहीं बना रहे हैं तो यह जब लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं बना तो ये लोगों को बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडी का रोड है। अब हमने पीडब्ल्यूडी से लिखवा कर दिलवा दिया कि पीडब्ल्यूडी की रोड नहीं है तो ये कहते हैं कि हमारे रिकॉर्ड में तो पीडब्ल्यूडी का रोड है। अब ये कैसे मैच करें! पीडब्लूडी ने जब लिखित में दे दिया के भई, पीडब्लूडी का रोड नहीं है एमसीडी का रोड है, ये उसके बावजूद ये मानने को तैयार नहीं हैं। तो कमिश्नर साहब यहाँ पर नहीं हैं। नहीं तो मैं उनको बताता मैं यहाँ पर।

अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल आया हमारे इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट ने चूंकि जब हमने एक हौजखास एसएफएस फ्लैट्स के अंदर ये चाहा कि उनकी बाउंड्री वाल बन जाए तो इन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया कि भई, हम एनओसी नहीं देंगे। ''अच्छा जी।'' हमने

कहा, ''भई, तुम पैसे ले लो फिर।'' 25 लाख रुपये दे दिये इनको। 25 लाख लेकर के इन्होंने डेढ़ साल बैठे रहे, एनओसी नहीं दिया। उसके बाद हमने क्या किया जैसा कुछ लोग मुझे जानते हैं, इस नेचर का हूँ। मैं मैंने कहा कि भई एनओसी के बगैर काम करो। तो इरिगेशन एण्ड फ्लड से बगैर एनओसी के काम कराया हमने और वो जो दीवार बनकर उभरी है, पूरे क्षेत्र में एक मिसाल है। तो दिल्ली सरकार का इरिगेशन एण्ड फ्लड डिपार्टमेंट जो दीवाा बनाया है, वो ऐसा मिसाल बनकर उभरा है कि क्षेत्र की जनता कह रही है कि भई, हमको तो एमसीडी से काम ही नहीं कराना है। अभी स्थिति उभर के आ गई। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार ईमानदार हो तो सारे काम हो सकते हैं और ये मेरे सरकार के कुछ डिपार्टमेंट्स ने मेरे क्षेत्र में करके दिखाया और इसके लिए मैं अपनी सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और साथ में आपके जरिए ये बताना चाहता हूँ कि जो चिट्ठियाँ विधायक भेजता है, वो अपने ऑफिस ऑर्डर के इंस्ट्रक्शन्स के माध्यम से मैक्सिमम विद इन वन वीक उसका रिस्पांस आ जाना चाहिए। आप ये अपने ऑफिस से ऐसा आदेश दें कमिश्नर्स को और एमएलए के साथ मंथली मीटिंग हो और जो भी एमएलए लैड फंड्स के साथ हमने रिक्वेस्ट भेज रखी है वर्क्स के लिए, वो टाइम बाउंड उसका एग्जीक्यूशन हो।

अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी मुसीबत जो हर तरफ आ रही है कि कुत्तों की समस्या जो हमने पहले भी सदन के अंदर कहा था मैं फिर से उठाना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग बहुत प्रभावित हैं इससे, बहुत आतंकित हैं इससे। कुत्तों और बंदरों की समस्या पर एमसीडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है और मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूँ एमसीडी के, कि भई, ये बहुत ही भयावह समस्या बन गई है दिल्ली के अंदर इस

पर आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इन्हीं शब्दों के साथ और जो लैटर्स मैं सारे लेकर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए मैं उन तक पहुँचा दूँ और मैं सदन के पटल पर रख दूँगा। ये सारी चिट्ठियाँ वहाँ पर पहुँच जाएं जिससे कि इसका जवाब समयानुसार आ जाए और हमारे क्षेत्र के अंदर कुछ काम हो सके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री इमरान जी।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री इमरान हुसैन): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे अपने एरिये का मुद्दा उठाने एमसीडी से जो आज पुरानी दिल्ली जो है, पूरा वाल्ड सिटी में जितना भी काम होता है, चाहे वो सड़क का हो, स्ट्रीट लाइट का हो, जो भी काम होता है, वो सारा एमसीडी द्वारा ही किया जाता है और पिछले दो तीन साल से गलियों में अंधेरा पड़ा है। पिछले दो साल से स्ट्रीट लाइट्स का बहुत बुरा हाल है। सिर्फ एमसीडी जो आज काम कर रही है वाल्ड सिटी के अंदर, वो सिर्फ एक काम कर रही है कि जहाँ जहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं, वहाँ वहाँ इनके जेई, एई यहाँ तक कि डीसी, कमिश्नर सब लोग राउंड लेते हैं, खूब राउंड लेते हैं और सिर्फ इन्होंने बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया हुआ है। एक तरीके से ये कंस्ट्रक्शन एजेंसी बन गई है। अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग्स बनाने की और इन्होंने इलाके में बाकी जो काम हो रहा है, आज मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि आप वाल्ड सिटी के अंदर कमिश्नर को यहाँ से आदेश दें कि जिस तरीके से उनके जेई, एई बिल्डिंगों पर जाते हैं, इसी तरह रात के टाइम गलियों में घूमकर ये चैक करें कि गलियों में अंधेरा पड़ा है सारा। ये सारी स्ट्रीट्स लाइट्स खराब हैं और मैं पिछले दो साल से... एक बार मैंने बीएसईएस को बोला। एमसीडी को बोला पहले मैंने कि मेरे एरिये में लगभग 600 लाइटों की जरूरत है, लाइटें लगा दो।

तो उसके बाद मैंने रिटन में उन्हें दिया, उन्होंने कहा हम लगा देंगे, बीएसईएस ने मुझसे कहा। उसके बाद बीएसईएस और एमसीडी की एक कमेटी बनी हुई है। उसके अंदर वो प्रपोजल गया और उस प्रपोजल को एमसीडी के अधिकारियों ने उसमें बैठकर नकार दिया कि ये प्रपोजल नहीं लगाएंगे क्योंकि एमसीडी के अंदर जो है, अब हम ये जितनी भी पुरानी लाइटें लगी हैं, इसको एलईडी के लिए हम चेंज कर रहे हैं और इसलिए ये प्रपोजल नहीं लगाएंगे। उसके बाद फिर मैंने एक दो सौ, ढ़ाई सौ लाइटों की रिक्वीजीशन एमसीडी के एक्सईएन को दी और ये बात कमिश्नर को भी पता है जो पहले कमिश्नर थे, उन्हें भी और पिछले छह महीने से पैसा गया हुआ है उनके पास और आज तक मैं जब भी फोन करता हूँ या जब भी बुलाता हूँ एक तो एक्सईएन नहीं आता, किसी जेई को भेज देते हैं और वो उसके बाद में उनसे बात होती है तो कहते हैं कि दस पन्द्रह दिन में आ जाएंगी। आज कसाबपुरा, बाड़ा मेरा जितना एरिया है, लगभग अगर रात को कमिश्नर राउंड ले लें या जेई, एई राउंड ले लें तो अंधेरा मिलेगा और ये खाली मेरे एरिये का हाल नहीं है ये अलका जी का एरिया है, जामा मस्जिद, मटिया महल, सदर बाजार का जितना एरिया लगता है सबका यही बुरा हाल है और एक अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। लाल कुँआ, हौजकाजी, चावड़ी बाजार, नई सड़क, बल्लीमारान मेन रोड, कुतुब रोड, लाहौरी गेट रोड, सिंगाड़ा चौक और ईदगाह रोड, रामकुमार मार्ग, सब पे इतना ज्यादा एन्क्रोचमेंट है कि जब स्कूल से दोपहर को बच्चे आते हैं तो एक एक घंटा उन्हें जाम में खड़ा होना पड़ता है। जिस बच्चे को दो बजे एक बजे छुट्टी होने के बाद दो बजे घर पहुँचना चाहिए, वो चार चार, पाँच पाँच बजे तक जाम में फंसे रहते हैं और यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी होने की वजह से दुकानदारों ने लगभग 8–8, 10–10 फुट तक बाहर निकाल रखा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जाम रहता है और लाइसेंस विभाग

को बार बार मैं बुलाता हूँ मीटिंग भी करता हूँ इन्हें आदेश भी दिये जाते हैं। जिस दिन हम लोग राउंड रखते हैं, उस दिन ऑटोमैटिक साफ मिलता है और राउंड के जैसे ही हमारा राउंड... अगर कभी हमने राउंड किया और खत्म होता है, उसके 10–15 मिनट बाद ही वहाँ फिर वहीं अतिक्रमण हो जाता है और इसके साथ साथ जो हम लोगों का क्योंकि पुरानी दिल्ली के अंदर वाल्ड सिटी के अंदर सारा का सारा काम जो है, वो विधायक निधि का होता है। एमएलए फण्ड का जो होता है, वो एमसीडी द्वारा ही किया जाता है। उसके न फ्लड से करा सकते हैं हम लोग, न डीएसआईआईडीसी वहाँ कोई काम करता है। तो इसकी वजह से हमें बहुत एस्टिमेट बनवाए हुए एक एक साल हो गये हैं और उन पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है और इसकी वजह एक और भी है पिछले 10–10, 15–15 साल से वो ही एई, जेई, एक्सईएन वहाँ नियुक्त हैं और वो लोग खुद काम करना भी नहीं चाहते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि कम से कम अध्यक्ष महोदय, स्ट्रीट लाइटों के लिए तो कमिश्नर को यहाँ से आदेश देना चाहिए कि वो खुद राउंड लें क्योंकि रात को बहुत लूटपाट के मामले वहाँ अब होने लगे हैं, बिल्कुल अंधेरा पड़ा है, शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय मंत्री जी श्री सत्येन्द्र जैन जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय सदस्य जो सभी ने अपने विचार रखे, कल से अपने रख रहे हैं, मैं सुन रहा था ध्यान से। सबसे पहले अध्यक्ष जी, एक छोटी सी कहानी सुनाऊँगा मैं। 'एक चिड़िया थी,

... (व्यवधान)

माननीय शहरी विकास मंत्रीः दोबारा सुना देता हूँ, काम आएगी। मैं आपके यहाँ गया था, इसलिए सुनाई थी। इस सभा में न जिसके जो भी मुझे बुलाते हैं वहाँ पर जरूर सुनाकर आता हूँ। सच्ची बात है वैसे... चिड़िया अपने काम में लगी रहती थी। तो चिड़िया ने कहते हैं, फसल बोई सारी मेहनत करी। जब छः महीने में फसल पककर तैयार हो गई, उसने इकट्ठी कर ली। सब कुछ तैयार होने के बाद कौआ और चिड़िया दोनों थे, कौआ आकर बैठ गया काँव काँव कहते हुए कि ये तो मेरा है। इस सदन के अंदर बैठे हुए ज्यादातर सदस्य बता सकते हैं कि जितनी मेहनत से ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे कामों के ऊपर जाके कुछ कौआ रूपी लोग हैं, वो जाकर कहते हैं हमने किया, हमने किया, हमने किया... काँव काँव करते रहते हैं।

श्री सोमनाथ भारतीः हैडलाइन बनने वाला है जैन साहब।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः हाँ, बन जाएगा। हाँ, तो क्या है, मैं ठीक कह रहा हूँ। अरे! मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप के कितने पार्षद हैं, बने हुए उनको तीन दिन नहीं हुए थे तीसरे दिन कहते हैं मैंने पटरी बनवा दी, मैंने ये करवा दिया जब कि उनके यहाँ पर एक एक साल तक तो कुछ होता ही नहीं है। पहले महीने में ही उन्होंने अपने बोर्ड लगवाने चालू कर दिये और कुछ नहीं किया कि जी, मैं ये करवा रहा हूँ।

मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। हमने बहुत सारे जिम और प्ले स्टेशन लगवाये। कुछ लोगों के नहीं लग पाए, मेरे यहाँ लग गये थे क्योंकि मैंने एक साल पहले स्टॉर्ट किया, मैंने ही सबसे पहले स्टॉर्ट किया था। नहीं–नहीं, मैंने सबसे पहले स्टॉर्ट किया, इसलिए लग गये थे। तो जब वो लगे इतने बड़े बड़े हर्षवर्धन जी की फोटो लगा दी उसके ऊपर। काउंसलर ने अपनी फोटो लगा दी। कहते हैं जी, हम जिम लगवा रहे हैं। मैंने कहा, ये कमाल

हो गया यार! आज तक तो जिम का इन्हें पता नहीं था, जिम होता क्या है और ये काउंसलर जीत के आये हुए उसको जुम्मा जुम्मा चार दिन हुए नहीं और ये आज से लगवाने लग गया। तो ये इस तरह के हालात सभी विधानसभाओं में कमोवेश कम या ज्यादा हैं। लाइट लगवाएंगे सोमनाथ जी। तो वो आकर कुछ नहीं करेंगे, नाम जरूर अपना लिख जाएंगे। आपने जाकर पार्कों में जो बेंच लगवाई थी, चैक कर लेना उनमें नाम चेंज कर चुके होंगे वो। देखो, उधर बता रहे हैं। मतलब ज्यादातर जाकर चैक कर लीजिएगा, नाम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। तो ये प्रवृत्ति का फर्क है। तो चिड़िया की प्रवृत्ति काम करने की और कौवे की प्रवृत्ति काम न करके उसके ऊपर कब्जा जमाने की है। अभी बात चल रही थी... लास्ट, फिर वापस आता हूँ। पहले कि जी, अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन कराते हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि एमसीडी का कोई काम ही नहीं बचा। सर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी अगर एक वर्श में या एक महीने में करोड़ों रुपये कमायेगा। तो उसका ये एमएलए फण्ड में या काम में मन लगेगा ये करने में? हमारे सदस्य... मुझे लगता है कि गलत बात के लिए उत्तेजित हैं। भई, आप कितने का काम करा लोगे साल भर में? एक करोड़ रुपये का करा लो मुझ से काम और वो कितने लोग हैं? एक करोड़ तो एक महीने में कमा लेते हैं। एक आदमी... सबकी बात नहीं कर रहा। अभी आपके यहाँ बहुत सारे पार्षद चुने गए हैं। पार्षद को बने हुए एक साल भी नहीं हुआ। मेरे यहाँ पर एक पार्षद हैं, रानी बाग में रहा करते थे। तीन महीने में सैनिक विहार पहुँच गए। नहीं सैनिक विहार नहीं, कोठियों में पहुँच गए। तो मतलब ये देखो, तरक्की का स्टाइल देखिएगा उनका। मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि करप्शन का जो लेवल है, आप अन्दाजा नहीं लगा सकते। बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो काम करता है, कैसे करप्शन होता है। दिल्ली के अंदर हर साल लगभग 60 हजार मकान जो पुराने बने हुए है, टूट कर

दोबारा बनते हैं। पूरी दिल्ली के अंदर 30 लाख मकान हैं। अगर 30 लाख मकानों में जो दो परसेंट मकान भी दोबारा से बनते हैं, जो पुराने बन चुके हैं, किसी को 50 साल हो गए किसी को 60 साल हो गए किसी को 70 साल हो गए। मैं कन्जर्वेटिव एस्टीमेट बता रहा हूँ। साठ हजार मकान वो होते हैं और दिल्ली में लगभग 40 हजार मकान फर्स्ट टाइम बनते हैं। और एक भी मकान दिल्ली में ऐसा नहीं है जिससे एमसीडी या पार्षद या इनके गुर्गे पैसे न लेते हों और रेट बता देता हूँ आपको मैं। दो सौ गज के प्लाट का रेट 2 लाख रुपये लैंटर। पाँच लैंटर डलते हैं जी, आजकल एक स्टिल्ट का ऊपर चार। तो दस लेते हैं पीतमपुरा के अंदर, रोहिणी के अंदर आपके शालीमार बाग में, यमुना पार में दो सौ गज का दो लाख। सर आगे आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। और साउथ दिल्ली का रेट आप सुन लीजिए... अलका जी, सुन लीजिए। साउथ दिल्ली का रेट डबल है। अगर वहाँ पर पाँच सौ गज की कोठी बनती है तो दस लाख रुपये लैंटर का रेट है।

... (व्यवधान)

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अरे! सर आपको नहीं पता। आप इलाके में नहीं रहते, इसका मतलब। और गाँधी नगर जैसी जगह जो है, वहाँ पर पचास गज के प्लाट का रेट अगर वो बनाएगा चार मंजिल, पाँच मंजिल बनाता है तो कम से कम 10–15 लाख रुपये देने पड़ते हैं उसको। तो वहाँ पर चार गुना रेट है... तीन गुना रेट है। और जो अनऑथोराइज्ड कालोनीज हैं, अनऑथोरोइज्ड रेगुलराइज्ड कालोनी जितनी भी हैं, उसका रेट भी यही हुआ करता था। पहले गज के हिसाब से रेट होता अध्यक्ष जी। वो कहते हैं, ''जी, हजार रुपये गज।'' आपका तो दूर है इसलिए हजार रुपये रेट है। तो अंदर वाले एरिया हैं, अब उनके रेट कर दिये दो हजार

रुपये गज। पचास गज का प्लाट अगर रानी बाग में बनता है तो एक लाख रुपये लैंटर लेते हैं। पहले पचास हजार रुपये लेते थे। अबकी बार ये ईमानदार लोगों को लेकर आएं है इसलिए रेट डबल कर दिये है यहाँ पर। सर जी, इस लिए बैकग्राउंड बता रहा हूँ। जिस दिन एसीबी आ गई, करूँगा, बिल्कुल। मैं इस लिए ऑन रिकॉर्ड सब के सामने कह रहा हूँ, ये करप्शन है और जिनके हाथ में ये पॉवर है, उसको बंद करना चाहिए। नहीं तो इसका मतलब वो भी लेते हैं हिस्से। उनके पास भी हिस्सा जाता होगा। दिल्ली के अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का ही कम से कम

कन्जर्वेटिव एस्टीमेट बता रहा हूँ पाँच हजार करोड़ रुपया रिश्वत है सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंगों की। मैं पाँच लाख रुपये लगा रहा हूँ एवरेज। गाँधी नगर में 15–20 लाख रुपये हैं, साउथ दिल्ली में पचास लाख रुपये रेट है और शालीमार बाग में 20 लाख रुपये रेट है। तो अलग–अलग रेट लगा हुआ है। इनके यहाँ तो कमाल ही है! चाँदनी चौक में तो पचास गज का अगर है तो 20–25 लाख रुपये ले लेंगे। नहीं पचास गज की बात कर रहा हूँ। पचास गज के पचास लाख रुपये चांदनी चौक में। वो कमर्शियल पर आ रहा था... रेजिडेंशियल की बात कर रहा था। मैं कमर्शियल पर आ रहा हूँ। इसके बाद कमर्शियल एक्टिविटी है। जहाँ पर अगर चाँदनी चौक में कमर्शियल दुकानों को बना रहे हैं खाली खाली दुकानों को चार मंजिल उठा कर रख देते हैं ऊपर। नीचे दुकान बनी रहती है, ऊपर चार मंजिल ले जाते हैं। पता नहीं क्या टैक्नोलोजी बनाई इन्होंने। मैं आप ही लोगों से पूछ कर बता रहा हूँ। किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया है। आप ही का ज्ञान में बता रहा हूँ। और कमर्शियल प्रापर्टीज के अंदर 20 लाख से लेकर 50 लाख से लेकर एक–एक करोड़ दो –दो करोड़ रुपये तक लेते हैं फार्म हाउसेज के अंदर। एक–एक करोड़ से तो चालू होता

हे रेट इनका। एक करोड़ रुपये दे दो जी चलो बना लो बनाना है तो। अभी कह रहे है कि कम्पलीशन की लिस्ट मांगी है इन्होंने कि जी आपने नक्शे कितने पास किए और कम्पलीशन कितने किए हैं। पहले भी बात तो ये किसी भी कोर्ट को कुछ देने वाले हैं नहीं। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं चिकना घड़ा और जो दूसरी बात कह लीजिएगा यह शब्द तो अच्छा नहीं है पर गैंडे जैसी खाल वाले लोग हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पडता। ये किसी को कोई जवाब देने वाले नहीं है और मैं आपको बता रहा हूँ जवाब क्या है। दो परसेंट लोगों को कम्पलीशन नहीं देते ये। दिल्ली में जितनी भी प्रोपर्टीज एमसीडी के अंडर आती हैं, अगर रेजिडेंशियल प्रोपर्टी 25 लाख एमसीडी के अंडर है तो 25 लाख में से आज तक एक साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आज तक एमसीडी ने पचास हजार लोगों को कम्पलीशन नहीं दिये हैं क्योंकि ये पैसे खाते हैं, कम्पलीशन देते नहीं है ये। अगर एक आदमी महीने के अंदर करोड़ो रुपये इकट्ठे कर रहा है और प्रोटेक्शन मनी ऊपर तक जा रही है तो मुझे लगता है एमएलए फण्ड के अंदर इनका इन्टरेस्ट होना या ना होना स्वाभाविक है। वो पैसा कमाने की इण्डस्ट्री में लगे थे और उसमें लगे हुए हैं। अभी कह रहे थे कि भई, एमसीडी के अंदर बीजेपी का राज है। नहीं, मैं इसे ठीक कर दूँ, करैक्शन कर दूं। एमसीडी में बीजेपी का राज कतई नहीं है, एमसीडी में भ्रष्टाचार का राज है। जो कि क्योंकि बीजेपी भ्रष्टाचारी है इसलिए बार–बार वो आते हैं। तो बीजेपी से भ्रष्ट डिपार्टमेंट मैं तो गारंटी से कह सकता हूँ, इस देश में नहीं, इस धरती के ऊपर संसार के अंदर कोई डिपार्टमेंट एमसीडी से ज्यादा करप्ट नही है। अगर इस देश के राष्ट्रपति भी किसी की अप्रोच लगा दें। प्रधान मंत्री जी खुद किसी की अप्रोच लगा दें कि भाई साहब, मेरे रिश्तेदार का मकान बन रहा है इसको छोड़ दो। छोड़ तो देंगे पर बता कर जरूर आएंगे, ''भाई साहब, दस लाख का काम था, फ्री में कर रहा हूँ। प्रधान मंत्री का

फोन आया था इसलिए और फाइल में वो भी लिख देंगे। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये सब चीजें, ये ऐसे करते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, एमसीडी का जो कल्चर है, एमसीडी का जो सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर पनप रहा है। जैसे नाली का गंदा पानी होगा तो कीड़े उसी में ही पलते हैं, साफ पानी में नहीं पलते हैं। और ये भ्रष्टाचार उसकी गंदगी की वजह से पनप रहा है। क्योंकि बीजेपी के पास पिछले बारह साल से था, पाँच साल के लिए और मिल गई तो इन्होंने गंदगी इतना बढ़ा दी है। तो इन कीड़ों को आगे मौका मिल रहा है फलने फूलने का। तो ये भ्रष्टाचार कौन करता है... कि ये पार्षद करते हैं कि इन्जीनियर करते हैं। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जो मैंने लोगों से बातचीत की है 40 : 60 का बता रहे है जी। कोई कहता है 50 : 50 कोई कहता फोर्टी:सिक्सटी। फिफ्टी:फिफ्टी में कोई झगड़ा हीं नही रहता। फोर्टी:सिक्सटी में झगड़ा है। कुछ सदस्य कहते हैं, ''सिक्सटी परसेंट पार्षद का होता है।'' कुछ कहते हैं, ''नहीं जी, पार्षद का चालीस होता है और अफसरों का साठ होता है।'' चलो, जो भी हो, चालीस परसेंट तो पार्षद का भी है कम से कम। उसमें कोई झगड़ा नहीं है। चालीस परसेंट से कम पार्षद को किसी को नहीं मिलता। और जितने भी पार्षद इस बार ईमानदार आए थे, इन्होंने एक नारा लगाया था, ''सारे भ्रष्टों को हटा रहे हैं, ईमानदारों को ला रहे हैं।'' जो साईकिल वाले थे, स्कूटर वालों को तो मैं जानता हूँ जी, मेरे यहाँ स्कूटर वाले थे, गाड़ी पर तो आ गए। ये पाँच साल के अंदर हवाई जहाज में नजर आएंगे सारे के सारे। जितने भी पार्षद हैं, मेरा अपना

कन्जर्वेटिव एस्टीमेट है पाँच साल के अंदर जो ज्यादा गड़बड़ नहीं करता, वो पार्षद 25–30 करोड़ कमाता है। जो ठीक ठाक है, पचास करोड़ रुपये और जो बदमाश है, सौ करोड़ रूपया। शिवचरण जी, गलत तो नहीं

कह रहा? जो सीधा साधा है पच्चीस करोड़, ठीक ठाक है, पचास करोड़ और जो बदमाश है, सौ करोड़ रुपये पाँच साल के अंदर कमाता है। इस वजह से वो बेचारे जेई भी डरते हैं उनसे। पैसे का पॉवर है ना उनके पास। पैसे की ताकत है। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, ''कोई इस देश का मंत्री भ्रष्टाचार के बारे में कभी ऐसे बोल नहीं सकता।'' टैक्नीकली एमसीडी मेरे अंडर आता है। मैं जवाब दे रहा हूँ ना एमसीडी का। मैं कह रहा हूँ, ''भ्रष्ट हैं सारे के सारे। पैसे खाते हैं।'' मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अरे! किसी की तो आँख खुले, कोई तो माने। मैं कह रहा हूँ ना, ''हाँ जी, पैसे खाते हैं। ये रेट बता रहा हूँ, सारे के सारे रेट बता रहा हूँ।''

माननीय अध्यक्षः चलिए, कन्क्लूड करिए, प्लीज।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, एमसीडी को बनाया गया है और इतने सालों से संरक्षण दिया गया है नेताओं के द्वारा, इसलिए कि वो पैसा कमा कर देते हैं। और एक चीज और भी है जो कमाऊ पूत होता है, वो प्यारा भी होता है। ये बहुत कमाऊ पूत हैं उनके। तो इन कमाऊ पूत को छोड़ नहीं सकते। उनके ऊपर ये सख्ती कर नहीं सकते। इस सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन दिल्ली सरकार के पास ये पॉवर आ गयी, जो पहले हुआ करती थी, एसीबी जिस दिन दिल्ली सरकार के पास आ गयी, इनके पैसे कमाने बंद कर देंगे एक दिन के अंदर... 24 घंटे के अंदर। पैसे की बंदरबांट नहीं होगी। अभी सदन में काफी सारे सुझाव मिले हैं। मुझे जो लगता है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो एमएलए फण्ड का कोई भी प्रपोजल है, अक्सर क्या कर रहे हैं लोग... एमएलए ने कोई भी प्रपोजल दिया तो तुरंत लेके, ''जी,'' कांउसलर को देते हैं पहले तो ये। अफसर की हिम्मत नहीं है उसपे एस्टिमेट बना

दे और वो कांउसलर क्या करता है जाता है सीधा अपने एमपी साहब के पास, ''सर जी, सर जी, थोड़ा सा पैसा दे दो।'' सड़कों के लिए नहीं देते परन्तु उसके अलावा कोई भी काम आप करा लो तो सीधा एमपी के पास जायेगा। कहता है, ''हाँ, मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैंने तो चार साल से पिछले खर्च ही नहीं करे हैं।'' चौथा साल है। उसका एक रुपया नहीं लगाया उन्होंने। और मिलते कितने हैं एमपी को? छः करोड़ रुपये। तो 18–18 करोड़ रुपये पड़े हैं सबके पास। 24 करोड़ हो गये इस साल। तो पैसे उनके पास हैं खूब सारे। तो सीधा जाता है वो एमपी के पास कि सर जी, ये क्योंकि उनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि वो प्रपोजल ले आएं। प्रपोजल भी हमारे एमएलए देते हैं सारे के सारे। कहते हैं, ये तो यहाँ पे झूला लग सकता है, यहाँ पे जिम लग सकता है, यहाँ पे बेंच लग सकती है, यहाँ पे ये काम हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है। तो वो सीधा एमपी साहब के पास जाता है, ''सर जी, थोड़ा पैसा दे दो।'' तो वो उसके काम से कराना चाहता है पहले। अगर नहीं होता तब वो कहता है, ''चलो, एमएलए फण्ड से करा दीजिएगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।'' तो मेरा एक तो सुझाव ये है कि पहले तो जो भी सिस्टम है, इस सिस्टम को थोड़ा सा सुधारने की आवश्यकता है। हम 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' की बात करते हैं। हम कहते हैं, ''नक्शा?'' ''जी, एक महीने में पास कर देंगे।'' ऑनलाइन नक्शा पास होगा। ऑनलाइन एमएलए फण्ड का भी काम कर दो भई। अगर कोई पार्क के अंदर... पार्क की बात करता हूँ मैं, एमएलए ने कहा कि भाई, मैं इस पार्क में 10 बेंच लगवाना चाहता हूँ तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर दे। अगर उससे पहले एमपी साहब ने अप्लाई कर रखा है तो ठीक है। अगर उस से पहले काउंसलर ने अप्लाई कर रखा है तो भी ठीक है। परन्तु अगर एमएलए ने अप्लाई कर दिया, उसके बाद कुम्भकरण की

नींद खुल जाए कि भाई, साहब, आप? मेरी तो नींद खुल गयी, मैं बनाऊँगा, ये तो मैं करूँगा। ये नहीं चलेगा। एमएलए फण्ड है इमरजेंट फंड, इमरजेंट फण्ड का मतलब है कि इमरजेंसी में फटाफट काम कराना है। जनता आती है घर पे कि जी, मेरे यहाँ पे दो बेंच डलवा दो। कोई कहता है कि दो लाइट लगवा दो जी। कोई कहता है, ये झूला लगवा दो। अगर उसको लगने में तीन साल लगेंगे तो एमएलए फण्ड की जरूरत क्या है? वो तो गवर्नमेंट के फण्ड से बन जाएगा। गवर्नमेंट किस लिए है? गवर्नमेंट का काम ही है ये सारे काम कराने। एमएलए फण्ड में ऐसी एक भी आइटम नहीं है जो सरकारी फण्ड से न हो सके। एमएलए फण्ड इमरजेंसी फण्ड है, उसको इमीडिएटली होना चाहिए, पहला तो मेरा सुझाव ये है।

दूसरा, सौरभ जी ने अभी एक टाइमलाइन दी है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। बिल्कुल सही है। विद इन दैट टाइमलाइन काम को अप्रूव करना जरूरी है। दूसरा, मैं इसमें ये जरूर कहूँगा कि जो इन्होंने फर्स्ट टाइमलाइन दी है, या तो वो उतने दिन में एस्टीमेट बना के दे दें या विद इन सेवन डेज़ वो कह दें कि जी, आप से पहले ये रिक्वेस्ट इनकी आई हुई है, उसका प्रूफ दे दें साथ में। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वो फिर ये कहेंगे, ''नहीं जी, हर चीज तो हमारे एमपी साहब बना रहे हैं, हम अपने डिपार्टमेंट के फण्ड से बना रहे हैं।'' इनके पास एक नया ड्रामा आ गया कि जी, हमारी दूसरी स्कीम से बन रहा है, हम दूसरी स्कीम से करेंगे। और जनता कहती है जी, भाई साहब, हुआ क्यों नहीं? भई आप स्कीम से कर लो तो हमें क्या आपत्ति है। एक पार्कों के बारे में ये कहना चाहूँगा... जितने भी हमारे विधायकों के एरिया में पार्क हैं, उसमें से ज्यादातर पार्क को अगर आप चाहें तो आरडब्ल्यूएस़ को ट्रांसफर करा दीजिएगा। एमसीडी के पास उनको मेंटेन करने के लिए न तो मैनपावर है, न ही इंक्लिएनेशन है, न ही उनके पास पैसा है। दिल्ली सरकार ने पार्कस् एण्ड गार्डन सोसाइटी

बनाई हुई है, इमरान हुसैन जी मंत्री हैं उसके। वो उसको संभालते हैं, उसके अंदर पैसा देते हैं। वो पार्क आरडब्ल्यूए को ट्रांसफर करा दीजिएगा, आरडब्ल्यूए उसको मेंटेन करेगी और वहाँ पे इमरान जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बोर्ड लगवा दो। एक लाख रुपये एकड़ मिलता है एक साल का, जिसको बढ़ा रहे हैं। मेरे को अभी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, कितना है। अमाउंट बढ़ा रहे हैं अभी उसका।

... (व्यवधान)

माननीय शहरी विकास मंत्रीः है, ऑलरेड्डी है।

श्री नरेश बाल्यानः पार्क्स एण्ड गार्डन सोसायटी का?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः जी।

श्री नरेश बाल्यानः सर, सारे लोग परेशान हैं। वो दिल्ली पार्कस् एण्ड गार्डन सोसाइटी वाले जो वहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं और सारी...

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी, एक मिनट। नरेश जी, बताओ।

श्री नरेश बाल्यानः वहां पे एक ही... रोजाना फोन आ रहे हैं।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अभी करवा देता हूँ।

श्री नरेश बाल्यानः डीडीए पार्क है, उसका भी फण्ड नहीं रिलीज कर रहे।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अभी मैं नरेश जी, एक मिनट। अगर आदरणीय मंत्री जी ने मुझे अभी बताया है कि इस साल का फण्ड सबका

रिलीज हो चुका है। अगर किसी सदस्य के एरिया में नहीं हुआ है तो उसको इमीडिएटली करा दिया जायेगा और दूसरा भई, वो तो हमारे अंडर आता है, उसको तो कर ही देंगे। ठीक? पैसा भी बढ़वा देंगे, नंबर भी बढ़वा देंगे, जो भी करना है, करवा देंगे।

दूसरी बात, कल जगदीश प्रधान जी ने ये बताई थी बात या किसने. मेरे को याद नहीं आ रहा कि पार्कों के मालिक तो एमसीडी है ही नहीं। जो कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज़ की मालिक तो वो खुद हैं मालिक। तो एमसीडी तो वहाँ पे केयरटेकर है बस। तो एनओसी... तो इसका मतलब वो खुद दे सकते हैं। भई, जो सोसाइटी को आप ट्रांसफर करेंगे, वो सोसाइटी डायरेक्ट एनओसी दे दे। हाँ, ओम प्रकाश जी ने बताया था। दिल्ली में 50 परसेंट तो काम खत्म हुआ। उसके बाद मैं आपको ये जो ऑर्डर है पार्कों के अंदर जो हम काम कर सकते हैं; जिम लगाने का। ये ऑर्डर हुआ था 11 सितम्बर, 2015 में। ढ़ाई साल हो गया है तब सरकार ने इसका ऑर्डर किया था और उसमें क्लियर लिखा था कि एमएलए फण्ड से आप पार्कों के अंदर जिम, प्ले स्टेशन प्ले इक्विपमेंट लगा सकते हैं ***The ownership of the open Air gym, machine will be with the agency of the Central Govt.èStateèUT Govt.èAdmn. Or Local Body.*** मतलब तीनों के पास होगा जिस भी एजेंसी से आप काम करायेंगे। मान लो सीपीडब्ल्यूडी से कराया, तो वो एजेंसी ओनरशिप रखेगी। अगर पीडब्ल्यूडी से कराया है तो वो रखेगी, अगर एमसीडी से कराया है तो वो ओनरशिप रखेगी इन्क्लूडिंग मेन्टेनेंस। वो 5 साल का कांट्रैक्ट करा दो, सीधा ही कि भई मेंटेनेंस सहित उसका कांट्रैक्ट करा दीजिएगा तो लोग भी खुश रहेंगे। तो मुझे लगता है इस ऑर्डर...

... (व्यवधान)

माननीय शहरी विकास मंत्रीः लोकल बॉडी में आता है डीडीए। डीडीए अगर करना चाहेगा तो लोकल बॉडी में आएगा। तो...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई, आ गया न, दिल्ली गवर्नमेंट आ तो गया, दिल्ली गवर्नमेंट बोला है।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः एक इश्यू ये भी उठ रहा था कि भई पार्कों के अंदर घास लगाने का पॉवर नहीं है, मिट्टी डालने की पॉवर नहीं है। तो मुझे ये कहना है कि देखिएगा, एमएलए फण्ड स्पेसिफिकली कैपिटल असैट्स के लिए है, मेन्टेनेंस के लिए नहीं है। और अगर मेन्टेनेंस की बात पे आयेंगे तो कल को बिजली का बिल जमा कराने का चक्कर पड़ जायेगा। एमएलए के पास इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो चार लाइटों का बिल भी जमा करा पाए। उसका सॉल्यूशन यही है कि आप सोसायटी को ट्रांसफर करा दीजिएगा, आरडब्ल्यूए को ट्रांसफर करा दीजिएगा। उसको अलाऊड है, वो घास भी लगवा सकते हैं, वो मिट्टी भी डलवा सकते हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं वहाँ पे। तो उसकी दिक्कत वहाँ पे साल्व हो जायेगी, अपने ऊपर डायरेक्टली लेने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। एमएलए फण्ड की जरूरत नहीं है, सरकार दे रही है ना। सरकार दे रही है और अगर आपको लगता है तो इसको मैं सोचता हूँ देख लेते हैं, इसपे विचार कर लेते हैं कि एमएलए फण्ड भी अगर जो सोसाइटियाँ, जो आरडब्ल्यूएज़ पार्कों को मेन्टेन कर रही हैं, तो एक फिक्स्ड अमाउंट अगर उसको एमएलए देना चाहे तो हम उसमें प्रोविजन कर देते हैं कि एमएलए भी दे दे इसको। भई मान लो एक लाख रुपये साल के लिए देते हैं, आपको लगता है 50 हजार लंपसम देने हैं, आप उसको दे दीजिएगा। उनका ऑडिट होता है,

सब कुछ होता है। उसको चैक कर लेते हैं, एग्जामिन करा लेते हैं। अगर हो सकता है तो इसको भी डाल दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्षः चलिए।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः दूसरी बात ये है अध्यक्ष महोदय, कुछ सड़कों के बारे में बात आई थी। सड़कों के बारे में मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। देखो, एमसीडी की जितनी सड़कें हम ले चुके हैं, वो तो ठीक है, दिल्ली के अंदर सिर्फ पीडब्ल्यूडी के पास 60 फुटी रोड नहीं है। डीडीए के पास भी नहीं है, एमसीडी के पास भी नहीं है, एनडीएमसी के पास भी नहीं हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के पास है। सड़क तो हम ले लेंगे। सड़क लेने के बाद उसकी सारी शिकायतें हमारे ऊपर आ जाती हैं और ओनरशिप वो अपने पास रखते हैं। कहते हैं, ''जी यहाँ पे कब्जा भी करवाएंगे।'' इसके अंदर कहते हैं, ''हम कहीं पर भी उठा के ना सड़क के बीचो–बीच कूड़ेदान बना देते हैं।'' अरे! वहाँ पे गाड़ी निकलेगी, रिक्शा निकलेगी या कूड़ेदान रहेगा बीच में! राजेश जी के यहाँ तो फुटपाथ के ऊपर टॉयलेट बना दिए। तो मुझे लगता है कि जब तक ये ओनरशिप वाला मामला सॉल्व नहीं होगा। देखो, एक आप किसी को लीज़ के ऊपर घर देते हैं, डीडीए लीज़ पे देती है ना, तो लीज़ पे देती है। तो वो मकान अपने पैसे से बनाता है, उसको किराये पे भी तो चढ़ा सकता है। सब कुछ वो करता है, लीज़ पे है, ओनरशिप डीडीए की है। मान लेते हैं डीडीए की ओनरशिप है परन्तु उसने 99 साल के पट्टे पे दे दिया तो अब ये सब कुछ हमारे पास है ना। अब दिल्ली सरकार को तो ये समझते हैं कुछ नहीं है कि आप को लीज़ पे तो दे दिया, सारा पैसा आप खर्च करो। साल के पॉच सौ, डेढ़ हजार करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। मालिक वो बने हुए बैठे हैं। फिर वही चिड़िया कौवे वाली कहानी आ गई। वो नहीं चलेगा

कि हम नई सड़कें तभी लेंगे उसी कंडीशन में लेंगे कि दिल्ली सरकार को सारी पॉवर्स होनी चाहिए, सारा कुछ उसके ऊपर करेंगे तब। और मैं अपने साथियों से एमएलएज से रिक्वेस्ट करूँगा, जो कमेटी है, कानून को अच्छी तरह पढ़ कर बनायें और ये बिल्कुल आसान है और होना चाहिए; सड़कों के ऊपर एन्क्रोचमेंट बढ़ रही है। कई सदस्यों की ये शिकायत है कि मेन रोड के ऊपर जो चौड़ी चौड़ी सड़कें है, उनके ऊपर ज्यादा कब्जे हो रहे हैं। तो उस एनक्रोचमेंट को हटाने की पॉवर जैसे ही दिल्ली सरकार को मिलेगी, मैं गांरटी से कहता हूँ, दिल्ली की सड़कों को हम साफ करा कर दिखायेगें आपको, बिल्कुल क्लीयर कर देंगे। आज ये लोग एनक्रोचमेंट हटाने के नाम पर सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों को हटाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं दिल्ली के अंदर जिसने एक आदमी ने कई कई सौ कारें सड़क पर खड़ी कर रखी हैं। आपके लिए नहीं है... जनरैल जी, जगदीप जी, इनके एरिये मैं हैं। एक सड़क के ऊपर एक आदमी ने तीन सौ कारें खड़ी कर रखी हैं। जितनी जगह पर वो कब्जा करके बैठा है। तीन सौ करोड़ की जमीन है। एक बेचारा रेहड़ी पटरी वाला सुबह आता है, अपना रोजगार करके चला जाता है, उससे सबको तकलीफ है... उससे तकलीफ नहीं है बिल्कुल भी। असली कारण ये है... मैं इस बात को अक्सर कह चुका हूँ, असली बात से सबको डर लगता है क्योंकि उन लोगों से मंथली आती है सबकी। शिवचरण जी के यहाँ पर शो रूम हैं; कारों के शोरूम के अंदर होगी बीस कारें और शो रूम के बाहर कारें होंगी दो सौ! अरे भई! कमाल है! दो सौ कारें सड़क पर क्यों खड़ी कर रखी हैं तुमने? परमानेंट धंधा कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये जो सिस्टम... इसीलिये तो कह रहा हूँ कि पॉवर तो हमारे पास आनी चाहिए। कहते हैं, ''नहीं जी, चालान कटने की पॉवर भी एमसीडी के पास है या दिल्ली पुलिस के पास है। तो ये पॉवर हमें मिल जायेगी तो हम बिल्कुल इसको कर देंगे, धन्यवाद, जयहिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्षः अभी आने दीजिए, थोड़े दिन रुकिए। अब श्री सौरभ भारद्वाज जी, माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति लेंगे।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, जैसा कि हमारे बहुत सारे साथियों ने विधायक निधि से जो भी काम होते हैं, उनके अंदर किस तरीके से इंटेंशनल डिले की जाती है, उसका उदाहरण दिया, सदन के आगे कागज रखे और मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस विधान सभा की रिर्पोटिंग भी करते हैं; पत्रकार के तौर पर, टीवी के पत्रकार हों या न्यूज के पत्रकार हों, सब लोग इस दिल्ली में ही रहते हैं और उनको खुद... मुझे लगता है फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि नगर निगम कितना भ्रष्ट है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने मकान खरीदा न हो या मकान बनवाया न हो या अड़ोस पड़ोस के अंदर मकान बने न हों। तो उनको मालूम न हो। तो ये सब मालूम है तो हम लोगों ने जो डिस्कशन की, उसके हिसाब से हमने दो तीन चीजों के ऊपर एक रेजॅलूशन तैयार किया है।

माननीय अध्यक्षः नहीं, अभी तो आप रेजॅल्यूशन के लिए अनुमति माँगेंगे।

श्री सौरभ भारद्वाजः जी, तो अध्यक्ष जी, मैं इस हाऊस से आपके माध्यम से एक संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति चाहूँगा।

माननीय अध्यक्षः अब ये प्रस्ताव सदन के सामने हैं:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

सदन द्वारा माननीय सदस्य को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, ये संकल्प अंग्रेजी के अंदर है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ।

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः वो हैं ही नहीं, आज बाहर हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए।

श्री सौरभ भारद्वाजः बाहर सुन रहे होंगे तो मैं हिंदी में बता देता हूँ।

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः ***"The Legislative Assembly in its sitting on 10th April 2018 resolves that :***

Whereas there have been numerous complaints of MLA(s) that Municipal Corporations of Delhi intentionally delay the work under MLALAD funds,

This House directs the GNCTD to formulate strict guidelines for the execution of works under MLALAD funds.

The request for estimate of any work should not take more than 21 working days for any executing agency to provide estimate of work to the respective MLA and if there is any other proposal for the same work by other entities, the MLA must be informed in 7 days.

The request and process of allocation of funds to an executing agency should not take more than 14 working days.

The requestèprocess of preparing NH and inviting Tender should not take more than 30 days of receipt of funds.

The award of work after opening of bids should not take more than 14 days after finalization of bids.

The execution of work after the award of work should not take more than 90 days.

The savings in the MLALAD work should be returned to the Urban Development Departmentwithin 90 days of completion of work.

If any agency applies for NOC regarding any work to MCD under 'MLALAD' work, the NOC would be deemed to have been provided, if 'NOC' is not provided in 15 days or reason is communicated to the agency for not granting 'NOC' for MLALAD work.

In case there is delay in any of the stages as provided above, the concerned Executive Engineer of the executing agency should write a letter to the concerned MLA explaining the reasons for such delay and expected timeline for the said work under MLALAD funds. The concerned Executive Engineer should mark copy of such letter to Secretary, Urban Development Department and Commissioner of its Municipal Corporation.

Any violation of the guidelines in this resolution shall be treated as Contempt and breach of

Privileges of Legislative Assembly of Delhi and its Members.'

मोटे तौर पर हमने इसमें सब जगह पर टाइम लाइन लगा दिए हैं। आपने एस्टीमेट के लिये दर्ख्वास्त दी, 14 दिन में आपको एस्टीमेट मिलना चाहिए। अगर उस सेम एस्टीमेट को किसी और ने लगाया है तो सात दिन के अंदर आपको रिटर्न कम्युनिकेशन आना चाहिए कि फलाँ एमपी ने या फलाँ काउंसलर ने इस चीज के लिए ओलरेडी फण्ड दिया हुआ है या एस्टीमेट माँगा हुआ है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन्स में सब आ गये। सब आ गये, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे लगता है कि सब लोग समझ ही रहे हैं इसको हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है।

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः टेन्डर वाला टेन्डर एनआईटी बनाने के लिए एक संशोधन आया है कि ये जो एक बार फण्ड मिल जाये तो एनआईटी प्रेपेयर करने के लिए 21 दिन को हटाकर तीस दिन कर लिया जाये तो मैं इसको तीस दिन कर देता हूँ। तो अध्यक्ष जी, ये जो संकल्प है, ये सदन के सामने है मैं पेश कर रहा हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो इसमें नहीं हो पायेगा सुरेन्द्र जी, प्लीज। अब सौरभ भार्द्वाज जी को प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मैं एक छोटी सी अनुमति और चाहता था आपसे कि एक अखबार है हिंदी का दैनिक अखबार 'दैनिक जागरण।' ये मैं इसको... जब से हमारा सदन चल रहा है, मैं इसको खासतौर पर देख रहा हूँ कि ये अखबार लगातार सदन की कार्यवाही जो है...

श्री कपिल मिश्राः अखबारों के खिलाफ सुझाव नहीं आने चाहिए, ये विनती है।

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए, कपिल जी। नहीं, बैठिए। कोई अखबार सदन को अपमानित करे, कोई अखबार विधायिका को अपमानित करे, बैठिए प्लीज। आप बैठिए, प्लीज। बैठिए, कोई बात नहीं। चलिए।

... (व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, प्रस्ताव लेकर आये हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः रखिये, सौरभ जी।

सुश्री अलका लाम्बाः जेल भी हुई है। ये गलत बात है आप जनता को गुमराह कर रहे हैं इस तरह के रिपोर्टिंग करके...

माननीय अध्यक्षः वो देखेंगे, कानून के तहत देखेंगे। हम कानून के तहत देंगे, जो भी देंगे।

श्री सोमनाथ भारतीः पत्रकार अगर गलत बोलेगा, जेल भी जायेगा वो।

सुश्री अलका लाम्बाः हम लोग हवाला देंगे।

श्री सोमनाथ भारतीः गलत रिर्पोटिंग करेगा, जेल जायेगा।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए।

श्री सोमनाथ भारतीः पत्रकारों को...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, बैठिए। आप पूरा पढ़ कर सुनाइए। सोमनाथ जी, बैठिए। आप पूरा पढ़ कर सुनाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कपिल जी, मैं आग्रह कर रहा हूँ, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री कपिल मिश्राः मैं बैठ रहा हूँ, पर ठीक नहीं है ये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। अब ठीक है, गलत है, ये सदन का काम है देखना।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, कोई बात नहीं। वो देखेंगे हम।

श्री सोमनाथ भारतीः वो पत्रकार, वो चैनल जो दलाल की तरह काम करता है, वो जेल भी जायेगा और जो...

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः वो भी जेल जायेगा जो दलालों की दलाली करे, वो भी जेल जायेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, कोई बात नहीं। बैठिए, आप बैठिए। इस सदन.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, बैठिए प्लीज। सोमनाथ जी। बैठिए, बैठिए। सदन के अधिकारों की रक्षा करना... सोमनाथ जी, दो मिनट बैठिए प्लीज। मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ। इस सदन के विधायिका के अधिकारों की रक्षा करना इस सदन के सदस्यों का दायित्व है। अखबार है या कोर्ट है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप दो मिनट रुक जाइए। मैं बोल रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, कोई बात नहीं। एलजी क्या खुदा हो गया? नहीं एल जी क्या खुदा हो गया? एलजी को कम्पलेंट करेंगे!

ये सदन की कम्पलेंट एलजी को करेंगे! एल जी आपके लिए खुदा होगा, हमारे लिए खुदा नहीं है। बैठ जाइए आप।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप चुप हो जाइए अब।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी, आप पढ़िए इसको, पूरा पढ़िए।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मैं ये बताना चाहता था कि ये अखबार जो है, लगातार पूरे सदन की जो कार्रवाई है, इसको गलत तरीके से मिस्लीड करते हुए, कार्रवाई को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम सब लोगों को मालूम है कि ये विधान सभा मुझे लग रहा है, 1993 से चल रही है। 1993 से लेकर अब तक हर बार पुलिस से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। मेरी विधान सभा में तो लोग पूछते हैं, मुझे लगता है सबकी विधान सभा में, अगर कोई विधायक उस एरिया में दिखता होगा तो उससे जरूर पूछते होंगे कि भाई, ये पुलिस का क्या हाल है और अगर विधायक से पुलिस के बारे में पूछा जा रहा है तो विधायक कहाँ पूछेगा? विधायक इस विधान सभा में पूछेगा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस के बारे में जो सवाल पूछे गए, उसके जवाब नहीं आए। भ्रष्टाचार के बारे में लोग बाहर विधान सभा से जैसे ही निकलते हैं, माइक के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भ्रष्टाचार के बारे में सवाल पूछा गया कि अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, उसके बारे में कोई जवाब नहीं आया। जब सदन में इस बारे में माँग हुई तो इस अखबार ने लिखा 'नहीं मिले जवाब, अधिकारियों पर निकाली खुन्नस' और ये आपके लिए लिखा है, नेता इस सदन के नेता आप, आपके लिए लिखा है कि 'अध्यक्ष ने निकाली खुन्नस।' ठीक है ये खुन्नस शब्द जो है, ये निहायती घटिया है और मुझे नहीं लगता कि इस कागज को ये अखबार कहने का हक रखते है।

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारतीः अनपार्लियमेंटरी भी है।

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः उसके बाद इन्होंने मंडल आयुक्त, मनीषा सक्सेना का वो विवादास्पद बयान जिसके लिए इनको बुलाया गया था, उसको दुबारा छापा। ये मालूम होने के बावजूद कि वो जो बयान है, वो गलत था, डिपार्टमेंट मना कर चुका है कि ऐसा नहीं हुआ, उस चीज को दुबारा छापा। तो अगर आज मैं कुछ भी कह दूँ तो क्या छाप देंगे अखबार वाले? मेरे कहने से तो नहीं छापते। इसका मतलब इनकी इंटेंशन है इसके अंदर कि ये कुछ न्यूसेंस क्रिएट की जाए।

इसी तरीके से एक और हेडलाइन छापी इन्होंने 28/3/2018 को, 'बढेगी तल्खी, कार्यवाही पर राज्य निवास की पैनी नजर' और एलजी साहब की फोटो छाप दी। उसके अंदर लिखा है, 'जहाँ एक ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री, अधिकारियों को विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति तथा विशेषाधिकार समिति के दायरे में लाकर परेशान करने की रणनीति पर चल रहे है।' मतलब मंत्री और सरकार कमिटियों के अंदर अधिकारियों को लाने की एक रणनीति, एक साजिश चल रहे है मतलब इस साजिश के अंदर जहाँ पर सवालों के जवाब नहीं आए, इस अखबार ने उस साजिश के अंदर एक–एक आदमी जो यहाँ पर चुनकर आया है, लाखों वोटों से जीतकर आया है, उसको उस षड़यंत्र का हिस्सा बना दिया। इन समितियों को इस षड़यंत्र का हिस्सा बना दिया। ये मुझे लगता है कि ये इसको आप कुछ भी कहेंगे, मैं इसको पत्रकारिता तो नहीं मानूँगा, ठीक है और पत्रकार अध्यक्ष जी, मैंने वो भी देखें हैं, महान राष्ट्रीय पत्रकार जो करोड़ों रूपए की दलाली फाइव स्टार होटल में माँग रहे थे कांग्रेस वालों से कि नहीं तो आपकी खबर चलेगी। नवीन जिंदल से पैसे माँग रहे थे। वो भी देखें हैं जो बंद रहे तिहाड़ में पैसे लेने के इल्जाम में। वो भी पत्रकार ही हैं और वो भी रोज शाम को 7.00 बजे आ जाते हैं टीवी पर। सेम कैटेगिरी है।

अध्यक्ष जी, इसके बाद एक और खबर है जिसके अंदर इन्होंने लिखा है 'सीलिंग से राहत का विधेयक केंद्र को भेजें केजरीवाल' और इसमें हाउस के ऊपर इन्होंने ये कहा कि भई, हाउस जो है, वो विधेयक बनाकर मतलब बिल बनाकर, कानून बनाकर केंद्र सरकार को भेजे, अब ये अखबार मुझे लगता है कि काफी साल पुराना अखबार है, सो कॉल्ड... ये, ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये हाउस न तो कोई बिल बना सकता है, न ही सीलिंग के विषय में कोई एक्ट बना सकता है तो ये लिखकर गुमराह करना कि हाउस अब जो है, वो बिल बनाकर, विधेयक बनाकर केंद्र सरकार को भेजे। ये भी मुझे लगता है पूरा मिस्लीड करने वाला, गुमराह करने वाला है। और मैं ये मानता हूँ अध्यक्ष जी, कि पिछली बार संजीव झा ने भी एक अखबार के विषय में आपको कम्पलेंट की थी और ये मेरी एक दूसरी कम्पलेंट है। आप कृपया करके जो बेहतर समझें, मेरा तो मानना है कि इसको विशेषाधिकार समिति के पास भेजना चाहिए, बाकी आपको जैसा सही लगे, आप वैसा करें, धन्यवाद।

... (व्यवधान)

श्री राजेश ऋषिः इस अखबार ने छापा है कि हर विधायक को सवा लाख रुपये तनख्वाह मिल रही है और ... (व्यवधान) ... तनख्वाह होने वाली है जबकि जनता के बीच में भ्रम पैदा कर रहे है कि यह विधायक इतना–इतना पैसा ले रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए अब।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे है? बस

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दो मिनट तो रूकिए, सोमनाथ जी।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही चीज के बारे में थोड़ा कमेंट देना चाहूंगा, जब भी सदन में आते हैं, जितने भी मंत्री हैं यहाँ, मतलब पूरी तैयारी करके आना पड़ता है। अभी जितने प्रश्न लगाए गए थे, मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ रात–रात बैठकर, रात को 12–12 बजे, 1–1 बजे तक तो मैंने प्रश्न देखे हैं। उनको वापस भेजते हैं, इनको ठीक कराते हैं, जो भी रेजॅल्यूशन लगते हैं, उसकी तैयारी करते है और इस तरह से कहना कि कमिटियाँ... कमिटियाँ सरकार के अंडर बिल्कुल नहीं आती हैं। ये सदन सरकार के अंडर काम नहीं करता है, सरकार सदन के अंडर काम करती है, मैं ये बताना चाहता हूँ धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः सौरभ भारद्वाज जी ने जो विषय रखा है, मैं भी इसको पिछले चार महीने से बराबर अध्ययन कर रहा हूँ देख रहा हूँ और मैंने टोका भी है लेकिन उसके बावजूद भी अखबार गलत भाषा का प्रयोग करने से, तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने में अपनी सारी बुद्धि लगा रहा है। ये सौरभ जी ने जो विषय रखा है, मैं इसको सीधा प्रिविलेज कमिटी को सौंपता हूँ और प्रिविलेज कमिटी अपनी इस पर बहुत जल्दी एक महीने में पूरी इस पर अपनी रिपोर्ट, अगले सदन में प्रस्तुत करे, ये मैं आग्रह कर रहा हूँ। सदन इस बार बहुत लम्बा चला, वर्किंग डेजस... ये सतरहवाँ दिन था...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अभी नहीं, अब नहीं, अब नहीं प्लीज, प्लीज प्लीज। मैं मानता हूँ आपकी भावनाएं...

... (व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, एक दिन का और बढ़ा दो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अभी अल्पकालिक चर्चा पर इसमें तीन हमारे विषय रह गए थे, एक अलका जी का, दूसरा पंकज पुष्कर जी–अलका जी का, एक जल पर था जल का समय जो चर्चा होनी थी, वो विपक्षी सदस्यों ने ही उसको समय को खराब कर लिया। मैं... मुझे इसके लिए अफसोस भी है।

अब इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करूं, स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, सभी मंत्रीगण, श्री विजेन्द्र गुप्ता–माननीय नेता, प्रतिपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ–साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सीआरपीएफ बटालियन–55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलैक्ट्रिकल व हॉर्टिकल्चर डिवीजन, अग्निशमन विभाग आदि द्वारा बजट सत्र की लम्बी अवधि के दौरान किए गए सराहनीय कार्य के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ। विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

एक चीज बीच में रह गई जो एमसीडी पर चर्चा हुई है, वो भी सारी मैं पीछे जो चर्चा हुई थी, ये कौन सी कमिटी बोल रहे थे? हां, क्वेश्चन एण्ड रेफरेंस कमिटी को ये सारा मेटर मैं सौंप रहा हूँ।

अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हों।

(राष्ट्रगान)

माननीय अध्यक्षः अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गई।)

... समाप्त ...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्सs, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।